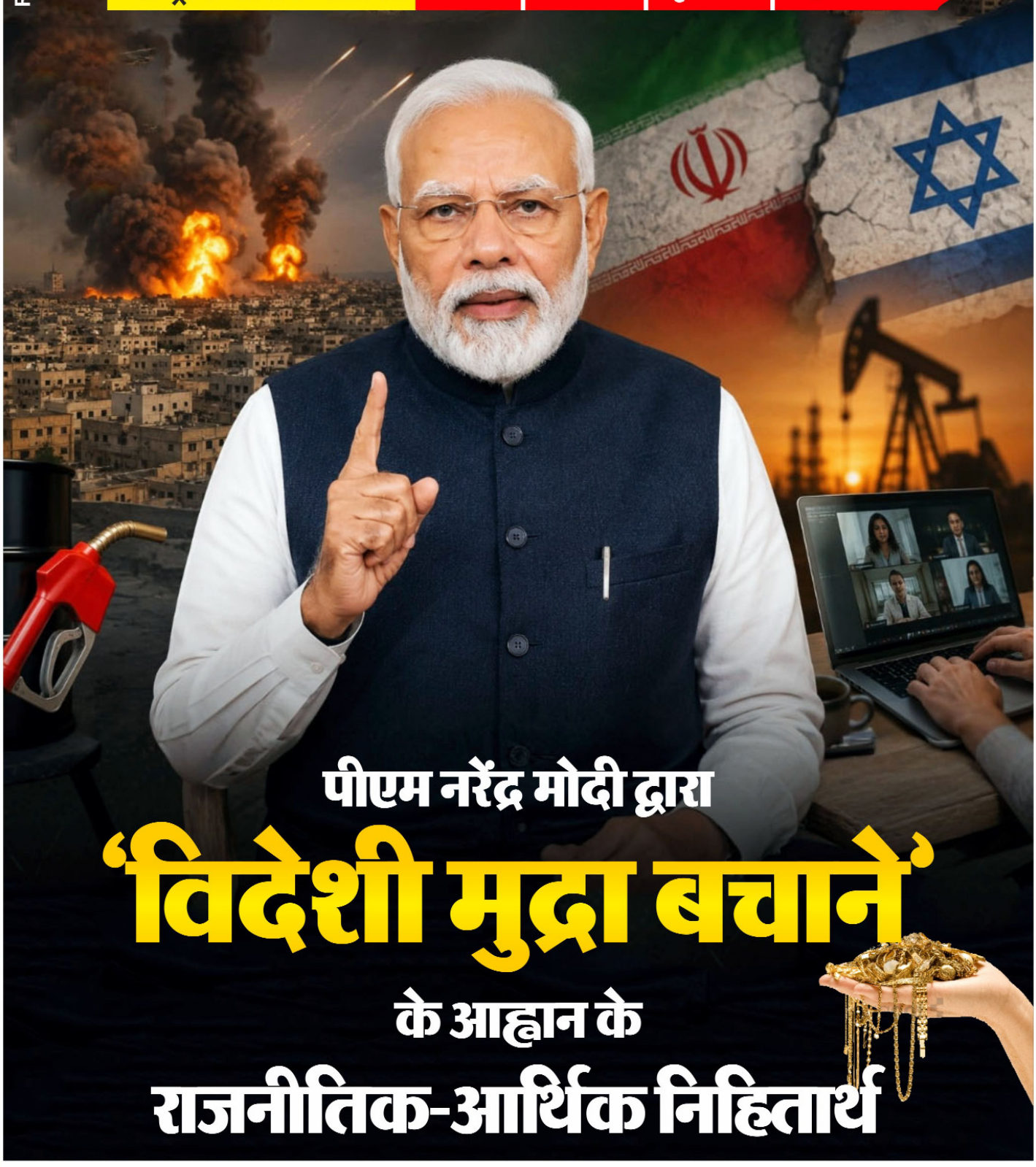
RNI NO. DELHIN/2015/61881

www.srojvarta.in

मूल्य : 10 रूपये

सरोज वार्ता

राष्ट्रीय मासिक पत्रिका | वर्ष-12 | अंक- 05 | पृष्ठ- 44 | मई 2026



पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा

'विदेशी मुद्रा बचाने'

के आह्वान के

राजनीतिक-आर्थिक निहितार्थ

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

शक्ति से समृद्धि



नारी
उत्तर प्रदेश
के विकास
की धुरी

नवनिर्माण के 9 वर्ष

सुरक्षा से समझौता नहीं
सभी थानों में 'मिशन शक्ति' केंद्र

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना
26.81 लाख+
बेटियां सशक्त

निराश्रित महिलाओं को पेंशन

लखपति दीदी योजना
18.55 लाख+
महिलाएं बनीं लखपति

महिला श्रम बल भागीदारी
13% से बढ़कर 36%

1 करोड़+
ग्रामीण महिलाएं बनीं आत्मनिर्भर

मेधावी छात्राओं को स्कूटी का उपहार

कामकाजी महिलाओं के लिए
श्रमजीवी महिला छात्रावास

महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड
ब्याज मुक्त ऋण

10,400+
स्टार्ट-अप का नेतृत्व



विकास की गति अपार-डबल इंजन सरकार

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

UPGovtOfficial | CMOUttarpradesh | CMOfficeUP

BREAKING NEWS

www.srojvarta.in



RNI NO. DELHIN/2015/61881
राष्ट्रीय
सरोज वार्ता
हिन्दी मासिक पत्रिका
मूल्यः 10 रूपये
वर्ष-12 । अंक - 05 । मई 2026
संरक्षक : रामकुमार सिंह
प्रधान संपादक : जगत किशोर सोलंकी
संपादक : अनुराग प्रताप
विधि सलाहकार : ललित पराशर
ग्राफिक डिजाइनर : सहदेव माहौर
मार्किटिंग मेनेजर : कृष्ण कुमार (उत्तर प्रदेश)

ब्यूरो प्रमुख
उत्तर प्रदेश : कृष्ण कुमार
राजस्थान : सौमेंद्र सिंह
दिल्ली : रिचा जोशी
छत्तीसगढ़ : विजय कुमार

संपादकीय, विज्ञापन एवं प्रसार कार्यालय
सरोज वार्ता, आर जेड ए 3/73 गली न. 3ए दुर्गा पार्क नई दिल्ली-110045

फोनं,: 09456004121, 09555253051, 9899864010

www.srojvarta.in
sarojvartanews@gmail.com
srojvartanews@gmail.com

क्षेत्रिय कार्यालय (उत्तर प्रदेश)
नियर हनुमार मंदिर, अमापुर सिद्धपुर रोड़, सिद्धपुर जिला, कासगंज

पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। सभी पद अवैतनिक हैं। विज्ञापन की सत्यता की जांच स्वयं कर लें। इसकी जिम्मेदारी उनकी है, एवं इसके प्रकाशक एवं संपादक की सहमति अनिवार्य नहीं है। पत्रिका से संबंधित सभी विवादों का निपटारा दिल्ली न्यायलय के अधीन होगा।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अनुराग प्रताप द्वारा मैसर्स जवाद लीठोफराफर (M/s Jawaad Lithofrapher) 3622, दीनाबेग, लाल कुंआ, दिल्ली : 6 द्वारा मुद्रित व आर.जेड. ए : 3/73, गली नं. 3ए दुर्गा पार्क नई दिल्ली : 45 से प्रकाशित

संपादक : अनुराग प्रताप

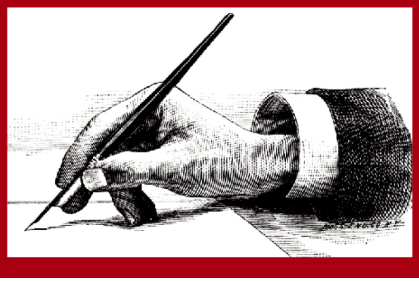
चेतावनी के धमाके

गाहे-बगाहे पंजाब में शांति भंग करने के अनेक कुत्सित प्रयास होते नजर आए हैं। सीमा पार से पंजाब का सुख-चैन छीनने के षड?यंत्र काले दौर से लेकर अब तक रुके नहीं हैं। नशे और बेरोजगारी को हथियार बनाकर भटके युवाओं को इन साजिशों का हथियार बनाने के मामले भी उजागर हुए हैं। पंजाब में हाल ही में दो धमाके हुए, पहला जालंधर में बीएसएफ चौकी के बाहर और दूसरा अमृतसर में सेना की छावनी के पास हुआ। सेना और सुरक्षा बलों को लक्षित इन हमलों के घातक मंसूबों को समझा जा सकता है। वहीं दूसरी ओर समय और लक्ष्य के लिहाज से इतने करीबी हमलों के निहितार्थ समझना कठिन नहीं है कि ये महज सामान्य मामले नहीं थे। अब भले ही इन धमाकों की तीव्रता कम रही हो,लेकिन इनमें गंभीर रणनीतिक चेतावनी छिपी है। वह ये कि भारतीय सुरक्षा व्यवस्था के संवेदनशील क्षेत्रों की हिफाजत को आंका जा रहा है। वहीं दूसरी ओर पंजाब के डीजीपी गौरव यादव द्वारा सैन्य क्षेत्र के पास हुए धमाकों में विस्फोटक उपकरण यानी आईडीपी के इस्तेमाल की पुष्टि करना, खतरे की गंभीरता को रेखांकित करता है। निस्संदेह, ये महज आकस्मिक घटनाएं मात्र नहीं हैं। ये सुनियोजित तरीके व जासूसी के जरिये रक्षा प्रतिष्ठानों के आसपास की कमजोर कड़ियों को तलाशने की कुत्सित कोशिश है। अब चाहे इन आतंकी गतिविधियों के तार स्थानीय साजिश से जुड़े हों या फिर सीमा पार से साजिश को अंजाम दिया गया हो, कह सकते हैं कि मिलाजुला षड?यंत्र हो, मगर तौर-तरीका स्पष्ट है। हालांकि, राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक लाइन के अनुरूप बयान देने से बाज नहीं आ रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसका दोष भाजपा पर मढ़ा है। वहीं भाजपा आप सरकार पर आरोप लगा रही है कि वह राज्य को सुरक्षा देने में विफल रही है। बहरहाल, भले ही आरोप-प्रत्यारोप का यह खेल नेताओं को राजनीतिक लाभ-हानि के गणित के अनुरूप लगता हो, मगर राज्य की सुरक्षा के नजरिये से अदूरदर्शी कदम ही कहा जाएगा। यह विडंबना ही है कि पंजाब के राजनेता अतीत के स्याह दौर की घातकता से कोई सबक नहीं सीखते हैं। राजनेताओं की संकीर्णता और दूरगामी प्रभावों को नजरअंदाज करके की गई बयानबाजी ही चिंगारी को आग बनाने का काम करती है। जिसकी कीमत दशकों तक पंजाब के लोगों व राज्य की अर्थव्यवस्था को चुकानी पड़ती है। यह सामान्य तथ्य है कि कि जब भी इस संवेदनशील व सीमावर्ती राज्य पर कोई सुरक्षा संकट पैदा हो, उसके लिये राजनीतिक भेदभाव भुलाकर समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता है। टकराव की राजनीति से राज्य का अहित ही होगा। निस्संदेह, पंजाब का अतीत इस मामूली अशांति के प्रति भी विशेष रूप से संवेदनशील होने की जरूरत बताता है। दशकों तक पंजाब ने सुदृढ़ पुलिस व्यवस्था और खुफिया जानकारी पर आधारित अभियानों हेतु देशव्यापी ख्याति अर्जित की है। लेकिन हाल की घटनाओं ने हमारी सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाया ही है। यह गंभीर मसला है कि इस सीमावर्ती संवेदनशील राज्य में दस दिनों के भीतर तीन सुनियोजित व उच्च तकनीक से लैस विस्फोट हुए हैं। ये धमाके सभी पक्षों की मेहनत से अर्जित साख को धूमिल करने के जोखिम को बढ़ाते हैं। सवाल मात्र यही नहीं है कि इन धमाकों के लिये कौन जिम्मेदार है। प्रश्न यह भी है कि क्या इन धमाकों के बाबत खुफिया सूचनाओं को नजरअंदाज किया गया है? या फिर मिली हुई खुफिया सूचनाओं के आधार पर समन्वित प्रतिक्रिया देने में कहीं चूक हुई है? वास्तव में वक्त की सबसे बड़ी जरूरत इस बात को लेकर है कि हम ऐसी किसी भी चुनौती को लेकर एक समन्वित प्रतिक्रिया दें। केंद्र व राज्य सरकार की एजेंसियों के बीच खुफिया जानकारी का बेहतर ढंग से आदान-प्रदान किया जाए। वहीं दूसरी ओर सुरक्षा घेरे के दायरे का तत्काल प्रभाव से सुरक्षा ऑडिट किया जाए। इन साजिशों पर कड़ी निगरानी रखने की जरूरत है। खासकर लगातार गहरी होती ड्रोन आधारित घुसपैठ के खतरों को रोकने के लिये युद्धस्तर पर कार्रवाई की आवश्यकता है। ड्रोन आज अवैध हथियारों व नशीले पदार्थों की तस्करी का साधन बन रहे हैं। जनता का मनोबल बढ़ाना जरूरी है, लेकिन सुरक्षा जोखिमों को कम न आंका जाए।

● अनुराग प्रताप



जगत किशोर सोलंकी



हाशिये पर आधी दुनिया

एक बार फिर साबित हुआ कि महिला आरक्षण की जोरदार वकालत करने वाले राजनीतिक दल हकीकत में महिलाओं को उनका हक देने में ईमानदार नहीं हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल, केरल, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों में महिलाओं को दिये गए टिकटों ने हकीकत बयां कर दी। महिला आरक्षण के नाम पर पिछले दिनों जमकर राजनीति करने वाले दलों ने तैंतीस प्रतिशत तो दूर, इसकी आधी संख्या के बराबर भी महिलाओं को टिकट नहीं दिए। यह विडंबना ही है कि हालिया विधानसभा चुनावों में एक तो बेहद कम महिलाओं को टिकट दिए गए, दूसरे उनमें भी बहुत कम महिला प्रत्याशी जीतकर विधानसभाओं में पहुंच सकी हैं। उल्लेखनीय है कि हाल में चार राज्यों व एक केंद्रशासित प्रदेश के लिए कुल आठ सौ चौबीस सीटों पर चुनाव संपन्न हुए थे, जिनमें सिर्फ पांच फीसदी सीटों पर ही महिलाएं चुनाव जीतने में सफल हो पायी हैं। दरअसल, जिस प्रतिशत में महिलाओं को आरक्षण देने की पुरजोर वकालत करते राजनीतिक दल नजर आते हैं, उस अनुपात में किसी भी राजनीतिक दल ने उन्हें टिकट नहीं दिए। यहां उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल, जिस राज्य को लेकर देश में सबसे ज्यादा गहमागहमी रही, वहां सत्तारूढ़ भाजपा ने कुल 294 सीटों में से तैंतीस पर ही महिलाओं को टिकट दिए। वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस ने 291 सीटों में बावन महिलाओं को टिकट दिए। कुल मिलाकर राज्य में सिर्फ दस फीसदी महिलाएं ही विधानसभा पहुंच पायीं। निश्चय यह आंकड़ा 33 फीसदी का एक-तिहाई भी नहीं है। कमोबेश तमिलनाडु में सत्ता की दहलीज पर खड़ी टीवीके ने जिन 234 सीटों पर चुनाव लड़ा, उसमें सिर्फ 24 महिलाओं को ही टिकट दिए गए। इसी तरह असम में सत्ता में आए राजग ने सिर्फ छह महिलाओं को ही उम्मीदार बनाया था। वहीं प्रगतिशील होने का दावा करने वाले कांग्रेस नीत यूडीएफ ने सिर्फ दस महिलाओं को ही टिकट दिए। जाहिर है सभी दलों में महिलाओं को उनका हक देने के प्रति उदासीनता देखी गई। हालिया विधानसभा चुनावों में महिलाओं को दिए गए टिकट और उनकी जीत के आंकड़े ने एक बार फिर साबित किया कि जनप्रतिनिधि संस्थाओं में महिलाओं को न्यायसंगत प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण देना अपरिहार्य ही है। किसी भी राजनीतिक दल में स्वतः ही महिलाओं को ईमानदारी से तैंतीस फीसदी आरक्षण देने की इच्छाशक्ति नजर नहीं आती है। कहा जा सकता है कि सभी दल महिला प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर सिर्फ औपचारिकता पूरी करते ही नजर आते हैं। इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने का अंतिम विकल्प यथाशीघ्र महिला आरक्षण व्यवस्था ही बचती है। विश्वास करें कि सभी राजनीतिक दल महिलाओं को उनका वाजिब हक देने के लिए ईमानदार पहल करेंगे। सवाल है कि जो राजनीतिक दल हाल में महिलाओं को आरक्षण देने और परिसीमन के मुद्दे पर संसद में जमकर राजनीति कर रहे थे, वे टिकट वितरण के समय महिलाओं के हक को लेकर गंभीर क्यों नजर नहीं आए? उन्होंने महिलाओं को पर्याप्त संख्या में टिकट देने के प्रति उत्साह क्यों नहीं दिखाया? सही मायने में जब तक विधायिका में महिला आरक्षण व्यवस्था हकीकत में लागू नहीं होती, तस्वीर नहीं बदलने वाली है। सवाल यही है कि जब संसद में महिला आरक्षण विधेयक लागू करने में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी प्रतिबद्धता जतायी है तो टिकट बांटते समय उनकी सोच क्यों नहीं बदलती? उनकी कथनी-करनी का यह अंतर कब तक जारी रहने वाला है? इस मुद्दे पर उनका संजीदा व्यवहार क्यों नहीं होता है? आखिर राजनीतिक दलों में ईमानदार इच्छाशक्ति क्यों नहीं नजर आती है? हालिया चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सिर्फ पांच फीसदी महिलाओं का चुना जाना बताता है कि इस दिशा में सभी राजनीतिक दलों का आधी दुनिया के प्रति एक जैसा नजरिया ही होता है। इसलिए जरूरी है कि महिलाएं जागरूक होकर अपने अधिकारों को पाने के लिए अपना संघर्ष तेज करें। अन्यथा राजनीतिक दल दशकों से लटके मुद्दे पर अपनी राजनीतिक सुविधा के अनुसार ही काम करेंगे। निश्चय ही हालिया विधानसभा के चुनाव परिणाम बताते हैं कि आधी दुनिया को जनप्रतिनिधि संस्थाओं में वाजिब हक दिलाने में राजनीतिक दलों की कवायद से, उनकी ईमानदारी को लेकर सवाल खड़े होना स्वाभाविक ही है।



पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 'विदेशी मुद्रा बचाने' के आह्वान के राजनीतिक-आर्थिक निहितार्थ

सरोज वार्ता/ब्यूरो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी प्रकार की आपदा को अवसर में बदलना जानते हैं। पहले कृत्रिम वैश्विक महामारी कोरोना (कोविड-19), फिर रूस-यूक्रेन युद्ध और अब अमेरिका/इजरायल-ईरान युद्ध के दौरान भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है। फिलवक्त मौजूदा वैश्विक संकट से भारत को निजात दिलाने और इससे प्रभावित हो रहे आम भारतीयों के हितों की रक्षा करने के लिए ही उन्होंने विदेशी मुद्रा बचाने, आयातित वस्तुओं का उपभोग मितव्ययिता पूर्वक करने और इनके मौजूद देशी विकल्प को आजमाते हुए स्थायी हल निकालने और उनपर निर्भर होने की दिशा में जनसहयोग का आह्वान करके सबको चौंका दिया है। समझा जाता है कि अमेरिका, चीन, यूरोप और अरब के कुछ देशों के द्वारा लगातार भारत विरोधी षड्यंत्र किए जा रहे हैं। कोई अपना इस्लामिक एजेंडा भारत पर थोपना चाहता है तो कोई भारत-रूस के भरोसेमंद सम्बन्धों में पलीता लगाना चाहता है और कोई भारत को पाकिस्तान, बंग्लादेश और चीन के त्रिपक्षीय कुचक्र में उलझा कर अपना आर्थिक हित साधना चाहता है। जबकि, तेजी से आर्थिक और सैन्य उन्नति कर रहा 21वीं सदी का भारत अब

> ● प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मौजूदा सरकार अपनी त्रासदी से निपटने के लिए आपसे कोई सोना नहीं मांग रही है, बल्कि अगले 1 साल तक इनकी खरीदारी कम करने की बात कह रही है ताकि विदेशी मुद्रा बचे। इसी कड़ी में उन्होंने उन तमाम वस्तुओं का जिक्र बारी-बारी से किया और कहा कि इनपर विदेशी मुद्रा ज्यादा खर्च होते हैं, इसलिए अगले 1 साल तक इनका संयमित उपभोग कीजिए। दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कीजिए।

रूस-ईरान-इजरायल के सहयोग से मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और यूरोप के बाजारों तक पहुंच बढ़ाने की दिशा में अग्रसर है। भारत-यूरोप की बढ़ती नजदीकियों और उसको निकट भविष्य में और अधिक बल देने वाली विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं पर अमल से चिढ़े अमेरिकी डीप स्टेट और उनके चीनी-अरबी पिट्ठुओं ने पहले ईरान को बर्बाद करने और फिर इंडिया को उसकी तपिश में झुलसाने की जो कुचक्र रची है, अब भारत उसकी भी काट ढूंढ चुका है। इस बार भारत ने लोकल फ़ॉर वोकल और चीनी वस्तुओं के बहिष्कार करने की जगह विदेशी मुद्रा बचाने हेतु विभिन्न सकारात्मक पहल करने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मौजूदा सरकार अपनी त्रासदी से निपटने के लिए आपसे कोई सोना नहीं मांग रही है, बल्कि अगले 1 साल तक इनकी खरीदारी कम करने की बात कह रही है ताकि विदेशी मुद्रा बचे। इसी कड़ी में उन्होंने उन तमाम वस्तुओं का जिक्र बारी-बारी से किया और कहा कि इनपर विदेशी मुद्रा ज्यादा खर्च होते हैं, इसलिए अगले 1 साल तक इनका संयमित उपभोग कीजिए। दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कीजिए। स्पष्ट है कि यह सिर्फ 'देशभक्ति' वाला संदेश नहीं होता; बल्कि यह आर्थिक संकेत भी होता है कि सरकार को वैश्विक अनिश्चितता, महंगे आयात, या डॉलर पर दबाव की चिंता है। ऐसा इसलिए कि जब विदेशी मुद्रा पर दबाव होता है, तब देश कोशिश करता है कि रुपये पर ज्यादा दबाव न पड़े, जरूरी आयात (तेल, दवा, रक्षा) जारी रह सकें, महंगाई नियंत्रित रहे, विदेशी मुद्रा भंडार सुरक्षित रहे। उल्लेखनीय है कि भारत की विदेशी मुद्रा कई बड़े क्षेत्रों में खर्च होती है, लेकिन सबसे ज्यादा खर्च आयात पर होता है। अगर 'सबसे ज्यादा' की बात करें, तो आमतौर पर क्रम

कुछ ऐसा रहता है:

1. **कच्चा तेल**
2. **इलेक्ट्रॉनिक्स/मशीनरी**
3. **सोना**
4. **रसायन/उर्वरक**
5. **रक्षा खरीद।**

हाल के वर्षों में भारत का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा खर्च कच्चे तेल के आयात पर ही रहा है। उनके हाल के बयान की बात करें तो मौजूदा वैश्विक संकट (जैसे युद्ध, तेल कीमतें, सप्लाई-चेन दबाव) के बीच प्रधानमंत्री ने विदेशी मुद्रा (स्नशहद्ग×) बचाने की बात जब कही, तो इसका अर्थ आमतौर पर यह होता है कि भारत डॉलर में होने वाले खर्च को कम करे और आय बढ़ाए।

● **उल्लेखनीय है कि ऐसे आह्वानों के मुख्य बिंदु आमतौर पर ये होते हैं:** आयात कम करना/ आत्मनिर्भरता बढ़ाना- खासकर तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा, खाद्य तेल जैसी चीजों में विदेश निर्भरता घटाना। 'लोकल खरीदें' और घरेलू उत्पादन बढ़ाने की बात इसी से जुड़ती है। इसलिए प्रधानमंत्री द्वारा 'विदेशी मुद्रा बचाने' की बात का राजनीतिक-आर्थिक मतलब संदर्भ पर निर्भर करता है, लेकिन आम तौर पर इसके कई स्तर होते हैं। इसके मायने क्या हैं? इसे ऐसे समझते हैं।

● **पहला, आर्थिक मायने:** आयात बिल कम करने का संकेत। चूंकि भारत का बड़ा विदेशी मुद्रा खर्च तेल, सोना और इलेक्ट्रॉनिक्स आयात पर होता है। लिहाजा जब सरकार विदेशी मुद्रा बचाने की बात करती है, तो अक्सर मतलब होता है: घरेलू उत्पादन बढ़ाओ ('मेक इन इंडिया' जैसी नीति), आयातित वस्तुओं पर निर्भरता घटाओ, ऊर्जा बचत या वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा दो और रुपये और व्यापार घाटे पर दबाव कम करो। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा डॉलर बाहर जाते हैं तो रुपये पर दबाव पड़ सकता है और व्यापार घाटा बढ़ सकता है। इसलिए विदेशी मुद्रा बचाने का संदेश बाजार को यह संकेत भी देता है कि सरकार बाहरी आर्थिक जोखिमों को लेकर सतर्क है। चूंकि ऊर्जा सुरक्षा का मुद्दा अहम है इसलिए तेल आयात महंगा होने पर सरकार कभी-कभी ईंधन बचत, एथेनॉल मिश्रण, इलेक्ट्रिक वाहन, या घरेलू उत्पादन पर जोर देती है ताकि डॉलर खर्च कम हो। वहीं, विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत रखने से आयात भुगतान, संकट प्रबंधन और निवेशकों का भरोसा बनाए रखने में मदद मिलती है।

● **दूसरा, राजनीतिक मायने:** आत्मनिर्भरता की राजनीतिक कथा जैसा संदेश अक्सर 'देशी बनाम विदेशी निर्भरता' या आत्मनिर्भरता के नैरेटिव से जुड़ता है–यानी आर्थिक राष्ट्रवाद का तत्व। वहीं जनता से व्यवहार परिवर्तन की अपील के पीछे कभी-कभी सरकार जनता से कुछ आदतें बदलने (जैसे ऊर्जा बचत, आयातित वस्तुओं का कम उपयोग) की नैतिक अपील करती है, ताकि नीति को सामाजिक समर्थन मिले। इससे कठिन आर्थिक समय का संकेत भी मिलता है। स्पष्ट है कि यदि बयान ऐसे समय आए जब तेल महंगा हो, डॉलर मजबूत हो, या वैश्विक संकट हो, तो यह आर्थिक सावधानी का संकेत भी माना जा सकता है–हालाँकि जरूरी नहीं कि संकट ही हो। जहां तक नीतिगत फैसलों की पृष्ठभूमि तैयार करने की बात है तो ऐसे बयान आगे चलकर कुछ कदमों (आयात शुल्क, उत्पादन प्रोत्साहन, ऊर्जा नीति, निर्यात बढ़ावा) के लिए राजनीतिक आधार भी बना सकते हैं।

● **आइए, यहां पर हमलोग समझते हैं कि किन-किन वस्तुओं पर विदेशी मुद्रा ज्यादा खर्च होती है-**

● **पहला, कच्चा तेल और पेट्रोलियम आयात:** भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा तेल विदेशों से खरीदता है। इसलिए विदेशी मुद्रा का सबसे बड़ा खर्च तेल, गैस और पेट्रोलियम उत्पादों पर होता है। उदाहरण: ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) जैसी घरेलू कंपनियाँ उत्पादन करती हैं, फिर भी आयात बहुत अधिक है।

● **दूसरा, सोना आयात:** भारत दुनिया के सबसे बड़े सोना उपभोक्ताओं में है। ज्वेलरी और निवेश के लिए भारी मात्रा में सोना आयात किया जाता है, जिससे डॉलर में भुगतान करना पड़ता है।

● **तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी:** मोबाइल फोन के पार्ट्स, सेमीकंडक्टर, कंप्यूटर उपकरण, औद्योगिक मशीनें आदि विदेशों से आती हैं। जैसे एप्पल इंक. या अन्य ब्रांडों के कंपोनेंट्स का आयात।

● **चौथा, रक्षा उपकरण:** लड़ाकू विमान, हथियार, रक्षा तकनीक और सैन्य उपकरणों की खरीद पर भी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। उदाहरण: राफेल जैसे विमान खरीद।

● **पांचवां, रसायन, उर्वरक और दवाओं का कच्चा माल:** खेती के लिए उर्वरक और दवा उद्योग के लिए कई सक्रिय रसायन विदेशों से मंगाए जाते हैं।

● **छठा, विदेश यात्रा और शिक्षा:** भारतीय जब विदेश में पढ़ाई, इलाज, पर्यटन या बिज़नेस के लिए खर्च करते हैं, तब भी विदेशी मुद्रा बाहर जाती है।

● **सातवां, विदेशी कंपनियों को भुगतान:** टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर लाइसेंस, रॉयल्टी, निवेशकों को मुनाफा आदि के रूप में भी डॉलर/विदेशी मुद्रा जाती है।

● **आठवां, ऊर्जा बचत:** तेल आयात भारत का बड़ा विदेशी मुद्रा खर्च है। पेट्रोल-डीजल की खपत कम करना, गैस/बिजली की बचत, वैकल्पिक ऊर्जा अपनाना–इनका सीधा असर डॉलर बचत पर पड़ता है। वैश्विक संघर्षों से तेल आपूर्ति प्रभावित होने की चिंता सरकार ने भी जताई है।

● **नौवां, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा:** विदेशी सामान की जगह भारतीय उत्पाद खरीदने से डॉलर बाहर कम जाता है। 'वोकल फॉर लोकल' का आर्थिक मतलब यही है।

● **दसवां, निर्यात और निवेश बढ़ाना:** विदेश से डॉलर कमाने के लिए निर्यात, सेवाएँ, और विदेशी निवेश आकर्षित करने पर जोर।





विधानसभा चुनाव परिणामः स्पष्ट जनादेश, नई सरकारों की होगी कड़ी अग्निपरीक्षा

मृत्युंजय दीक्षित

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम आ चुके हैं। नई सरकारों के गठन की प्रक्रिया आरम्भ हो चुकी है। बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुद्दुचेरी के ये विधानसभा चुनाव परिणाम कई स्पष्ट संकेत देने वाले हैं। बंगाल, असम, और पुद्दुचेरी ने जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले भाजपा व राजग गठबंध को दो तिहाई बहुमत के साथ चुना वहीं तमिलनाडु और केरल में भी सत्ता बदल गई। बंगाल, असम और पुद्दुचेरी में विकास, कल्याणकारी योजनाओं व हिंदुत्व का कमाल रहा। असम में कल्याणकारी योजनाओं के सहारे भाजपा जहां महिलाओं और युवाओं को साधने में सफल रही वहीं मुख्यंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ मुहिम छेड़कर नस्ल, क्षेत्र और भाषा में बनते हिंदुओं को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई। असम और बंगाल की जनता को भाजपा यह भरोसा दिलाने में सफल रही कि केवल भाजपा ही बांग्लादेशी घुसपैठ की समस्या से मुक्ति दिला

> *ईरान पर हमले के बाद यह आशंका बढ़ गई है कि अमेरिकी नागरिकों के खिलाफ दुनिया में क्रोध पनपे। यह भी हो सकता है कि आतंकी घटनाएं बढ़ें। गुरिल्ला युद्ध और ईरान समर्थित ताकतों द्वारा आतंकवाद के मुखौटे में अमेरिका और उसके समर्थकों को निशाना बनाया जाए। इससे दुनिया की चिंताएं बढ़ना अस्वाभाविक नहीं है।*

सकती है। बंगाल और असम के बाद सबसे अधिक चर्चा तमिलनाडु को लेकर हो रही है। तमिलनाडु के चुनाव परिणामों ने सभी को हैरान कर दिया है। एक बार द्रमुक और एक बार अन्नाद्रमुक का मिथक टूट गया है। फिल्म स्टार विजय की झोली वोटों से भरी है। केरलम में पराजय के बाद देश भर से वामपंथी सरकारों का अंत हो चुका है तथापि वह अपना राजनैतिक और वैचारिक अस्तित्व बचाए रखने के लिए दो विधायकों के बल पर तमिलनाडु में एक्टर थलपति विजय की नई सरकार मे घुस रही है। सभी राज्य विधानसभाओं में भाजपा का खाता खुल चुका है। पहली बार केरलम में भाजपा के तीन व तमिलनाडु में एक विधायक जीतने में सफल रहे हैं। तमिलनाडु में थलपति विजय की सरकार- तमिलनाडु की जनता द्रविड़ राजनीति से हताश और निराश हो चुकी थी। कभी द्रमुक और कभी अन्ना द्रमुक राज्य इनके बीच में झूलता रहता था। तमिल राजनीति में फिल्मी कलाकारों की अहम भूमिका रही है एम. जी. रामचंद्रन से लेकर करुणानिधि और जयललिता जैसे सितारों ने वहां की राजनीति में अहम भूमिका निभाई और लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। तमिलनाडु में एक्टर थलपति विजय की इतनी प्रचंड लहर चली कि मुख्यमंत्री स्टालिन अपनी सीट तक हार गए। इस लहर का आभास किसी भी राजनैतिक विश्लेषक

को नही था। एक्टर थलपति विजय की विजय में मुख्य भूमिका उनके चुनावी वायदों ने की है जो अधिकांशतः मुफ्त की रेवड़ी वाले हैं। विवाह के लिए महिलाओं को 22 कैरेट का आठ ग्राम सोना देने से लेकर 60 सल से कम आयु की महिलाओं को 2500 रुपए मासिक सहायता प्रति परिवार छह फ्री सिलेंडर देने का वादा काम कर गया। गरीब दुल्हनों के लिए रेशमी साड़ी और महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूहों के लिए पांच लाख रुपए तक के बयाज मुक्त ऋण का आश्वासन भी विजय ने दिया है। थलपति विजय ने वैसे ही कई लोक लुभावन वायदे किये है जैसे कभी आप नेता अरविंद केजरीवाल किया करते थे। यह थलपति विजय तमिलनाडु के केजरीवाल सिद्ध हो सकते हैं। ईसाई पिता ओर हिंदू मां की संतान विजय ने अपनी पार्टी की विचारधारा तैयार करने में द्रविड़ विचारधारा और तमिल राष्ट्रवाद के तत्वों को जोड़ा है। इनकी पार्टी तमिलगा वेटी कझागम की स्थापना फरवरी 2024 में हुई, जो तमिलनाडु और पुद्दुचेरी तक फैली हुई है। लोग सोच रहे हैं कि विजय की आखिर इतनी बड़ी विजय कैसे हो गई- विजय लम्बे समय से कई घरों के चूल्हों के ईंधन, बेटियों की पढ़ाई ओर बहनों की शादी का खर्च लगातार उठा रहे थे। उनके वोटबैक में सबसे बड़ी हिस्सेदारी महिलाओं और युवाओं की रही है। वह अपनी फिल्मों में गरीबों के मसीहा के तौर पर पेश किए जाते थे जिसका परिणाम अब सबके सामने है। विजय की चुनावी जनसभाओं में अभूवपूर्व भीड़ उमड़ रही थी किंतु कोई राजनैतिक विश्लेषक यह मानकर नहीं चल रहा था कि वह सरकार बनाने तक पहुंच जाएंगे।



तमिलनाडु में यदि कोई सबसे बड़ा परजीवी दल साबित हुआ है तो वह कांग्रेस है क्य उसने हर बार की तरह अपना अस्तित्व बचाये रखने के लिए एक और क्षेत्रीय दल की सरकार में गठबंधन के बहाने सेंधमारी कर ली है। जो दल कांग्रेस के साथ गए व कांग्रेस जिन दलों के साथ गई उन दलों का क्या हाल हो रहा है सभी को पता है। वैसे अभी थलपति विजय का शपथ ग्रहण समारोह भी ग्रहण ग्रस्त लग रहा है।



सिनेमा से बिजनेस तक: अभिनेत्री दिविता जुनेजा की नई उड़ान

सरोज वार्ता/ब्यूरो



अंबाला व चंडीगढ़ के बीच पली-बढ़ी दिविता जुनेजा के जीवन में सिनेमा ने काफी जल्दी दस्तक दे दी थी। देश के जाने-माने उद्यमी संजीव जुनेजा की बेटी होने के नाते उन्हें बचपन से ही बिजनेस और ब्रांडिंग की बारीकियों को करीब से समझने का अवसर मिला। उनके पिता ने पेन रिलीफ और पेट केयर से जुड़े प्रोडक्ट्स के क्षेत्र एक मजबूत और सफल बिजनेस खड़ा किया है, जिसका प्रभाव दिविता की सोच और विजन में साफ दिखाई देता है। हाल ही में रिलीज हुई उनकी डेब्यू फिल्म 'हीर एक्सप्रेस' में उन्होंने अनुभवी कलाकारों के साथ स्क्रीन साझा की, लेकिन दिविता की असली खासियत सिर्फ अभिनय तक सीमित नहीं है। उनका आफ-स्क्रीन विजन और उद्यमशीलता उन्हें अलग पहचान दिला रही है। इसी कड़ी में, दिविता अब अपने पहले वेडिंग-थीम्ड पाप-अप इवेंट के साथ मुंबई के वर्ली स्थित एक स्टूडियो में कदम रखने जा रही हैं, जहां वह अपने लक्जरी फ्रेग्रेंस ब्रांड D'JANAÉ Attars को लान्च करेंगी। यह ब्रांड खास तौर पर शादियों और बड़े सेलिब्रेशन्स से जुड़े हाई-वैल्यू गिफ्टिंग सेगमेंट को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। मास मीडिया में स्नातक दिविता का फ्रेग्रेंस को लेकर नजरिया बेहद स्पष्ट और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। D'JANAÉ Attars का मतलब है 'डिवाइन एसेंस' यानी ऐसी खुशबू जो सिर्फ महक नहीं, बल्कि एक भावना और अनुभव बनकर उभरे। ब्रांड के अंतर्गत Shanti, Shringaar, Oud Al Mallk और Oud Al Mallka जैसे प्रोडक्ट्स शामिल हैं, जो पारंपरिक भारतीय खुशबूओं को आधुनिक और प्रीमियम टच के साथ प्रस्तुत करते हैं।



D'JANAÉ की खासियत सिर्फ इसकी खुशबू तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कस्टमाइज्ड और पर्सनलाइज्ड गिफ्टिंग एक्सपीरियंस भी प्रदान करता है। जिसमें नाम, इनीशियल्स, खास संदेश और प्रीमियम पैकेजिंग शामिल हैं। यह ब्रांड उन लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो अपने खास पलों को और भी खास बनाना चाहते हैं।दिविता का लक्ष्य स्पष्ट है कि भारत की पारंपरिक खुशबूओं को एक ग्लोबल और लक्जरी पहचान देना, जो देश के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी अलग छाप छोड़ सके। सिनेमा और बिजनेस, दोनों क्षेत्रों में अपने कदम मजबूती से रखते हुए, दिविता जुनेजा एक नई पीढ़ी की ऐसी युवा हस्ती के रूप में उभर रही हैं, जो परंपरा और आधुनिकता के बीच एक खूबसूरत संतुलन बनाकर आगे बढ़ रही हैं।

एसजेवीएन और टीएचडीसी के निदेशक ने 1500 मेगावाट की नाथपा झाकड़ी एचपीएस और 412 मेगावाट की रामपुर एचपीएस परियोजनाओं का दौरा किया

सरोज वार्ता/ब्यूरो



एसजेवीएन लिमिटेड के निदेशक (वित्त) श्री पार्थजीत डे और एनएचपीसी लिमिटेड के निदेशक (वित्त) श्री महेश कुमार शर्मा ने हिमाचल प्रदेश में स्थित 1500 मेगावाट के नाथपा झाकरी जलविद्युत स्टेशन (एनजेएचपीएस) और 412 मेगावाट के रामपुर जलविद्युत स्टेशन (रामपुर एचपीएस) का दौरा किया। रामपुर एचपीएस के परियोजना प्रमुख श्री विकास मारवाह, एनजेएचपीएस के परियोजना प्रमुख श्री राजीव कपूर, लुहरी-1 एचईपी के परियोजना प्रमुख श्री विवेक शर्मा और परियोजना के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका हार्दिक स्वागत किया। एनजेएचपीएस और रामपुर एचपीएस में, गणमान्य व्यक्तियों ने विद्युत संयंत्रों का दौरा किया और दोनों विद्युत संयंत्रों के परिचालन प्रदर्शन, रखरखाव प्रक्रियाओं, दक्षता पहलों और प्रमुख वित्तीय एवं तकनीकी मापदंडों के बारे में जानकारी प्राप्त की।

एनटीपीसी सिपट ने क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने के लिए अस्पतालों को सीएसआर पहल के तहत 7.19 करोड़ रुपये आवंटित किए



सरोज वार्ता/ब्यूरो

एनटीपीसी सिपट ने क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने के लिए अस्पतालों को सीएसआर पहल के तहत 7.19 करोड़ रुपये आवंटित किए। एनटीपीसी सिपट ने 7.19 करोड़ रुपये की सीएसआर पहल के माध्यम से क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवा को मजबूत किया है, जिससे बिजली से परे जीवन को बेहतर बनाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि होती है। यह कार्यक्रम माननीय केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री और बिलासपुर के सांसद श्री तोखन साहू की उपस्थिति में आयोजित किया गया था। कुमार साहब स्वर्गीय श्री दिलीप सिंह जुदेव सरकारी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं के समर्थन के लिए 4.27 करोड़ रुपये और सीआईएमएस में नए चिकित्सा उपकरणों के लिए 2.92 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह पहल बेहतर निदान, गंभीर उपचार और जीवन रक्षक सेवाओं को लोगों के करीब ला रही है। एनटीपीसी समय पर देखभाल, आशा और सम्मान के साथ जीवन को बेहतर बनाकर एक स्वस्थ और मजबूत समाज के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है।

अस्तित्व से अस्मिता की ओरः मध्य प्रदेश में महिला विकास के नए प्रतिमान

बिन्दु सुनील

मध्यप्रदेश की धरा पर 'नारी तू नारायणी' का मंत्र केवल उपदेशों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नीतिगत निर्णयों और जमीनी क्रियान्वयन की आधारशिला बन चुका है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के विजन में आज की महिला केवल शासन की योजनाओं की 'हितग्राही' नहीं है, बल्कि वह नए मध्य प्रदेश की 'भाग्य विधाता' और 'नेतृत्वकर्ता' बनकर उभर रही है। प्रदेश की नीतिगत प्राथमिकताओं में आए इस बुनियादी बदलाव ने आज मध्य प्रदेश को महिला केंद्रित विकास के मामले में देश के अग्रणी राज्यों की पंक्ति में खड़ा कर दिया है। मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की यात्रा केवल नारों तक सीमित न रहकर आर्थिक स्वावलंबन के ठोस धरातल पर टिकी है। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना इस बदलाव का सबसे मुखर प्रतीक बनकर उभरी है, जहाँ प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (ष्ठङ्क्ष) के माध्यम से जून 2023 से अब तक लगभग 55,926 करोड़ रुपये की विशाल राशि 1.26 करोड़ बहनों के बैंक खातों में पहुँचाई जा चुकी है। प्रति माह दी जाने वाली 1500 रुपये की यह सम्मान राशि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के आत्मविश्वास का संबल बनी है। आर्थिक सशक्तिकरण का यह सिलसिला यहीं नहीं रुकता, बल्कि स्व-सहायता समूहों के माध्यम से 62 लाख ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और 'लखपति दीदी' अभियान के तहत 12 लाख से अधिक महिलाओं की आय को एक लाख रुपये के पार ले जाना यह सिद्ध करता है कि प्रदेश की नारी अब परिवार की आर्थिक रीढ़ बन चुकी है। सुरक्षा और तकनीक के संगम ने मध्य प्रदेश की महिलाओं को एक नया आकाश दिया है। केंद्र सरकार की 'सेफ सिटी' परियोजना के तहत धार जिले का चयन होना और वहाँ 10 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक सुरक्षा ढांचा विकसित करना, राज्य सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है जहाँ भयमुक्त वातावरण को विकास की पहली शर्त माना गया है। पिंक टॉयलेट्स, चप्पे-चप्पे पर सीसीटीवी की निगरानी और अस्पतालों में विशेष सुविधाओं के साथ-साथ 'नमो ड्रोन दीदी' जैसी योजनाएं यह प्रमाणित करती हैं कि मध्य प्रदेश की बेटियाँ अब पारंपरिक सीमाओं को तोड़कर तकनीक के उच्चतम शिखरों को छू रही हैं। कृषि क्षेत्र में ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित हो रही महिलाएं आधुनिक भारत की नई पहचान बन रही हैं। डॉ. मोहन यादव की सरकार ने न केवल वर्तमान को संवारा है, बल्कि भविष्य की पीढ़ी के लिए भी सुरक्षा कवच तैयार किया है। वर्ष 2007 से संचालित लाड़ली लक्ष्मी योजना आज अपने उस मुकाम पर है जहाँ 53 लाख से अधिक बेटियों का भविष्य सुरक्षित है और वे उच्च शिक्षा के लिए 25,000 रुपये जैसी प्रोत्साहन राशियों के माध्यम से अपने सपनों को हकीकत में बदल रही हैं। सामाजिक न्याय की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने शासकीय सेवाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 35 प्रतिशत कर दिया है। यह निर्णय आने वाले समय में प्रशासन के हर स्तर पर स्त्री-शक्ति की निर्णायक भूमिका सुनिश्चित करेगा। इसके साथ ही, नगरीय निकायों में महिला प्रतिनिधियों के मानदेय में की गई वृद्धि उनके राजनैतिक सशक्तिकरण को नई ऊर्जा प्रदान कर रही है। औद्योगिक परिदृश्य में भी मध्य प्रदेश की नारी अब 'जॉब सीकर' के बजाय 'जॉब क्रिएटर' की भूमिका में है। एमएसएमई नीति-



2025 के तहत महिला उद्यमियों को 48 प्रतिशत तक का भारी अनुदान और स्टार्टअप्स के लिए विशेष वित्तीय सहायता ने प्रदेश के आर्थिक परिदृश्य को बदल दिया है। वर्तमान में प्रदेश के 47 प्रतिशत एमएसएमई उद्योगों का संचालन महिलाओं द्वारा किया जाना इस बात का प्रमाण है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में व्यापार और नवाचार के द्वार महिलाओं के लिए पूरी तरह खुल चुके हैं। स्वास्थ्य के मोर्चे पर 'मातृशिशु संजीवन अभियान' और 'प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना' में प्राप्त 91 प्रतिशत का लक्ष्य यह सुनिश्चित कर रहा है कि राज्य का आने वाला कल स्वस्थ और सुरक्षित हो।

नेतृत्व में हिस्सेदारीः 35 प्रतिशत आरक्षण का ऐतिहासिक निर्णय

डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार ने शासकीय सेवाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 35 प्रतिशत कर एक ऐतिहासिक मानक स्थापित किया है। यह निर्णय केवल रोजगार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नीति निर्माण की प्रक्रियाओं में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने वाला कदम है। नगरीय निकायों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के मानदेय में 20 प्रतिशत की वृद्धि उनके राजनीतिक सशक्तिकरण को और अधिक मजबूती प्रदान करती है। मध्य प्रदेश की एमएसएमई नीति-2025, जहाँ महिला उद्यमियों को 48 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है, यह स्पष्ट करती है कि आने वाला समय मध्य प्रदेश की महिला उद्यमियों का है। प्रदेश में 47 प्रतिशत एमएसएमई का महिलाओं द्वारा संचालित होना यह सिद्ध करता है कि वे अब रोजगार माँगने वाली नहीं, बल्कि रोजगार देने वाली बन गई हैं। मध्य प्रदेश की नारी अपनी सफलता के अमिट हस्ताक्षर कर रही है। डॉ. मोहन यादव के सक्षम नेतृत्व में राज्य आज देश को यह संदेश दे रहा है कि जब नीतियों में संवेदनशीलता और निर्णयों में दृढ़ता हो, तो नारी शक्ति केवल वंदनीय ही नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की सबसे प्रबल शक्ति बन जाती है।

नारी शक्ति का अधिकार और लोकतांत्रिक जिम्मेदारी



सरोज वार्ता

भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी केवल एक अधिकार नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की अनिवार्य आवश्यकता है। एक ऐसी महिला, जिसने अपने जीवन में अभाव, संघर्ष और सामाजिक चुनौतियों का सामना करते हुए सार्वजनिक जीवन में स्थान बनाया हो, वह भली-भांति समझ सकती है कि अवसर मिलने पर महिलाएं समाज को किस दिशा में ले जा सकती हैं। आज जब देश में महिला आरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण पहल की जा रही है, तब यह आवश्यक है कि सभी पक्ष मिलकर इस विषय पर सकारात्मक और रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। यह देश की आधी आबादी की भागीदारी सुनिश्चित करने का सशक्त प्रयास है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'नारी शक्ति वंदन' को 21वीं सदी का एक महत्वपूर्ण संकल्प बताया है। यह उस भारत की परिकल्पना है, जहां महिलाएं नीति निर्माण और नेतृत्व की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाएं और विकास की दिशा को सशक्त बनाएं। महिला आरक्षण को लेकर सरकार द्वारा गंभीर और प्रतिबद्ध प्रयास किए गए हैं, जिससे महिलाओं की भागीदारी को संस्थागत स्वरूप दिया जा सके। इस दिशा में आवश्यक प्रक्रियाएं भी आगे बढ़ाई गई, लेकिन सभी पक्षा की सहमति के अभाव में यह पहल अपने अपेक्षित परिणाम तक नहीं पहुंच सकी। यह विषय इतना महत्वपूर्ण है कि इसे सभी



श्रीमती संपतिया उइके

लेखिका, मध्यप्रदेश शासन की लोकस्वास्थ्य यांत्रिकीय मंत्री

पक्षों के सहयोग और सकारात्मक सहभागिता के साथ आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है, ताकि देश की आधी आबादी को उनका उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। महिला आरक्षण का 33 प्रतिशत प्रावधान केवल प्रतिनिधित्व बढ़ाने का प्रयास नहीं है, बल्कि यह सामाजिक संरचना को संतुलित करने का एक सशक्त माध्यम है। इससे महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में अधिक भागीदारी मिलेगी, नीति निर्माण में संवेदनशीलता बढ़ेगी और समाज के विभिन्न वर्गों की आवाज को उचित मंच प्राप्त होगा। विशेष रूप से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों की महिलाओं के लिए यह अवसर अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अनुभव यह दर्शाते हैं कि जब महिलाओं को अवसर मिलता है, तो वे समाज में व्यापक और सकारात्मक परिवर्तन लाने में सक्षम होती हैं। ग्राम पंचायत से लेकर विभिन्न स्तरों तक, महिलाओं ने अपनी नेतृत्व क्षमता का प्रभावी परिचय दिया है। स्व-सहायता समूहों के माध्यम से भी महिलाओं ने आर्थिक और सामाजिक बदलाव को नई दिशा दी है, जो नारी सशक्तिकरण का सशक्त उदाहरण है। यह आवश्यक है कि महिला सशक्तिकरण के इस प्रयास को सभी के सहयोग और समन्वय से आगे बढ़ाया जाए। यह किसी एक पक्ष का नहीं, बल्कि पूरे समाज का विषय है और इसमें सामूहिक प्रतिबद्धता ही सफलता का आधार बनेगी। आज भारत की महिलाएं जागरूक हैं, आत्मनिर्भर हैं और अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं। उनकी यह बढ़ती भागीदारी देश के विकास को नई गति दे रही है और आने वाले समय में यह परिवर्तन और अधिक व्यापक रूप में दिखाई देगा। नारी सशक्तिकरण का यह अभियान केवल एक पहल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत के सामाजिक और लोकतांत्रिक भविष्य को सशक्त बनाने की दिशा में एक सतत और दूरदर्शी प्रयास है।

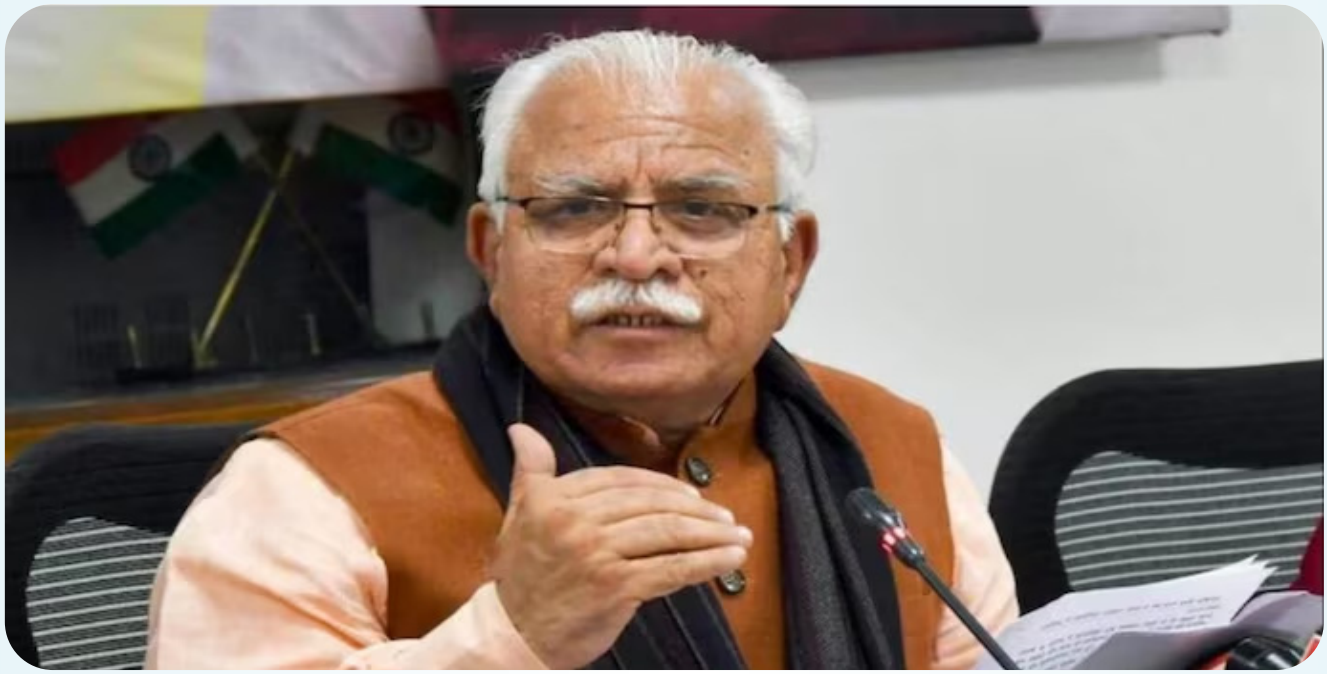
पंजाब में भाजपा सरकार बनने पर आमजन को देंगे हरियाणा जैसा सुशासनः नायब सिंह सैनी

सरोज वार्ता/ब्यूरो



हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंजाब में भाजपा सरकार बनने के बाद वहां के लोगों को हरियाणा की तरह सुशासन मिलेगा। हरियाणा की तरह ही पंजाब के वंचित वर्ग को भी प्लाट, मकान, बच्चों को शिक्षा, छात्रवृत्ति व इलाज सहित सभी सुविधाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने यह बात चंडीगढ़ स्थित अपने आवास 'संत कबीर कुटीर' में पंजाब के विभिन्न जिलों से आए धानक समाज के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करते हुए कही। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल के आग्रह पर 30 जून को संत कबीर दास जी के प्रकट दिवस पर पंजाब में वंचित अनुसूचित जाति (डीएससी समाज) द्वारा आयोजित किए जाने वाले समारोह में आने का न्यौता भी स्वीकार किया। इस अवसर पर पंजाब में लोकसभा का चुनाव लड़े मदनलाल खटक, मुख्यमंत्री के ओएसडी भारत भूषण भारती व महेंद्र सिंह सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। पंजाब में धानक समाज के अध्यक्ष सतीश खुंडिया ने समाज की समस्याएं बताते हुए कहा कि समाज के पढ़े-लिखे युवकों को रोजगार नहीं मिल रहा है और वे मंडियों में बोरियां ढोने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में विधानसभा की 117 में से 34 सीटें तथा लोकसभा की 13 में से 4 सीटें वंचित अनुसूचित जाति (डीएससी समाज) से बनती हैं लेकिन हमारी भागीदारी न तो विकास में है और न ही राजनीति में। उन्होंने कहा कि हरियाणा में डीएससी समाज ने जहां इतनी तरक्की कर ली है वहीं पंजाब में हालात बहुत खराब हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं आपके समाज की पीड़ा समझता हूं। पंजाब में कांग्रेस रही हो या वर्तमान आम आदमी पार्टी की सरकार, सभी ने पंजाब के वास्तविक विकास की ओर कभी ध्यान नहीं दिया। इन पार्टियों ने हमेशा लोगों पर राज किया है, कभी सेवा नहीं की। उन्होंने कहा कि वर्तमान मुख्यमंत्री कॉमेडियन से ज्यादा कुछ नहीं हैं और केजरीवाल का हाल तो सब जानते ही हैं जिसने दिल्ली और पंजाब में सबकुछ निचोड़ लिया। आम आदमी पार्टी ने पिछली बार लोगों को झूठे सब्जबाग दिखाकर पंजाब में सरकार बना ली लेकिन अब इनकी असलियत लोगों के सामने आ गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि साढ़े 11 साल पहले हरियाणा में भी इसी प्रकार के हालात थे लेकिन भाजपा सरकार ने मजबूत इरादों के साथ यहां की स्थिति को ठीक किया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार बनते ही हमने पुलिस विभाग में 5500 जवानों की भर्ती की जिसमें से 605 बच्चे डीएससी समाज से भर्ती हुए। हमने घोषणा की थी कि हर सिर को छत मिलनी चाहिए। कांग्रेस ने केवल 100-100 वर्ग गज के मकान देने की घोषणा की थी किसी को प्लाट के कागज या कब्जे नहीं दिए थे। लेकिन हमारी सरकार ने कांग्रेस के समय के वंचितों को प्लाटों के कागज व कब्जे दिए। इसके अलावा पोर्टल के माध्यम से जरूरतमंदों से आवेदन मंगवाकर 16500 परिवारों को अलग से 100-100 वर्गगज के प्लाट दिए। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना से जोड़कर इन प्लाटों पर मकान बनवाकर इनकी चाबियां पात्र परिवारों को सौंपी। पिछले साढ़े 11 सालों में हरियाणा सरकार ने 1.60 लाख मकान पात्र परिवारों को दिए हैं। जिन परिवारों को जमीन व प्लाट नहीं मिले उन्हें फ्लैट बनाकर दिए हैं। पिछले दिनों सोनीपत व गुरुग्राम में 3250 फ्लैट पात्र परिवारों को दिए गए हैं, अगले चरण में 4000 फ्लैट जल्द ही दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि हरियाणा में पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत 27.5 लाख लोगों को निःशुल्क इलाज मिला है जिसके लिए हरियाणा सरकार ने अस्पतालों को 4000 करोड़ रुपये दिए हैं। इसी प्रकार आज हरियाणा में गरीब-मजदूर परिवारों के बच्चे बिना सिफारिश और बिना रिश्वत अपनी मेहनत व योग्यता के आधार पर एचसीएस तक की नौकरियों के लिए चुने जा रहे हैं। हरियाणा में वंचित समाज के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है, वजीफे दिए जा रहे हैं, बेटियों को पोस्ट-ग्रेजुएशन तक की मुफ्त पढ़ाई, बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा है। हरियाणा के किसी भी हिस्से से बेटियों के लिए कॉलेज की सुविधा 20 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर नहीं है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा में 3 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले 50 लाख पात्र व्यक्तियों को 3200 रुपये प्रतिमाह और महिलाओं को चुनावी घोषणा के अनुरूप 2100 रुपये प्रतिमाह दिया जा रहा है। इसके लिए वर्तमान सरकार ने प्रथम बजट में 5000 करोड़ रुपये का तथा दूसरे बजट में 6500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके तहत अब तक महिलाओं के खातों में 1038 करोड़ रुपये की राशि भेजी जा चुकी है। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंजाब में बातें तो बड़ी-बड़ी हो रही हैं लेकिन काम नहीं हो रहा है। वहां सरकार का न तो नशे पर नियंत्रण है और न ही सरकार युवाओं को रोजगार दे पा रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब में बदलाव पंजाब के लोग ही ला सकते हैं और आने वाले चुनाव में लोगों के सामने सुनहरा मौका है। जब आप लोग बदलाव के लिए मेहनत करेंगे तभी आने वाली पीढ़ी का भविष्य संवरेगा। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को भरोसा दिलाया कि आने वाले पंजाब चुनाव में पूरा समाज भाजपा की जीत के लिए न केवल समर्थन देगा बल्कि भाजपा प्रत्याशियों की जीत के लिए दिन-रात मेहनत भी करेगा।

राष्ट्रसेवा में समर्पित जननायक श्री मनोहर लाल



डॉ. प्रभलीन सिंह

श्री मनोहर लाल जी के जन्मदिन के अवसर पर, मैं उनके दृढ़ निश्चय और अटूट नेतृत्व के सफर पर विचार करना चाहता हूं। श्री मनोहर लाल अपने 'राष्ट्रप्रथम - राष्ट्र सर्वोपरि' के दृष्टिकोण के कारण सारे देशवासियों के लिए आदरणीय और अनुकरणीय शख्सियत हैं। लम्बे समय से ही वह अपना जन्मदिन भव्य समारोहों के बजाय आध्यात्मिक और सामुदायिक गतिविधियों के साथ मनाते हैं। उन्होंने अपने सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन से अनगिनत लोगों को प्रेरणा दी है। विशेषकर युवाओं को, उन्होंने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठकर देश के हित में स्वयं को समर्पित करने की सीख दी है। वे अनुशासन, सेवा और राष्ट्र के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का एक जीता-जागता उदाहरण हैं। हरियाणा के एक साधारण किसान परिवार से अपने जीवन की शुरुआत करने वाले श्री मनोहर लाल का जीवन सादगी और परिश्रम पर आधारित रहा है। जमीनी हकीकतों से उनका शुरुआती परिचय ही उन्हें आम आदमी के संघर्षों और आकांक्षाओं की गहरी समझ प्रदान करता है। उनकी विशेषता यह है कि उन्होंने सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए प्रसिद्धि की लालसा के बजाय सादगी और सरलता का मार्ग चुनना पसंद किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ाव ने श्री मनोहर लाल जी के चरित्र की नींव रखी। प्रचारक के अनुशासित और निस्वार्थ जीवन को चुनकर उन्होंने सेवा और त्याग के मूल्यों को आत्मसात किया। सेवा के उद्देश्य के प्रति समर्पित होकर उन्होंने हरियाणा और अन्य क्षेत्रों की यात्रा की और अत्यंत साधारण जीवन स्थितियों में कठिन दिनचर्या का सामना किया। इन प्रारंभिक वर्षों ने उनके जीवन भर के वैराग्य और एक व्यापक उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्धता के दर्शन को आकार दिया। साल 1994 में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से सार्वजनिक जीवन में हुआ उनका प्रवेश एक नए अध्याय की शुरुआत थी। उनकी संगठनात्मक क्षमता और दूरदर्शिता ने शासन को बड़े स्तर पर प्रभावित किया। लगातार दो कार्यकाल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने प्रशासनिक दक्षता को नई परिभाषा दी। मैंने देखा है कि राज्य को उनकी जन-कल्याणकारी नीतियों जैसे पारदर्शी प्रणाली, ऑनलाइन तबादलों, योग्यता और मैरिट आधारित भर्ती से आमजन को कितना लाभ हुआ है। उनके कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने जनता का शासन में विश्वास बहाल किया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि हर सरकारी स्कीम का लाभ हर जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे। श्री मनोहर लाल की 10 साल की पारदर्शी जन स्कीमों की बदौलत हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री के रूप में शहरी जीवन स्तर को बेहतर बनाने के उनके प्रयास भी सराहनीय हैं। चाहे वह शहरी बाढ़ से निपटना हो, मेट्रो परियोजनाओं और स्मार्ट शहरों को गति देना हो या लाखों लोगों को घर उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवासयोजना-शहरी को आगे बढ़ाना हो। इन सभी क्षेत्रों में श्री मनोहर लाल जी के द्वारा पूरी निष्ठा से अभूतपूर्व कार्य किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन में उनके नेतृत्व ने पहले ही सैकड़ों कचरा स्थलों को उपयोगी भूमि में बदल दिया है। यह चुनौतियों को अवसरों में बदलने के उनके विश्वास को दर्शाता है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के रूप में श्री मनोहर लाल जटिल और चुनौती पूर्णवैश्विक भू-राजनीतिक स्थिति के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उनका मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भर और टिकाऊ ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण करना और संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अवसंरचना परियोजनाओं का प्रबंधन करना है। श्री मनोहर लाल जी मोदी 3.0 मंत्रिमंडल के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं और भारत के तीव्र अवसंरचना विस्तार, ऊर्जा परिवर्तन और शहरी विकास पहलों के प्रबंधन में केंद्रीय भूमिका निभा रहे हैं। श्री मनोहर लाल जी समर्पण की जीती जागती मिसाल है। तकरीबन 10 साल के मुख्यमंत्री कार्यकाल में जो सैलरी मिली, वो उन्होंने पद छोड़ने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में सारा पैसा देश के विकास हेतु जमा करवा दिया । गांव का घर, स्कूल को और लाइब्रेरी बनाने के लिए दान में दे दिया । अपने हिस्से की 1.5 एकड़ जमीन भी बेचकर जो पैसा मिला उसे भी प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में जमा करवा दिया। आज के युग में ऐसे समर्पण वाले इंसान बहुत कम मिलते हैं। श्री मनोहर लाल जी को जो बात सबसे अलग बनाती है, वह है उनका संदेश 'दुनिया के लिए खुद को ज़रूरी बनाओ - दुनिया तुम्हारा ख्याल रखेगी।' यह इस बात का सशक्त संदेश है कि निस्वार्थ योगदान ही सफलता का सर्वोच्च रूप है। उनके जन्मदिन पर, हम उन्हें न केवल एक नेता, बल्कि एकसत्यनिष्ठ और सिद्धांतवादी व्यक्ति के रूप में स्मरण करते हैं और भगवान से अरदास करते हैं कि उनको स्वस्थ जीवन और लंबी आयु दे, ताकि वह इसी साहस के साथ देश की सेवा करते रहें।

छत्तीसगढ़ की जड़ी-बूटियों से महकेगा नारी शक्ति का स्वावलंबन



धनंजय राठौर

छत्तीसगढ़ के वनांचल की गोद में छिपी अमूल्य औषधि संपदा अब केवल स्वास्थ्य का आधार नहीं, बल्कि प्रदेश की नारी शक्ति के आर्थिक स्वावलंबन का नया अध्याय बन रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार सुशासन की जिस परिकल्पना को साकार कर रही है, उसे वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप और छत्तीसगढ़ आदिवासी, स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के अध्यक्ष श्री विकास मरकाम के मार्गदर्शन में धरातल पर उतार रहा है। गिलोय, कालमेघ, बहेड़ा, सफेद मूसली, जंगली हल्दी, गुड़मार, अश्वगंधा, और शतावरी जैसी महत्वपूर्ण औषधीय वनस्पतियों से अर्क और उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं।

● पारंपरिक ज्ञान को वैज्ञानिक पहचान

वनांचल में बिखरे पारंपरिक ज्ञान को महज एक स्मृति न रहने देने के संकल्प के साथ बोर्ड ने इसे वैज्ञानिक पद्धति से जोड़ने का निर्णय लिया है। इसके तहत उन स्थानीय वैद्यों और जानकारों का चिन्हांकन शुरू किया गया है, जिनके पास असाध्य रोगों के उपचार का अद्भुत ज्ञान है। बोर्ड का प्रयास इन महिलाओं को एक उचित मंच प्रदान करना है, ताकि उनकी विशेषज्ञता का लाभ समाज को मिले और वे स्वयं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ कर सकें। यह केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि उस विरासत का सम्मान है जिसे ग्रामीण महिलाओं ने



सदियों से सहेजकर रखा है। छत्तीसगढ़ में पारंपरिक जड़ी-बूटी और जनजातीय ज्ञान को अब आधुनिक विज्ञान के माध्यम से नई पहचान मिल रही है। राज्य के वनों में छिपे औषधीय खजाने को वैज्ञानिक आधार पर प्रमाणित कर, उसे आजीविका के साधन के रूप में विकसित किया जा रहा है।

● संग्रहण से प्रसंस्करण तक- उद्यमिता की नई उड़ान

आर्थिक मोर्चे पर सबसे बड़ा बदलाव तब दिखाई दे रहा है, जब जड़ी-बूटियों का संग्रहण करने वाली महिलाएं अब संग्राहक से आगे बढ़कर निर्माता की भूमिका में नजर आ रही हैं। बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुरूप, महिला स्व-सहायता समूहों को औषधि प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) के उन्नत गुर सिखाए जा रहे हैं। यह पहल न केवल औषधीय पौधों का संरक्षण कर रही है, बल्कि वनवासियों और लघु वन उपज संग्राहकों की आय में वृद्धि करके उन्हें आत्मनिर्भर बना रही है। छत्तीसगढ़ में 1500 से अधिक सक्रिय वैद्यों के ज्ञान को सहेजने और जड़ी-बूटियों के विपणन के लिए छत्तीसगढ़ जनजातीय स्थानीय स्वास्थ्य परंपराएं और औषधीय पादप बोर्ड सक्रिय रूप से काम कर रहा है। यह संस्था हर्बल उत्पादों की खेती, मूल्य संवर्धन, और मार्केटिंग में तकनीकी सहायता और सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करती है।

● मूल्य संवर्धन (वेल्यू एडिशन)

छत्तीसगढ़ में जड़ी-बूटी मूल्य संवर्धन एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके माध्यम से राज्य के समृद्ध वन संसाधनों को वैज्ञानिक तरीके से संसाधित (प्रोसेस) करके उनके आर्थिक मूल्य को बढ़ाया जा रहा है। राज्य सरकार 'छत्तीसगढ़ हर्बल्स' ब्रांड के तहत इन उत्पादों को बढ़ावा दे रही है। जब ये महिलाएं वनों से प्राप्त कच्ची सामग्री को साफ कर, सुखाकर उसे चूर्ण, अर्क या तेल के रूप में परिवर्तित करती हैं, तो उत्पाद की कीमत और गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है। इस मूल्य संवर्धन का सीधा आर्थिक लाभ उनके बैंक खातों तक पहुँच रहा है, जिससे बिचौलियों का वर्चस्व पूरी तरह समाप्त हो गया है। गिलोय, कालमेघ, बहेड़ा, सफेद मूसली, जंगली हल्दी, गुड़मार, अश्वगंधा, और शतावरी जैसी महत्वपूर्ण औषधीय वनस्पतियों

से अर्क और उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। 65 से अधिक लघु वन उपज प्रजातियों की

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदी और उनका प्रसंस्करण किया जा रहा है। यह पहल छत्तीसगढ़ को एक प्रमुख हर्बल स्टेट के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो परंपरा और आधुनिक तकनीक का संगम है।

● छत्तीसगढ़ हर्बल्स को वैश्विक पहचान

छत्तीसगढ़, जिसे 'जड़ीबूटि गढ़' भी कहा जाता है, अपने घने जंगलों, विशेषकर बस्तर में 160 से अधिक प्रकार की दुर्लभ जड़ी-बूटियों का प्राकृतिक खजाना है। यहाँ की मिट्टी में अश्वगंधा, सर्पगंधा, गोक्षुरा (गोखरू), कुटकी और तिखुर जैसी औषधियां पाई जाती हैं, जो स्वास्थ्य और जीवन शक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। बाजार की चुनौतियों को अवसर में बदलते हुए बोर्ड ने विपणन (मार्केटिंग) तंत्र को पारदर्शी बनाया है। प्रदेश के छत्तीसगढ़ हर्बल्स ब्रांड को सशक्त करने के लिए प्रदर्शनियों और रिटेल आउटलेट्स के माध्यम से इन उत्पादों को सीधे शहरी उपभोक्ताओं तक पहुँचाया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 'व्होकल फार लोकल' और मुख्यमंत्री के 'लखपति दीदी' अभियान को सफल बनाने में यह रणनीति संजीवनी का कार्य कर रही है।

● नर्सरी प्रबंधन और स्थानीय रोजगार

जड़ी बूटियों को किचिन गार्डन, होम गार्डन में खिड़की, बालकनी, टेरिस पर गमलों, या अन्य कंटेनरों में कभी भी उगाया जा सकता है। कंटेनर गार्डनिंग या ग्रो बैग में जड़ी-बूटियां उगाने का एक फायदा यह भी है कि जड़ी-बूटी को उसकी जरूरत के आधार पर मिट्टी, पोषक तत्व, सूर्य प्रकाश और नमी के स्तर को नियंत्रित किया जा सकता है तथा गमलों में उगाई गई प्रत्येक जड़ी-बूटी (हर्बल) को उसकी आदर्श स्थितियां दे सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण और आजीविका के बीच संतुलन बनाने के उद्देश्य से औषधीय पौधों की 'मदर नर्सरी' विकसित करने की जिम्मेदारी महिला समूहों को सौंपी जा रही है। इससे दुर्लभ जड़ी-बूटियों की प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर महिलाओं के लिए बारहमासी रोजगार के द्वार खुल गए हैं, जिससे वनांचल से होने वाले पलायन पर भी अंकुश लगा है।

● समृद्ध नारी, सशक्त छत्तीसगढ़

राज्य शासन का यह समेकित दृष्टिकोण इस बात का प्रमाण है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशानुरूप छत्तीसगढ़ आदिवासी, स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड केवल एक प्रशासक की नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक की भूमिका निभा रहा है। सामूहिक नेतृत्व और संस्थागत सुधारों पर जोर देने से आज छत्तीसगढ़ की बेटियां आत्मनिर्भर बन रही हैं। वनांचल की महिलाओं के चेहरे पर उपजी मुस्कान एक समृद्ध और स्वावलंबी छत्तीसगढ़ की सच्ची तस्वीर पेश कर रही है।

सुशासन तिहार 2026: जन-जन तक पहुंचती सरकार

सरोज वार्ता/ब्यूरो

छत्तीसगढ़ में सुशासन को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में आयोजित 'सुशासन तिहार 2026' एक प्रभावी, संवेदनशील और जनोन्मुखी पहल के रूप में उभरकर सामने आया है। 01 मई से 10 जून तक चलने वाला यह विशेष अभियान केवल एक प्रशासनिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि सरकार की उस स्पष्ट मंशा का प्रतीक है, जिसमें शासन व्यवस्था को सरल, सुलभ और जवाबदेही बनाते हुए आम नागरिकों को केंद्र में रखा गया है। इस दौरान राज्य के गांव-गांव और शहरों के वार्ड-वार्ड तक प्रशासनिक अमला सक्रिय रूप से पहुंचकर लोगों की समस्याओं को सुन रहा है और मौके पर ही उनके समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे जनता और शासन के बीच वर्षों से बनी दूरी को कम करने में उल्लेखनीय सफलता मिल रही है। इस अभियान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है 'संवाद से संपूर्ण समाधान', जिसके तहत जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों द्वारा सीधे जनता से संवाद स्थापित किया जा रहा है। ग्राम पंचायतों और शहरी वार्डों में लगाए जा रहे जनसमस्या निवारण शिविरों में बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें और मांगें प्रस्तुत कर रहे हैं। इनमें भूमि संबंधी विवाद, नामांतरण, सीमांकन, जाति- निवास, आय प्रमाण पत्र, पेंशन, राशन कार्ड, बिजली-पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मुद्दे प्रमुख रूप से शामिल हैं। सुशासन तिहार के माध्यम से इन समस्याओं के त्वरित और समयबद्ध निराकरण पर विशेष जोर दिया जा रहा है, जिससे लोगों को दफ्तरों के चक्कर लगाने की मजबूरी से राहत मिल रही है और प्रशासन के प्रति विश्वास भी सुदृढ़ हो रहा



है। सुशासन तिहार 2026 केवल शिकायतों के समाधान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विकास को नई गति देने का भी सशक्त माध्यम बन रहा है। इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की जा रही है, अधूरे कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए जा रहे हैं और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार नई योजनाओं की रूपरेखा भी तैयार की जा रही है। इससे राज्य के दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास की रोशनी तेजी से पहुंच रही है और लोगों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। सरकार का यह प्रयास स्पष्ट करता है कि विकास केवल आंकड़ों तक सीमित न रहकर जमीनी स्तर पर भी दिखना चाहिए। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशा के अनुरूप इस अभियान में पारदर्शिता और जवाबदेही को विशेष महत्व दिया गया है। अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्राप्त शिकायतों का निराकरण तय समय सीमा के भीतर हो। इसके साथ ही, जनसुनवाई की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए तकनीकी माध्यमों का भी उपयोग किया जा रहा है, जिससे शिकायतों की निगरानी और समाधान की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। यह व्यवस्था प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक मजबूत कदम है, जो भविष्य में भी शासन प्रणाली को अधिक सुदृढ़ बनाएगा। इसके अतिरिक्त, सुशासन तिहार के दौरान विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि शासन की योजनाओं का लाभ वास्तव में पात्र हितग्राहियों तक पहुंचे। इसके लिए सुशासन तिहार के अवसर पर आयोजित शिविरों में योजनाओं से संबंधित जानकारी दी जा रही है, आवेदन लिए जा रहे हैं और पात्रता के आधार पर तत्काल स्वीकृति भी प्रदान की जा रही है। इससे न केवल योजनाओं की पहुंच बढ़ी है, बल्कि समाज के कमजोर और वंचित वर्गों का सशक्तिकरण भी हो रहा है। 'सुशासन तिहार 2026' छत्तीसगढ़ में सकारात्मक शासन व्यवस्था का एक सशक्त उदाहरण बनकर सामने आया है, जिसमें संवेदनशीलता, पारदर्शिता और तत्परता का समावेश दिखाई देता है। जब सरकार जनता के करीब जाकर उनकी समस्याओं को समझती है और समाधान के लिए प्रतिबद्ध होती है, तब वास्तविक अर्थों में सुशासन की स्थापना होती है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में यह अभियान राज्य को विकास, विश्वास और जनसंतोष के नए आयामों की ओर अग्रसर कर रहा है, जो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को एक आदर्श सुशासित राज्य के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

स्वदेशी मेला-2026 में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने किया स्वदेशी उत्पादों और झारखंड की समृद्ध संस्कृति को बढ़ावा देने का आह्वान

सरोज वार्ता/ब्यूरो





माननीय राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ऑड्रे हाउस परिसर, रांची में आयोजित तीन दिवसीय 'सांसद सांस्कृतिक महोत्सव-सह-स्वदेशी मेला-2026' के उद्घाटन समारोह में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए स्वदेशी उत्पादों के महत्व पर प्रकाश डाला। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे देश में अनेक विविधताएं हैं। देश के भीतर कई विभिन्न समाज एवं वर्ग के लोग रहते हैं जिनकी अलग-अलग खूबी और पहचान है। यही खूबी और पहचान देश का एक मजबूत स्तंभ भी है। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वदेशी का मतलब स्वयं उत्पादित वस्तुएं होती है। देश के भीतर उत्पादित वस्तुओं को अधिक से अधिक बढ़ावा मिले यह हम सभी की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार निरंतर इस दिशा में बेहतर कार्य कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी स्वदेशी को अपनाया तथा स्वदेशी अपनाने के प्रति देशवासियों को प्रेरित किया। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वदेशी मेला न केवल स्थानीय कारीगरों, हस्तशिल्पियों और उद्यमियों को एक सशक्त मंच प्रदान करता है बल्कि यह हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित एवं प्रोत्साहित करने का भी सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यहां की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के उद्देश्य निरंतर कार्य कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री ने इस आयोजन के लिए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं दी।

●स्वदेशी वस्तुओं को निरंतर प्रमोट कर रही राज्य सरकार

माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा आज सरकार द्वारा गांव तथा शहरों में कई कार्यक्रमों अथवा आयोजनों के माध्यम से स्वदेशी उत्पादों को प्रमोट किया जा रहा है। आज इस ऐतिहासिक ऑड्रे हाउस परिसर में आयोजित कार्यक्रम का उद्देश्य भी स्वदेशी वस्तुओं के साथ-साथ राज्य की कला-संस्कृति को बढ़ावा देना है। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड प्रदेश खनिज संपदाओं से पहचाना जाता है। ईश्वर ने इस राज्य में जमीन के अंदर के साथ-साथ जमीन के ऊपर भी काफी आकर्षक और खूबसूरत संपदाएं दी है। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वज स्वदेशी खान-पान के साथ जिस प्रकार जीवनयापन करना सिखा था वह काफी प्रभावित करने वाली चीजें हैं। उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं आज के वर्तमान दौर में मनुष्य कई ऐसी चीजों से प्रभावित हैं जिससे शरीर के आंतरिक तथा वाह्य वस्थाओं में भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

●झारखंड में प्रतिभा की कमी नही

माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि झारखंड के लोगों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। हमारे राज्य के युवा शिक्षा, संस्कृति तथा खेलकूद सहित विभिन्न क्षेत्रों में बहुत आगे हैं। हमारे बच्चे सीमित संसाधनों के बीच हर मंच पर राज्य का गौरव बढ़ा रहे हैं। इस राज्य की कला-संस्कृति की देश-दुनिया में अलग पहचान है। यहां के कलाकार कोई परिचय के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में इस राज्य के सरकारी स्कूलों में अध्यनरत बच्चे नेशनल लेवल पर आयोजित प्रतियोगिता-परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर अपने प्रतिभा को लोहा मनवा रहे हैं, यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है।

●प्रदशनी एवं स्टॉल का अवलोकन

इस अवसर पर माननीय राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने स्वदेशी मेले में लगे विभिन्न प्रदर्शनी एवं स्टॉल का अवलोकन किया तथा कारीगरों से बातचीत कर उनके कार्य की सराहना की। मेले में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से आए शिल्पकारों द्वारा लगाए गए स्टॉल आकर्षण का केंद्र रहे, जहां हस्तनिर्मित वस्त्र, आभूषण, घरेलू सजावटी सामग्री एवं मिट्टी तथा बांस इत्यादि से उत्पादित स्वदेशी वस्तुएं प्रदर्शित किए गए हैं। माननीय राज्यपाल एवं माननीय मुख्यमंत्री के आगमन पर लोक कलाकारों द्वारा पारंपरिक नृत्य एवं गीतों के साथ हार्दिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, सांसद राज्यसभा श्री आदित्य साहू, सांसद राज्यसभा श्री दीपक प्रकाश, विधायक श्री नवीन जायसवाल, महापौर रांची श्रीमती रोशनी खलखो, उप महापौर रांची श्री नीरज कुमार, पूर्व राज्यसभा सांसद श्री अजय मारू सहित अन्य गणमान्य, प्रबुद्धजन, विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लोक कलाकार सहित अन्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

बिजनेसमैन डा. संजीव जुनेजा को मिला 'एक्सीलेंस इन ब्रांड बिल्डिंग एंड कंज्यूमर ट्रस्ट' अवार्ड

डब्ल्यूपीओ अवॉर्ड्स 2026 में बिजनेस टाइकून संजीव जुनेजा को मिला प्रतिष्ठित सम्मान



सरोज वार्ता/ब्यूरो

वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गनाइजेशन द्वारा एक प्रतिष्ठित होटल में भव्य वैसाखी अवॉर्ड्स 2026 समारोह का आयोजन किया गया। जिसमें देश-विदेश की जानी-मानी हस्तियों की मौजूदगी के बीच उद्योगपति एवं एसबीएस बायोटेक के संस्थापक डा. संजीव जुनेजा को 'एक्सीलेंस इन ब्रांड बिल्डिंग एंड कंज्यूमर ट्रस्ट' अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें भारतीय उद्योग में उनके उत्कृष्ट योगदान, सशक्त ब्रांड निर्माण और उपभोक्ताओं के बीच अटूट विश्वास कायम करने के लिए प्रदान किया गया। यह भव्य समारोह डब्ल्यूपीओ के इंटर नेशनल प्रेसिडेंट एवं राज्य सभा सांसद डा. विक्रमजीत सिंह साहनी (पद्मश्री) के नेतृत्व में आयोजित किया गया। इसके अलावा कई गणमान्य अतिथि, वरिष्ठ उद्योगपति, सामाजिक कार्यकर्ता, कलाकार और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व भी इस अवसर पर शामिल हुए। समारोह के दौरान उद्योग, व्यापार, सिनेमा, खेल, मीडिया, फैशन, सामाजिक सेवा और वैश्विक व्यापार जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अनेक नामचीन लोगों को सम्मानित किया गया। यह आयोजन न केवल उपलब्धियों का सम्मान था, बल्कि पंजाबी संस्कृति, विरासत और वैश्विक पहचान का एक भव्य उत्सव भी रहा। इस अवसर पर डा. विक्रमजीत सिंह साहनी ने अपने संबोधन में कहा कि वैसाखी केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि यह हमारी पहचान, परंपरा, मेहनत और सामूहिक शक्ति का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि डब्ल्यूपीओ के माध्यम से दुनिया भर में बसे पंजाबी समुदाय को एक मंच पर लाकर उनकी उपलब्धियों को सम्मानित करना संगठन का प्रमुख उद्देश्य है। यह सम्मान उन व्यक्तित्वों को समर्पित है, जो अपने कार्यों से समाज में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं और भारत की छवि को वैश्विक स्तर पर मजबूत कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि डा. संजीव जुनेजा को मिला यह सम्मान उनके वर्षों के समर्पण, नवाचार और उपभोक्ता-केंद्रित सोच और आयुर्वेद को बढ़ावा देने का परिणाम है। उन्होंने अपने व्यवसाय के माध्यम से न केवल एक मजबूत ब्रांड स्थापित किया, बल्कि लाखों उपभोक्ताओं का विश्वास भी जीता है। उनके नेतृत्व में एसबीएस बायोटेक ने स्वास्थ्य और वेलनेस के क्षेत्र में उल्लेखनीय पहचान बनाई है। वहीं डा. संजीव जुनेजा ने डब्ल्यूपीओ व आयोजकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सम्मान उनके लिए गर्व का विषय है और यह उन्हें आगे भी बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं का विश्वास ही किसी भी ब्रांड की सबसे बड़ी पूंजी होता है, और वह हमेशा इस विश्वास को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। कार्यक्रम ने फिर साबित किया कि पंजाबी समुदाय न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी मजबूत पहचान और प्रभाव बनाए हुए है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ, दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा, डीएसजीएमसी के अध्यक्ष सरदार हरमीत सिंह कालका भी इस पुरस्कार समारोह में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पंजाब के राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया और दिल्ली के उपराज्यपाल श्री तरणजीत सिंह संधू मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

सीएम बोले: शिक्षक या शिक्षामित्र नकारात्मक सोच रखेंगे, तो बच्चों की नींव कमजोर करेंगे और इससे समाज व राष्ट्र की क्षति होगी



सरोज वार्ता/ब्यूरो

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2017 से पहले की सरकारों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने बिना नियम-कानून के शिक्षामित्रों को सहायक शिक्षक के रूप में मान्यता देने का कुत्सित प्रयास किया, जो पूरी तरह नियम-विरुद्ध था। उनकी इस गलती के कारण सुप्रीम कोर्ट ने सभी शिक्षामित्रों की सेवाएं समाप्त करने का आदेश दिया। ऐसे में हमारे सामने बड़ी चुनौती थी। डेढ़ लाख परिवार सड़कों पर भूखों मरने की नौबत पर आ सकते थे। ये लोग 18-19 वर्षों से सेवाएं दे रहे थे। उम्र के इस पड़ाव में वे कहां जाते? तब हमने मंत्रिमंडल में फैसला किया कि इनकी सेवाएं समाप्त नहीं करेंगे, बल्कि इनका सहयोग लेंगे। 2017 में ही सरकार ने शिक्षामित्रों का मानदेय 3,500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया था। अब इसे और बढ़ाते हुए 18 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है, जो अप्रैल महीने से लागू भी हो गया है। सीएम योगी मंगलवार को गोरखपुर में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राज्यस्तरीय शिक्षामित्र सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने आह्वान किया कि अब ट्रेड यूनियन वाली सोच और नकारात्मक वृत्ति को पूरी तरह त्याग देना होगा। उन्होंने कहा कि शिक्षक या शिक्षामित्र केवल

- पिछली सरकारों ने बिना नियम-कानून के सहायक शिक्षक के रूप में मान्यता देने का कुत्सित प्रयास किया, जो पूरी तरह नियम-विरुद्ध था: मुख्यमंत्री
- 2017 में सरकार ने शिक्षामित्रों का मानदेय 3,500 से बढ़ाकर 10 हजार किया और अब इसे 18 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया है: मुख्यमंत्री

मांगों पर अड़े रहेंगे, नकारात्मक सोच रखेंगे, तो न केवल बच्चों की नींव कमजोर करेंगे बल्कि पूरे समाज व राष्ट्र को क्षति पहुंचाएंगे। हमारा नेचर ट्रेड यूनियन जैसा नहीं हो सकता। पहले देश, फिर हम। सकारात्मक भाव के साथ कार्य करने वाले ही अच्छी पीढ़ी तैयार कर सकते हैं। सरकार सकारात्मक सोच के साथ आपके साथ है, इसलिए नकारात्मक भाव बिल्कुल नहीं आने चाहिए। वर्षों से चली आ रही आपकी मांग को सरकार ने संवाद व सहयोग के माध्यम से हल किया, न कि टकराव के रास्ते से। मुख्यमंत्री ने बताया कि आज सुबह जनता दर्शन कार्यक्रम में एक शिक्षामित्र परिवार आया था, जिसकी बेटी गंभीर रूप से बीमार है, डायलिसिस की जरूरत है। इसीलिए मैंने शिक्षामित्रों को भी प्रधानमंत्री की कैशलेस स्वास्थ्य सुरक्षा देने का निर्णय किया था। 5 लाख रुपये का सालाना कैशलेस स्वास्थ्य कवर सभी शिक्षामित्रों को उपलब्ध कराया जाएगा। जो छूट गए होंगे, उन्हें भी यह सुविधा दी जाएगी। बेसिक शिक्षा परिषद को तत्काल सभी जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। शीघ्र ही एक भव्य समारोह आयोजित कर सभी को यह कार्ड प्रदान किया जाएगा।

- **बैंकिंग और सामाजिक सुरक्षा:** मुख्यमंत्री ने कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद को तत्काल सभी शिक्षामित्रों के बैंक खाते खुलवाने का निर्देश दिया गया है। इससे मानदेय सीधा एकाउंट में आएगा। सरकार ने शिक्षामित्रों को उनके जिले व नजदीकी विद्यालय में तैनाती देने की व्यवस्था की है। खासकर विवाहित महिला शिक्षामित्रों को मायके या ससुराल के निकट विद्यालय में म्यूचुअल ट्रांसफर की सुविधा दी जाएगी।
- **शिक्षा क्रांति का जिक्र:** मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाया गया है और यह परिवर्तन साफ दिख रहा है। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत विद्यालयों की हालत बदली

गई है। पहले जहां टॉयलेट, पेयजल, फ्लोरिंग, फर्नीचर और स्मार्ट क्लास की उपलब्धता मात्र 30-36% थी, वह अब 96-99% हो गई है। ड्रॉपआउट दर 19% से घटकर 3% पर आ गई है। एक बच्चे का स्कूल छोड़ना राष्ट्रीय क्षति है। पहले बालिकाएं इसलिए स्कूल नहीं जाती थीं क्योंकि वहां पेयजल, अलग टॉयलेट और सुरक्षा नहीं थी। आज 1 करोड़ 60 लाख बच्चों को दो यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, जूते, मोजे और स्वेटर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। निपुण भारत, पीएम श्री, कस्तूरबा गांधी विद्यालय आदि योजनाओं का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि कस्तूरबा गांधी विद्यालयों को 12वीं तक बढ़ाया गया है और नए विकास खंडों में आवासीय स्कूल खोले जा रहे हैं। पीएम श्री, अटल टिंकरिंग लैब, सीएम कंपोजिट और अटल आवासीय विद्यालय मॉडल बन रहे हैं। मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हुए बताया कि 2017 से पहले बच्चे एक लाइन भी नहीं पढ़ पाते थे, आज दूसरी कक्षा की बच्चियां पूरा पेज पढ़ रही हैं। एक दृष्टिबाधित बच्ची ब्रेल में पढ़कर फ्लुएंट बोल रही थी। यह होता है विकास। एक और घटना का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि एक 3 साल के बच्चे ने अपने मुंडन पर कहा कि मैंने आपके जैसा दिखने के लिए बाल बनवाए हैं, उसकी यह बात उन्हें गहराई से छू गई।

● **शिक्षामित्रों से अपील, हर बच्चा पहुंचे स्कूल:** मुख्यमंत्री ने शिक्षामित्रों का आह्वान किया कि जुलाई के पहले सप्ताह में स्कूल खुलते ही 'स्कूल चलो' अभियान तेज करें। हर बच्चा स्कूल पहुंचना चाहिए। शिक्षक आधा घंटा पहले स्कूल पहुंचें, 25-25 घरों में जाकर अभिभावकों से बात करें। बच्चों को प्यार से पढ़ाएं, कभी मारपीट न करें। अच्छी कहानियां, कविताएं और उदाहरण देकर उन्हें प्रेरित कीजिए। अभिभावकों को भी जागरूक करें कि दी गई यूनिफॉर्म, स्वेटर आदि का सही उपयोग हो। परिवार की खींचतान स्कूल तक नहीं लाइए।

● **मुख्यमंत्री ने शिक्षा मित्रों का किया सम्मान:** मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 1,43,000 शिक्षामित्रों को बधाई दी और कहा कि आप लगन, ईमानदारी और सकारात्मकता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। शिक्षित समाज ही सशक्त राष्ट्र बनाएगा। यहीं से विकसित व आत्मनिर्भर भारत की नींव पड़ेगी। मुख्यमंत्री ने समारोह में चयनित शिक्षामित्रों को अपने कर-कमलों से सम्मानित किया और उन्हें बढ़े मानदेय का चेक भी प्रदान किया। इनमें संगीता (गोरखपुर), प्रतिमा गुप्ता (गोरखपुर), फारिया तबस्सुम (गोरखपुर), तेजभान सिंह (कासगंज), धीरेंद्र कुमार शर्मा (फिरोजाबाद), संजय (महाराजगंज), शशि प्रभा सिंह (महाराजगंज), अभय कुमार (देवरिया), सुमन लता देवी (देवरिया), सर्वेश कुमार पांडे (कुशीनगर), अनुराधा (कुशीनगर), लालता प्रसाद (बस्ती), सोनू यादव (संत कबीर नगर) और मीरा (गोरखपुर) शामिल रहे।

● **अरुणोदय कैलेंडर का किया विमोचन :** मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थी नेतृत्व आधारित प्रार्थना सभा गतिविधि कैलेंडर 'अरुणोदय' का विमोचन किया। इस कैलेंडर का उद्देश्य प्रार्थना सभा को परंपरागत गतिविधि से ऊपर उठाकर विद्यार्थियों के समग्र विकास का माध्यम बनाना है। इसमें पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ विज्ञान, गणित, भाषीय कौशल, परस्पर संवाद, विचार अभिव्यक्ति, रोल प्ले, एक्शन गीत तथा कला-क्राफ्ट जैसी गतिविधियों को शामिल किया गया है, ताकि बच्चे प्रार्थना सभा के दौरान ही सीख सकें और नेतृत्व गुणों का विकास कर सकें। इस कैलेंडर का विमोचन कर मुख्यमंत्री ने प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को एक बेहतरीन मार्गदर्शक उपलब्ध कराया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कई बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार भी कराया और महिलाओं को उपहार प्रदान किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बेसिक शिक्षा से संबंधित प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। उन्होंने बच्चों द्वारा बनाए गए नवाचारी मॉडल्स को देखा और उनकी सराहना की। उन्होंने नन्हे बच्चों पर स्नेह बरसाया और उनसे संवाद भी किया। इस अवसर पर बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री संदीप सिंह, गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ला, जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह, गोरखपुर के महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव, विधान परिषद सदस्य डॉ. धर्मेंद्र सिंह, विधायकगण विपिन सिंह, महेंद्र पाल सिंह, प्रदीप शुक्ला, राजेश त्रिपाठी, विमलेश पासवान, श्रवण निषाद, उपाध्यक्ष राज्य महिला आयोग चारु चौधरी, क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय, जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी, राजेश गुप्ता, अपर मुख्य सचिव शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा, महानिदेशक मोनिका रानी व अन्य लोग उपस्थित रहे।



टू ब्रदर्स ऑर्गेनिक फार्म्स खपली आटे के साथ रोज़ाना की रोटियों में उच्च प्रोटीन का पोषण लेकर आया है

सरोज वार्ता/ब्यूरो



कम ग्लूटेन वाले खपली गेहूं से बनी यह रोटी चार रोटियों में लगभग 22 ग्राम प्रोटीन प्रदान करती है और पाचन क्रिया को बेहतर बनाती है। ऐसे समय में जब भारतीय आहार में प्रोटीन की मात्रा सभी आयु वर्ग में लगातार कम होती जा रही है, टू ब्रदर्स ऑर्गेनिक फार्म्स ने खपली प्रोटीन आटा पेश किया है , जो उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन को सबसे अधिक खाए जाने वाले भोजन प्रारूपः रोजमर्रा की रोटी में शामिल करता है। बढ़ते बच्चों और सेहत के प्रति जागरूक व्यक्तियों से लेकर कामकाजी पेशेवरों और बुजुर्गों तक, सभी के लिए प्रोटीन संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। फिर भी, कई भारतीय परिवारों में दैनिक प्रोटीन का सेवन या तो अपर्याप्त होता है या प्रसंस्कृत सप्लीमेंट्स और विकल्पों पर निर्भर करता है। इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी-एरिड ट्रॉपिक्स (आईसीआरआईएसएटी), इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट (आईएफपीआरआई) और सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल स्टडीज (सीईएसईएस) जैसे संगठनों द्वारा किए गए शोध से पता चलता है कि भारत के अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में अधिकांश परिवार अनुशंसित मात्रा से कम प्रोटीन का सेवन करते हैं। इस कमी को दूर करते हुए, खपली प्रोटीन आटा सिर्फ चार रोटियों में लगभग 22 ग्राम प्रोटीन प्रदान करता है , जो 70 किलोग्राम वजन वाले एक औसत वयस्क की दैनिक प्रोटीन आवश्यकता का लगभग 40% पूरा करता है। मुख्य भोजन में बेहतर पोषण को एकीकृत करके, यह उत्पाद परिवारों को अपनी खान-पान की आदतों को बदले बिना प्रोटीन का सेवन बढ़ाने में सक्षम बनाता है। यह आटा खपली गेहूं (एम्मर) से बनाया जाता है, जो अपने पौष्टिक गुणों और आसानी से पचने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध एक प्राचीन अनाज है। इस आटे में 72% एम्मर गेहूं और 28% अन्य अनाज व सोया प्रोटीन शामिल हैं, जो पारंपरिक और कार्यात्मक पोषण का संतुलित मिश्रण तैयार करते हैं। इस आटे में एमर गेहूं, सोया आटा, चना दाल, सोया प्रोटीन आइसोलेट और रागी शामिल हैं। प्राकृतिक रूप से कम ग्लूटेन (पारंपरिक गेहूं की तुलना में 50% तक कम) और उच्च फाइबर वाला यह आटा आसानी से पच जाता है और लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करता है। यह तीन फायदे देता है - उच्च प्रोटीन, कम ग्लूटेन और उच्च फाइबर। लॉन्च पर टिप्पणी करते हुए, टू ब्रदर्स ऑर्गेनिक फार्म्स के सह-संस्थापक और किसान सत्यजीत हांगे ने कहा, 'आजकल हम देख रहे हैं कि प्रोटीन को हर चीज में मिलाया जा रहा है, अक्सर अत्यधिक प्रसंस्कृत सामग्रियों के माध्यम से। हमारा ध्यान रोजमर्रा के भोजन को बेहतर बनाने पर था। रोटी भारतीय घरों में एक अभिन्न अंग है, और इसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री को बेहतर बनाकर, हम लोगों को अपनी आदतों को बदले बिना प्रोटीन का सेवन बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। ' सह-संस्थापक और किसान अजिंक्या हांगे ने कहा, 'खपली हमेशा से हमारी कृषि पद्धति का अभिन्न अंग रहा है, क्योंकि यह बहुत टिकाऊ और पौष्टिक होता है। इस उत्पाद के साथ, हमने स्वदेशी अनाजों के लाभों को आज की प्रोटीन आवश्यकताओं के व्यावहारिक दृष्टिकोण के साथ जोड़ा है, जिससे एक ऐसा उत्पाद तैयार हुआ है जो हमारी जड़ों से जुड़ा हुआ है और प्रासंगिक भी है। ' यह लॉन्च टू ब्रदर्स ऑर्गेनिक फार्म्स के उस दृष्टिकोण को दर्शाता है जिसके तहत वे ऐसे रोजमर्रा के खाद्य पदार्थ बनाते हैं जो पारंपरिक अनाजों पर आधारित होने के साथ-साथ आधुनिक पोषण संबंधी जरूरतों के अनुरूप भी हों। खपली जैसी स्वदेशी सामग्रियों को कार्यात्मक पोषण संबंधी दृष्टिकोण के साथ मिलाकर, ब्रांड ऐसे उत्पाद बनाना जारी रखता है जो भारतीय आहार में सहजता से समाहित हो जाते हैं। खपली प्रोटीन आटा 1 किलो के लिए 265 रुपये में उपलब्ध होगा और इसे शुरुआत में ब्रांड की घरेलू वेबसाइट के माध्यम से खरीदा जा सकता है । यह उत्पाद आगामी महीने में अमेज़न पर त्वरित वाणिज्य के माध्यम से उपलब्ध होगा। साथ ही, यह जल्द ही चुनिंदा ऑफलाइन और प्रीमियम रिटेल स्टोर्स पर भी उपलब्ध होगा। इस नए उत्पाद के जुड़ने से, टू ब्रदर्स ऑर्गेनिक फार्म्स अपने रोजमर्रा के आवश्यक उत्पादों की श्रृंखला को और मजबूत करता है, साथ ही किसानों को प्राथमिकता देने वाले अपने सचेत दृष्टिकोण के प्रति भी प्रतिबद्ध रहता है। खपली प्रोटीन आटा के बारे में अधिक जानने या इसे खरीदने के लिए, टू ब्रदर्स ऑर्गेनिक फार्म्स की वेबसाइट पर जाएं या इसे यहां खोजें। अमेज़न।

टू ब्रदर्स ऑर्गेनिक फार्म्स के बारे में

टू ब्रदर्स ऑर्गेनिक फार्म्स भारत की एक किसान-स्वामित्व वाली, मिट्टी-केंद्रित पुनर्योजी खाद्य कंपनी है जिसकी स्थापना 2014 में हुई थी। वे पुनर्योजी प्राकृतिक खेती के सिद्धांतों का पालन करते हुए, बिना किसी शॉर्टकट के असली भोजन उगाते और तैयार करते हैं। दो भाइयों द्वारा स्थापित, जिन्होंने कॉर्पोरेट करियर छोड़कर अपने पैतृक गांव में वापसी की, टू ब्रदर्स हमारे खाद्य प्रणाली में सच्चाई को वापस लाने का एक आंदोलन है - जहां भोजन पोषक तत्वों से भरपूर, रसायन-मुक्त और अपनी जड़ों तक पता लगाने योग्य होता है।

आरईसी लिमिटेड ने बिहार के शंकर आई हॉस्पिटल को 11.55 करोड़ की सीएसआर सहायता प्रदान की





सरोज वार्ता/ब्यूरो

आरईसी लिमिटेड, विद्युत मंत्रालय के तहत 'महारत्न सीपीएसई' कंपनी, ने बिहार के सहरसा में 'शंकर आई हॉस्पिटल' के उद्घाटन के साथ स्वास्थ्य सेवा की पहुँच के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। अपनी प्रमुख पहल 'बिहार के लिए एक नई सोच' के तहत ?11.55 करोड़ के सीएसआर अनुदान से वित्तपोषित, इस अस्पताल को एक भव्य समारोह में आम जनता के लिए खोल दिया गया है। अस्पताल का उद्घाटन माननीय केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने, आरईसी लिमिटेड के निदेशक (परियोजनाएं) श्री टीएससी बोश और अन्य वरिष्ठ सरकारी गणमान्य व्यक्तियों के साथ मिलकर किया।

दृष्टि बहाली के लिए एक रूपरेखा

यह नई सुविधा उत्तरी बिहार के नेत्र चिकित्सा क्षेत्र को पूरी तरह से बदल देने के लिए तैयार है। अगले पाँच वर्षों के दौरान, इस परियोजना को इस प्रकार संरचित किया गया है कि यह निम्नलिखित परिणाम प्रदान करेः

- 1.5 लाख आउटपेशेंट परामर्शः व्यापक स्क्रीनिंग और विशेष नेत्र देखभाल प्रदान करना।
- 40,000 मोतियाबिंद सर्जरीः उन्नत सर्जिकल हस्तक्षेप के माध्यम से रोकी जा सकने वाली अंधता के उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित।
- समावेशी स्वास्थ्य सेवाः वंचित और आर्थिक रूप से हाशिए पर पड़े समुदायों को निःशुल्क और रियायती सेवाएं प्रदान करने का एक समर्पित अधिदेश।

11.55 करोड़ के सीएसआर अनुदान का उपयोग।

आरईसी लिमिटेड के वित्तीय सहयोग ने अस्पताल को आधुनिक चिकित्सा बुनियादी ढांचे से सुसज्जित किया है, जिसमें शामिल हैंः

- उन्नत नेत्र-विज्ञान तकनीकः अत्याधुनिक नैदानिक और शल्य-चिकित्सा उपकरण।
- ग्रामीण आउटरीच बेड़ाः दूर-दराज के गाँवों में आँखों की जाँच के शिविर आयोजित करने के लिए विशेष वाहन।
- परिचालन संबंधी बुनियादी ढांचाः पूरी तरह से सुसज्जित रोगी वार्ड और संक्रमण-मुक्त ऑपरेशन थिएटर।

आखिर कैसे आए ये चुनाव परिणाम



अवधेश कुमार

पांच राज्यों के चुनाव परिणामों पर कोई एक सुसंबद्ध टिप्पणी संपूर्ण स्थितियों का विश्लेषण नहीं कर सकता। किंतु सबको मिलाकर एक तस्वीर बनाएं तो इसमें दो ऐतिहासिक युगांतरकारी परिणतियां हैं। एक , पश्चिम बंगाल में भाजपा की ऐसी विजय जो एक समय अकल्पनीय थी तथा तमिलनाडु में थलापति विजय की पार्टी टीवीके का चमत्कारिक प्रदर्शन। वैसे तो असम में भी भाजपा की तीसरी बार लगातार विजय महत्वपूर्ण है पर ये दोनों घटनाएं ऐतिहासिक और युगांतरकारी हैं। बंगाल में एक तिहाई मुस्लिम मतदाताओं के बहुमत का हर हाल में भाजपा को सत्ता में आने से रोकने और तृणमूल के समर्थन में आक्रामकता से काम करने के बावजूद भाजपा की इतनी बढ़त सामान्य घटना नहीं है। आम सोच यही थी कि ममता की शुरुआत ही 30 प्रतिशत मत और लगभग 65-70 सीटों से होती है जबकि भाजपा को शून्य से शुरुआत करनी होगी। वैसे असम में इससे ज्यादा मुस्लिम आबादी के बावजूद भाजपा ने जीत हासिल कर कई मिथकों को तोड़ा। पर असम और बंगाल की राजनीति और सत्ता के चरित्र में मौलिक अंतर है। ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस ने लोकतांत्रिक व्यवस्था में पूरी राजनीति और सत्ता का चरित्र ऐसा बना दिया था जिसमें किसी भी पार्टी के लिए उसको भेदना असंभव सी चुनौती थी। पिछले एक दशक से ज्यादा समय के चुनावों का एक पहलू हर जगह लागू होता है वह यह कि हिंदुत्व व अपनी संस्कृति?, धर्म के प्रति हिंदुओं के पुनर्जागरण के कारण एक निश्चित वोट का आधार हर राज्य में निर्मित हो गया है और यह मत भाजपा से संतुष्ट असंतुष्ट या कुछ मायनो में नाराज होने के बावजूद वह हारे या जीते उसे या साथी दलों या उसकी अनुपस्थिति में दूसरे दलों को जाता है। यह प्रवृत्ति पांचो राज्यों में रही है। भाजपा स्थानीय -क्षेत्रीय मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हुए भी चुनावों को मतदाताओं को सीधे अपील करने वाले राष्ट्रीय विषयों के साथ संबद्ध करती है। भाजपा ने राष्ट्रीय सुरक्षा और जनसांख्यिकी को बंगाल एवं असम दोनों जगह प्रमुख मुद्दे के रुप स्थापित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान संबंधी कार्यों तथा नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिला आरक्षण को लागू करने की संसदीय पहल ने भी चुनावी माहौल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बंगाल के परिणाम ने केवल उन्हें चौंकाया है जो जमीनी वास्तविकता और 2018 से मतदाताओं मुख्यतः हिन्दुओं के बड़े वर्ग के अंदर बदलाव की छटपटाहट को महसूस नहीं कर रहे थे। तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी के नेतृत्व में सत्ता और पूरी राजनीति को निहित स्वार्थी तत्वों की गिरफ्त में दिए जाने से बंगाल की संस्कृति चुनावों को हर हाल में अपने पक्ष में करने की हो चुकी है। कट्टरपंथी तत्वों को प्रत्यक्ष- परोक्ष संरक्षण और प्रोत्साहन के कारण पूरा प्रदेश हमेशा सांप्रदायिक भय और तनाव की स्थिति में रहा। मतदाताओं की इच्छा नहीं तृणमूल नेताओं की चाहत से आप मतदान करिए या चुपचाप घर बैठिये अन्यथा हिंसा, आगजनी, दमन, उत्पीड़न और संबंधित स्थान या प्रदेश से पलायन का दंश झेलिये। साइलेंट रीगिंग बंगाल की मुख्य चुनावी प्रवृत्ति रह रही है। पहले इसी रास्ते वाम मोर्चा ने लगातार जीत सुनिश्चित किया और उसके विरुद्ध लंबा संघर्ष करते-करते ममता बनर्जी ने भी अपनी पूरी पार्टी को उससे ज्यादा हिंसक और दमनकारी तत्वों में परिणत कर दिया। पलायन या हिंसा की सर्वाधिक शिकार महिलाएं होतीं हैं। पुरुषों के मुकाबले 1.5 महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया महिला होने के बावजूद ममता बनर्जी के विरुद्ध इनका बहुत बड़ा मत भाजपा को गया है। भाजपा पर ध्रुवीकरण का आरोप लगाकर सतही विश्लेषण करने वाले विचार करें कि भद्र लोक माने जाने वाले बंगाल के हिंदुओं ने ममता बनर्जी की सत्ता संस्कृति के विरुद्ध विद्रोह कर भाजपा को मत दिया तो क्या इसे केवल ध्रुवीकरण कहेंगे और ऐसा हुआ भी तो क्यों? बंगाल में राजनीतिक संघर्ष वास्तविक लोकतंत्र की पुनर्स्थापना तथा सत्ता संस्कृति को सर्वसमावेशी बनाने का था। यह जिम्मेवारी मुख्यतः प्रदेश के गैर मुस्लिमो यानी हिंदुओं को ही लेना था। हिंदुओं के अंदर अगर यह भाव पैदा हुआ कि इस सरकार के रहते हमारा अस्तित्व संकट में है तो इसके कारण अत्यंत गहरे हैं। बांग्लादेश की घटनाओं ने इस मनोविज्ञान को सशक्त किया कि हमें कुछ हद तक जान की बाजी लगानी होगी। हिंदू आबादी में लगभग 75 प्रतिशत ने भाजपा के पक्ष में वोट दिया है। यह बहुत बड़ी बात है। एसआईआर में 90 लाख से ज्यादा मृत, संदिग्ध और स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने के कारण फर्जी मतदाताओं का खेल खत्म हो गया। सवा 2 लाख केंद्रीय बलों की उपस्थिति , चुनाव के बाद भी सुरक्षा बलों के बने रहने की घोषणा, दूसरे राज्यों

के अधिकारियों को चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्ति, प्रदेश के अधिकारियों का व्यापक पैमाने पर स्थानांतरण या चुनाव प्रक्रिया तक कार्य मुक्ति तथा चुनावी हिंसा वाले चिन्हित व्यक्तित्वों के विरुद्ध कार्रवाई व सतर्क दृष्टि आदि ने भय व संशयग्रस्त मतदाताओं के अंदर सुरक्षा को लेकर आश्वस्त किया जिससे चुनावी वातावरण में आमूल परिवर्तन आया। भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में पहले दिन से यह विश्वास दिलाने की रणनीति अपनाई कि हम सत्ता में आ रहे हैं तथा किसी के साथ अन्याय हुआ तो पूरी पार्टी खड़ी रहेगी। इन सबका सम्मिलित परिणाम है असंभव सा लगने वाला सत्ता परिवर्तन। असम में पहले दिन से स्पष्ट था कि वह भाजपा को बड़ी चुनौती नहीं है। किंतु गौरव गोगोई भी जोरहाट से हार जाएंगे इसकी कल्पना कांग्रेस को नहीं रही होगी। राहुल गांधी एवं प्रियंका वाड्रा व उनके रणनीतिकारों के कारण टिकट बंटवारे तक नेता पार्टी छोड़कर जाते रहे। भाजपा ने पिछले लंबे समय से असम अस्मिता व आसामी संस्कृति को भारत के व्यापक हिंदुत्व संस्कृति और राष्ट्रभाव से जोड़ने में सफलता पाई है। मुगलों से युद्ध करने वाले लचित बरफ़ुकन से लेकर महाराज शंकर देव को जिस तरह भाजपा ने प्रस्तुत किया एवं जनजाति गौरव को निचले स्तर तक ले गए उन सबसे सामाजिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण हुआ है। सरकार की आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा नीति ने उसे बल दिया है। हिमंता विस्वासरमा की छवि देश में भले घुसपैठी और मुस्लिम विरोधी बनाई गई किंतु इसके साथ असम में उन्होंने बच्चों व युवाओं के मामा और महिलाओं के भाई के रूप में भी छवि बनई है। असम में घुसपैठ लंबे समय से मुद्दा रहा है और इसके आधार पर वहां 80 के दशक में छात्र नेताओं की सरकार बनी। बाकी पार्टियों ने इसका उपहास उड़ाया और भाजपा आज भी इस पर कायम है। इन सबका असर हुआ है और भाजपा तीसरी बार सत्ता बनाए रखने में कामयाब रही। तमिलनाडु में थलापति विजय की टीवीके या तमिलगा वेत्री कझगम दोनों मुख्य गठबंधन द्रमुक नेतृत्व आईएनडीआईए तथा अन्नाद्रमुक भाजपा गठबंधन को पछाड़ नंबर एक की पार्टी बन जाएगी इसकी कल्पना किसी को नहीं थी। दरअसल, द्रमुक के विरुद्ध सत्ता विरोधी रुझान जमीन पर दिख रहा था। इसी कारण एमके स्टालिन ने एक तिहाई विधायकों का टिकट काटा। उन्होंने तमिलवाद और तमिल भाषा को लेकर आक्रामक राजनीति की। पूरी पार्टी और कांग्रेस को छोड़कर गठबंधन सनातन और हिंदुत्व के विरुद्ध जहर उगलने लगी। विधानसभा में अलग से तमिल राष्ट्रगान तक की परंपरा शुरू कर दी। आम लोगों को इस तरह का अतिवाद स्वीकार नहीं था और द्रमुक को इसका आभास हुआ। चुनाव आते-आते सनातन विरोधी वक्तव्य बंद हो गए और उदयनिधि स्टालिन जो एक समय सनातन के समूल नाश की बत करते थे मंदिर -मंदिर घूमने लगे। अन्नाद्रमुक और भाजपा गठबंधन सत्ता विरोधी जन असंतोष और लोगों की आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करने में सफल नहीं रहे और इसका लाभ विजय को मिला। वैसे भी भाजपा वहां केवल 27 सीटों पर लड़ रही थी। विजय फिल्मी कैरियर छोड़कर तमिलनाडु की राजनीति बदलने की घोषणा के साथ आए और 2024 में पार्टी बनाने के बाद लगातार सक्रिय रहे। यद्यपि उन्होंने दोनों पक्षों का मत काटा किंतु द्रमुक को ज्यादा क्षति पहुंचाई। ईसाइयों के मत का भी बड़ा हिस्सा उनके खाते आया और मुस्लिम मतों का भी। यहां से तमिलनाडु की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत हो रही है और एमजी रामचंद्रन के बाद विजय दूसरे बड़े फिल्म स्टार होंगे जिनके राजनीति में लंबे समय तक रहने की संभावना है। इसे नास्तिकतावाद और आक्रामक तमिलवाद की आंशिक पराजय के रूप में देखा जाना चाहिए। केरल में भाजपा ने खूब काम किया, जमीनी मुद्दे उठाए, धार्मिक प्रवृत्ति को देखते हुए लोगों की इच्छा को वाणी भी दी। इन सबके परिणामस्वरूप उसके जनाधार में उछाल आया, 2024 में त्रिशूर लोकसभा सीट पर जीत तथा तिरुवनंतपुरम के नगर निगम पर आधिपत्य इसका प्रमाण है। कुछ वर्ष पहले तक इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। किंतु अभी प्रदेश में व्यापक जनाधार और चुनावी सफलता की दृष्टि से यह कम है। लगातार 10 वर्ष सत्ता में होने के कारण वाम मोर्चा के विरुद्ध व्यापक असंतोष था और उनके सामने विकल्प के रूप में कांग्रेस नेतृत्व वाला यूडीएफ था। तो कुल मिलाकर इन परिणामों का भी निष्कर्ष यही है कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य 2024 के लोकसभा चुनाव के समय से काफी बदल चुका है। भारत के लोगों के लिए भाजपा अभी भी व्यक्तिगत - आंतरिक व राष्ट्रीय सुरक्षा, हिंदुत्व अभिप्रेरित व्यापक राष्ट्रवाद तथा, क्षेत्रीय अस्मिता को सकारात्मक महत्व देने वाली, आर्थिक विकास के प्रति प्रतिबद्ध, विरासत के संरक्षण तथा सामाजिक न्याय व लैंगिक समानता को सही परिपेक्ष में जमीन पर उतरने वाली पार्टी के रूप में मुख्य विकल्प बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्वमें 2014 लोकसभा चुनाव परिणाम से यह मीठा टूटा था कि बगैर मुस्लिम मत के केंद्र के में किसी पार्टी को अकेले बहुमत नहीं मिल सकता। बंगाल के चुनाव परिणाम में इस मिथक को अंतिम बार ध्वस्त करदिया।



सरोजिनी नगर स्थित प्रतिष्ठित 'भारत बिजनेस पार्क (बीबीपी)' की ऐतिहासिक ई-नीलामी

नई दिल्ली में पहली बार में 5,779 करोड़ रुपये का बिक्री मूल्य प्राप्त हुआ



- एनबीसीसी द्वारा आयोजित एक ही ई-नीलामी में अब तक का सबसे अधिक बिक्री मूल्य 5779.44 करोड़ रुपये दर्ज किया गया।
- ई-नीलामी के परिणामस्वरूप 8 टावरों में से 5 टावर बिक गए।
- 23.44 लाख वर्ग फुट में से लगभग 14 लाख वर्ग फुट का सुपर बिल्ट-अप एरिया बेचा गया।



सरोज वार्ता/ब्यूरो

एनबीसीसी ने नई दिल्ली के सरोजिनी नगर स्थित भारत बिजनेस पार्क (बीबीपी) में फ्रीहोल्ड आधार पर व्यावसायिक निर्मित स्थान की ई-नीलामी सफलतापूर्वक संपन्न कर ली है। इस ई-नीलामी में 8 टावरों में लगभग 23.44 लाख वर्ग फुट का सुपर बिल्ट-अप क्षेत्र पेश किया गया था और अंतरराष्ट्रीय/घरेलू बहुराष्ट्रीय कंपनियों, कॉरपोरेट और संस्थागत खरीदारों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। नीलामी के परिणामस्वरूप, 5 टावरों में नीलाम किए गए लगभग 14 लाख वर्ग फुट के सुपर बिल्ट-अप क्षेत्र के लिए उच्चतम बोली दरों के आधार पर कुल बिक्री मूल्य लगभग 5779 करोड़ रुपये रहा। यह एनबीसीसी द्वारा एक ही ई-नीलामी में दर्ज किया गया अब तक का सबसे अधिक बिक्री मूल्य है। मजबूत भागीदारी और प्रतिस्पर्धी बोली के परिणामस्वरूप कई टावरों और मंजिलों में इन्वेंट्री पूरी तरह बिक गई, जिससे दक्षिण दिल्ली में एक प्रीमियम वाणिज्यिक गंतव्य के रूप में परियोजना के आकर्षण की पुष्टि हुई। एनबीसीसी इस परियोजना में अटूट विश्वास जताने और ई-नीलामी को एक बड़ी सफलता बनाने में योगदान देने के लिए सभी निवेशकों, निगमों और हितधारकों को हार्दिक धन्यवाद देता है। सफल बोलीदाताओं में अंतर्राष्ट्रीय/घरेलू

बहुराष्ट्रीय कंपनियां, कॉर्पोरेट और संस्थागत खरीदार शामिल थे, जिनमें कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी थे। ई-नीलामी में औसत बिक्री दर 41,207 रुपये प्रति वर्ग फुट दर्ज की गई, जो आरक्षित मूल्य से 2,107 रुपये प्रति वर्ग फुट (5%) अधिक है। दक्षिण दिल्ली के मध्य में स्थित भारत बिजनेस पार्क (बीबीपी) एक प्रमुख व्यावसायिक संपत्ति है, जो एक अनूठा व्यापारिक अवसर प्रदान करती है। सीमित संख्या में ही शेष स्थान बचे होने के कारण, आगामी ई-नीलामी का दूसरा चरण कंपनियों को अपनी विशिष्ट व्यावसायिक जगह का मालिक बनने का एक दुर्लभ अवसर प्रदान करता है। नई दिल्ली के सरोजिनी नगर में स्थित भारत बिजनेस पार्क (बीबीपी) का विकास एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। यह एक आधुनिक वाणिज्यिक कार्यालय परिसर है जिसे टिकाऊ और ऊर्जा-कुशल सुविधाओं के साथ विश्व स्तरीय कार्यालय अवसंरचना प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह परियोजना कार्यस्थल की कार्यक्षमता, सुरक्षा और स्थिरता के समकालीन मानकों को पूरा करने के लिए विकसित की जा रही है। ऊर्जा दक्षता और स्थिरता पर विशेष ध्यान देते हुए डिज़ाइन किए गए भारत बिज़नेस पार्क (बीबीपी) में सौर ऊर्जा प्रणाली, सौर स्ट्रीट लाइटिंग, ऊर्जा-कुशल चिलर और बेहतर संचालन के लिए एक बुद्धिमान भवन प्रबंधन प्रणाली (बीएमएस) जैसी सुविधाएं होंगी। इस परियोजना में मॉड्यूलर वर्षा जल संचयन प्रणाली, उन्नत ऊर्जा निगरानी, ??इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और एमबीआर तकनीक पर आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) शामिल हैं, जो जल पुनर्चक्रण और पर्यावरण पर कम प्रभाव डालने में सहायक हैं। शून्य अपशिष्ट की दिशा में काम करने के अपने दृष्टिकोण के अनुरूप, इस परियोजना में कचरा फेंकने की व्यवस्था और अपशिष्ट संपीडन प्रणाली के साथ-साथ प्रत्येक इकाई के लिए स्मार्ट एएमआर/एएमआई आधारित अल्ट्रासोनिक जल मीटर जैसे कुशल संसाधन प्रबंधन प्रणालियां भी शामिल होंगी। परिसर में केंद्रीकृत वातानुकूलन, उन्नत सुरक्षा और निगरानी प्रणाली और 100% बिजली बैकअप की सुविधा भी होगी, जिससे निर्बाध संचालन सुनिश्चित होगा। 2,800 से अधिक वाहनों की क्षमता वाली तीन-स्तरीय बेसमेंट पार्किंग सुविधा उपयोगकर्ताओं की सुविधा को और बढ़ाती है। भारत बिजनेस पार्क (बीबीपी) को एक हरित, अगली पीढ़ी के वाणिज्यिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो राष्ट्रीय राजधानी में टिकाऊ शहरी बुनियादी ढांचे के प्रति एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। इस ई-नीलामी से प्राप्त धनराशि का उपयोग चल रहे विभिन्न पुनर्विकास कार्यों के वित्तपोषण, परियोजना पूर्णता की समयसीमा को सुनिश्चित करने और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (रूश्रा) के तहत वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। NBCC द्वारा अपनाई गई मुद्रीकरण पद्धति बड़े पैमाने पर शहरी पुनर्विकास, महत्वपूर्ण रोजगार सृजन, ऊर्जा कुशल पहलों और नवीनतम वैधानिक अनुपालनों के प्रति आत्मनिर्भर दृष्टिकोण को दर्शाती है। इस सफल सौदे के साथ, NBCC ने रियल एस्टेट क्षेत्र में एक अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत किया है और पारदर्शी, प्रौद्योगिकी-आधारित संपत्ति मुद्रीकरण में नए मानदंड स्थापित करना जारी रखा है। इस ई-नीलामी में व्यापक भागीदारी, बेहतर मूल्य निर्धारण और उच्च रूपांतरण दरें सरकारी नेतृत्व वाले विकास द्वारा समर्थित सुनियोजित वाणिज्यिक संपत्तियों में निवेशकों के बढ़ते विश्वास को रेखांकित करती हैं। इस ई-नीलामी की सफलता से भारत के वाणिज्यिक रियल एस्टेट बाजार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और भविष्य में उच्च मूल्य वाले लेन-देन के लिए मार्ग प्रशस्त होगा।

श्री दिलीप कुमार ने सेल के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया

सरोज वार्ता/ब्यूरो

इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स (आईआरएसएमई) के वरिष्ठ अधिकारी श्री दिलीप कुमार ने 27 अप्रैल, 2026 को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। उनके पास ट्रेन संचालन, रोलिंग स्टॉक रखरखाव और मानव संसाधन प्रबंधन में दो दशकों से अधिक का व्यापक अनुभव है। श्री कुमार ने भारतीय रेलवे में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है, जिनमें पूर्व मध्य रेलवे (ईसीआर) के अपर मंडल रेल प्रबंधक और बिहार के नालंदा में हरनौत के मुख्य कारखाना प्रबंधक का पद शामिल है। उन्हें कई नवाचारों जैसे पूर्व मध्य रेलवे की पहली ISO 9001 प्रमाणित ट्रेन, वैगन्स में इन-सिटु व्हील रिप्लेसमेंट तकनीक की शुरुआत करने और राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित मधुबनी रेलवे स्टेशन सौंदर्यीकरण परियोजना का श्रेय जाता है। आईआईटी, बीएचयू से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक श्री कुमार को 'राष्ट्रीय उत्कृष्ट सेवा पुरस्कार' (2016) और सर्वश्रेष्ठ नवाचार के लिए 'रेलवे बोर्ड का उत्कृष्टता प्रमाण



पत्र' (2018-19) से सम्मानित किया जा चुका है। उनके अंतरराष्ट्रीय अनुभव में इनसीड सिंगापुर और आईक्लिफ कुआलालंपुर, मलेशिया से उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम, और एआरआई शिकागो, यूएसए में वैगन बोगी डिजाइन का विशेष प्रशिक्षण शामिल है।

नई दिल्ली में पहली बार में 5,779 करोड़ रुपये का बिक्री मूल्य प्राप्त हुआ

रोजगार और इंडस्ट्रियल ग्रोथ का मेगा हब बनेगा यूपी का जेवर



- डायरेक्ट सेलिंग मॉडल को बताया आत्मनिर्भर भारत का सशक्त माध्यम
- युवाओं को 'जॉब सीकर' से 'जॉब क्रिएटर' बनने की दिशा में प्रेरित किया
- मातृशक्ति के सशक्तिकरण में डायरेक्ट सेलिंग की अहम भूमिका पर जोर
- उत्तराखंड में निवेश, स्टार्टअप और विकास के आंकड़ों को रखा सामने
- 'वोकल फॉर लोकल' और 'लोकल टू ग्लोबल' को बढ़ावा देने की अपील

सरोज वार्ता/ब्यूरो

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुग्राम में आयोजित AWPL के भव्य 'विजय पर्व' कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री श्री धामी ने अपने संबोधन में कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से AWPL के उन प्रतिभाशाली एवं परिश्रमी साथियों को सम्मानित किया जा रहा है, जिन्होंने अपने परिश्रम और समर्पण से सफलता के नए आयाम स्थापित किए हैं। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि यह संस्थान डायरेक्ट सेलिंग मॉडल के माध्यम से अपने उत्पादों को सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचा रहा है, जिससे ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध हो रहे हैं और लाखों लोगों को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में उपस्थित विशाल जनसमूह का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे यह स्पष्ट होता है कि डायरेक्ट सेलिंग मॉडल आज लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रभावी माध्यम बन चुका है। उन्होंने इस भव्य आयोजन के लिए AWPL के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ डॉ. संजीव कुमार तथा उनकी पूरी टीम को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में युवाओं को 'जॉब सीकर' के बजाय 'जॉब क्रिएटर' बनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और डायरेक्ट सेलिंग मॉडल इसी सोच का सशक्त उदाहरण है। उन्होंने कहा कि यह मॉडल न केवल आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम है, बल्कि व्यक्तित्व विकास और क्षमताओं को निखारने का भी अवसर प्रदान करता है। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं एवं मातृशक्ति की भागीदारी पर जोर देते हुए कहा कि आज महिलाएं इस प्रकार के प्लेटफॉर्म के माध्यम से परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही हैं और समाज में अपनी अलग पहचान स्थापित कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2021 में केंद्र सरकार द्वारा डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्र के लिए उपभोक्ता संरक्षण एवं स्पष्ट नियम लागू किए गए, जिससे इस क्षेत्र में पारदर्शिता, विश्वसनीयता और उपभोक्ता हितों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। इन नियमों से डायरेक्ट सेलर्स के अधिकार मजबूत हुए हैं तथा पूरे सेक्टर को एक संगठित एवं भरोसेमंद ढांचा प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री तेजी से आगे बढ़ रही है और देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के 'रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म' के दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे देश में निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत को विश्व स्तर पर विकास, विश्वास और अवसरों की भूमि के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने 'स्टार्टअप इंडिया', 'वोकल फॉर लोकल', 'मेक इन इंडिया', 'स्किल इंडिया' और 'डिजिटल इंडिया' जैसी पहलों का उल्लेख करते हुए कहा कि इनके माध्यम से देश आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में हो रहे विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए बताया कि वर्ष 2023 में आयोजित ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट के अंतर्गत 3.56 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश समझौते हुए, जिनमें से 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतारे जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था निरंतर सशक्त हो रही है,



जिसमें जीएसडीपी में 7.23% की वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय में लगभग 41% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राज्य का वार्षिक बजट 60 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में 20 हजार से अधिक नए उद्योग स्थापित हुए हैं तथा स्टार्टअप्स की संख्या 700 से बढ़कर 1750 से अधिक हो गई है। साथ ही हेलिपोर्ट और हेलिपैड की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे कनेक्टिविटी और आपदा प्रबंधन क्षमता मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में बिजली उत्पादन तीन गुना से अधिक बढ़ा है तथा पर्यटन क्षेत्र में होटल उद्योग में लगभग 25% और होमस्टे में 50% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिला है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य ने सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन में देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है तथा Ease of Doing Business और Startup Ranking में भी अग्रणी श्रेणियों में स्थान हासिल किया है। साथ ही, इनोवेशन इंडेक्स में हिमालयी राज्यों में दूसरा स्थान और नीति आयोग के स्वच्छ इंडेक्स में प्रथम स्थान प्राप्त करना राज्य की उपलब्धियों को दर्शाता है। उन्होंने मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि 'वोकल फॉर लोकल' और 'लोकल टू ग्लोबल' की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए 'हाउस ऑफ हिमालयाज' ब्रांड की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके परिणामस्वरूप प्रदेश की लगभग पौने तीन लाख महिलाएं 'लखपति दीदी' बनकर सशक्तिकरण की दिशा में अग्रसर हुई हैं। उन्होंने कहा कि AWPL भी स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ-साथ युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अंत में मुख्यमंत्री ने सभी उपस्थित लोगों से आह्वान किया कि वे प्रधानमंत्री के विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने में अपना सक्रिय योगदान दें तथा देश को आगे बढ़ाने के इस अभियान में सहभागी बनें।



आरईसी ने 16,282 करोड़ का अब तक सर्वाधिक लाभ



सरोज वार्ता/ब्यूरो

31 मार्च, 2026 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वार्षिक स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणामों को मंजूरी देते हुए, आरईसी लिमिटेड ने कहा कि भारत सरकार द्वारा उठाए गए अनेक कदमों के कारण भारतीय विद्युत क्षेत्र नई जीवंतता के कगार पर है। पारंपरिक घाटे में चलने वाली बिजली वितरण कंपनियों ने मिलकर कुल निवल लाभ हासिल किया। यह महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। इस सुधार से स्थिर माहौल बना, जिससे परिसंपत्तियों की बेहतर गुणवत्ता का पता चला, जिससे रिस्क प्रीमियम में कमी आई। राष्ट्र निर्माण पर केंद्रित जिम्मेदार ऋणदाता के रूप में आरईसी ने लोन एसेट्स पर अपने यील्ड को सही करके अपने बॉरोअर्स को इस कम रिस्क प्रीमियम का फ़ायदा पहले से ही दे रहा है। सस्टेनेबल ग्रोथ पर लगातार फोकस के नतीजे दिख रहे हैं, नेट स्टेज-3 लोन (NPA) लगभग 'ज़ीरो' (0.12%) और स्टेज-2 लोन में वर्ष दर वर्ष 75% की कमी आई है। एसेट क्वालिटी से समझौता किए बिना आरईसी ने पिछले साल लोन बुक में लगभग ?17,000 करोड़ की ग्रोथ दर्ज की है। परिणामस्वरूप, 31 मार्च, 2026 तक लोन बुक 5.84 लाख करोड़ के सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर है। सरकार के विज़न के साथ, रिन्यूएबल लोन बुक 31 मार्च, 2026 तक बढ़कर 75,347 करोड़ हो गई, जो 30% की ग्रोथ दिखाती है। मुश्किल मैक्रो इकोनॉमिक हालात और जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता के बावजूद, आरईसी ने 31 मार्च 2026 को खत्म हुए वित्तीय वर्ष के दौरान ?16,282 करोड़ का अब तक का सर्वाधिक वार्षिक निवल लाभ दर्ज किया है।

वर्ष 2025-26 के लिए प्रमुख परिचालन और वित्तीय परिणामों की मुख्य बिंदु

- **संस्वीकृतियाँ:** 4,09,097 करोड़ बनाम 3,37,179 करोड़, 21% की वृद्धि
- **संवितरण:** 2,11,189 करोड़ बनाम 1,91,185 करोड़, 10% ज़्यादा
- **संवितरण (आरबीपीएफ को छोड़कर):** ?1,46,227 करोड़ बनाम 1,13,897 करोड़, 28% की वृद्धि
- **निवल मूल्य:** 31 मार्च 2026 को 84,290 करोड़ बनाम 31 मार्च 2025 को 77,638 करोड़, 9% की वृद्धि
- **कैपिटल एडिक्वेसी रेश्यो (CRAR):** 31 मार्च, 2026 तक 23.11%, जो भविष्य की ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए पर्याप्त अवसर दिखाता है

इंटरेस्ट स्प्रेड और NIM क्रम से 2.62% और 3.43% पर बेहतर बने हुए हैं। मज़बूत प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से 31 मार्च, 2026 को खत्म हुए साल के लिए अर्निंग्स पर शेयर बढ़कर 61.71 प्रति शेयर हो गई है। अपने शेयरहोल्डर्स को इनाम देने की परंपरा को जारी रखते हुए, कंपनी के बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स ने हर इक्विटी शेयर (हर शेयर की फेस वैल्यू 10/- पर) पर 1.55 का फ़ाइनल डिविडेंड घोषित किया है, जिससे फ़ाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए कुल डिविडेंड 18.55 प्रति शेयर होगा। आरईसी ने एमओयू प्रदर्शन में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और लगातार तीन सालों (वित्तीय वर्ष 2023, 2024 और 2025) तक 'एक्सीलेंट' रेटिंग हासिल की है। इसके अलावा, DPE की वित्त वर्ष'25 की PE सर्वे रिपोर्ट के अनुसार, आरईसी नेट प्रॉफ़िट कमाने वाली CPSEs की रैंकिंग में चार पायदान ऊपर चढ़कर 9वें से 5वें स्थान पर आ गई। इसके लगातार बिज़नेस, ऑपरेशनल और फ़ाइनेंशियल परफॉर्मेंस और भविष्य में पॉज़िटिव ग्रोथ के आधार पर, जनवरी 2026 में किए गए रिव्यू के बाद डीपीई ने आरईसी के 'महारत्न' स्टेटस को फिर से कन्फ़र्म किया। सस्टेनेबिलिटी आरईसी के मूल में है। इसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए आरईसी ने अपने ऑपरेशन के हर पहलू में ईएसजी (श्वस्त) को शामिल किया है, जिसका मुख्य फोकस रिन्यूएबल पोर्टफोलियो ग्रोथ पर है। यह ईएसजी एक्सीलेंस एनएसई ईएसजी रेटिंग्स में दिखता है, जहाँ आरईसी को देश की सभी कंपनियों में सबसे ज़्यादा रेटिंग मिली है।

अब घुसपैठ से मुक्त होगा पश्चिम बंगाल

सुरेश हिंदुस्तानी



पश्चिम बंगाल में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के तौर पर शुभेन्दु अधिकारी ने शासन की बागडोर संभाल ली है। भाजपा का यह स्पष्ट नारा रहा है कि वह विदेशी घुसपैठियों को देश से बाहर करेगी। इसलिए पश्चिम बंगाल के जनादेश में इस पर अब जनता की मुहर भी लग गई है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी ने मुस्लिम तुष्टिकरण को बढ़ावा देकर अपने शासन का संचालन किया। इसमें बांग्लादेश के घुसपैठियों का भी समर्थन भी शामिल रहा। अब भाजपा की सरकार बनने के बाद यह तय हो चुका है कि अब पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश से लगी हुई सीमाएं पहले से ज्यादा सुरक्षित होंगी और एक बड़ी समस्या से छुटकारा भी मिलेगा। इससे यह भी आशय निकलता है कि सबका साथ और सबका विकास वाली राजनीतिक अवधारणा को स्वीकार किया जाने लगा है। देश में इसी प्रकार की राजनीति की आवश्यकता है। क्योंकि राजनीतिक दलों ने आज देश में रहने वाले समाज के बीच इतना भेद पैदा कर दिया है कि कई जगह समाज बंधु एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। हिन्दू और मुसलमान समाज के ही हिस्से हैं, इसलिए इनको अलग अलग देखने की राजनीति नहीं होना चाहिए। इसके विपरीत देश के कुछ राजनीतिक दलों का आधार ही मुस्लिम वोट हैं। जबकि यह भी सही है कि तुष्टिकरण से किसी का भला न तो हुआ है और न ही होगा। लम्बे समय से पश्चिम बंगाल में जनसंख्या का अप्रत्याशित रूप से बढ़ना कई प्रकार के सवाल खड़ा करता रहा है। इसके पीछे बांग्लादेश से आए घुसपैठिए भी एक बड़ा कारण है। इस समस्या से बंगाल ही नहीं, असम भी प्रभावित है, लेकिन अच्छी बात यह है कि विपक्षी राजनीतिक दलों को यह समस्या दिखाई नहीं देती। असम और पश्चिम बंगाल की जनता इस घुसपैठ के विरोध में खड़ी हो गई है, इसलिए इस बार का जनादेश भी बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरोध में आया। इसी के चलते असम में भाजपा सरकार का पुनः बनना और पश्चिम बंगाल में एक नए राजनीतिक उदय के साथ सत्तारूढ़ होना इसी बात का परिचायक है कि भाजपा ही नहीं, जनता भी देश से घुसपैठियों को निकालने का मन बना चुकी है। सुनने में यह भी आ रहा है जो बांग्लादेशी नागरिक पश्चिम बंगाल में घुसपैठ करके आए, वे अपने देश वापस जाने का मानस बना चुके हैं। इसलिए यह भी कहा जा रहा है कि अब पश्चिम बंगाल घुसपैठ की समस्या से मुक्त हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में प्रारंभ से ही इस बात पर जोर दिया था कि वह विदेशी घुसपैठियों के खिलाफ है। भाजपा के नेताओं के भाषण भी इसी पर केंद्रित रहते थे। इस मुद्दे पर भाजपा को जनता का भी समर्थन मिला और जनता ने भाजपा को बहुमत दे दिया। इसके अलावा ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने जो कार्य किए, वह कहीं न कहीं हिन्दू समाज को नीचा दिखाने वाले ही थे, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के नेता शायद इस बात को भूल गए कि बहुसंख्यक समाज को नकारने की राजनीति एक प्रकार से उसके लिए सत्ता से अलग होने की तस्वीर पेश कर सकती है। पश्चिम बंगाल घुसपैठ की समस्या से बहुत प्रभावित हुए हैं। यहां पर अप्रत्याशित रूप से ज़मीनों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं। कई जगह अचानक ही मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र बनते जा रहे हैं। जिनमें मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर और मालदा आदि है। यह तीनों जिले बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए हैं। इसके चलते बंगाल में अपराध भी बहुत होने लगे हैं। इसका कारण यही माना जा रहा है कि जो व्यक्ति घुसपैठ करके आए हैं, उनके सामने रोजगार का संकट है। जब रोजगार नहीं मिलेगा तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति गलत कार्य भी करने लगता है। इससे की दशा और दिशा भी ख़राब हो रही है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के रास्ते कई बांग्लादेशी नागरिक घुसपैठ करते रहे हैं। स्थानीय नागरिकों की मदद से वे सभी अपने आशियाने भी बना रहे थे, इनके ज्यादातर आशियाने अवैध कब्ज़ा करके ही बने हैं। तृणमूल कांग्रेस की सरकार के समय इनको पर्याप्त संरक्षण भी मिला। उल्लेखनीय है जिन क्षेत्रों में मुस्लिमों की जनसंख्या अचानक बढ़ी है, वे सभी तृणमूल कांग्रेस के प्रभाव वाले क्षेत्र रहे हैं। इन क्षेत्रों में हिन्दू समाज का कोई भी व्यक्ति जाने से डरता है। सवाल यह है कि यह डर किसने पैदा किया और इसको संरक्षण देने वाले कौन हैं। तृणमूल कांग्रेस ने तुष्टिकरण की राह पर चलते हुए इनको ताकत देने का काम किया। और यही उसकी हार का कारण भी बना। अब पश्चिम बंगाल का राजनीतिक दृश्य परिवर्तित हो चुका है। जिन्होंने लम्बे समय तक अमानुषिक अत्याचार सहन किए, वे सत्ता में आ चुके हैं, लेकिन भाजपा को यह सत्ता ऐसे ही नही मिल गई। उसके सैकड़ों कार्यकर्ता का बलिदान इस जीत के नींव के पत्थर बने। चुनाव के बाद शुभेन्दु अधिकारी के निजी सहायक देवनाथ की हत्या इसका ताजा उदाहरण है। जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यह कार्य प्रशिक्षित अपराधियों ने किया। संभावना इस बात की भी है कि घटना के बाद ये बांग्लादेश भाग चुके हैं। इसे राजनीतिक हत्या के तौर पर भी देखा जा रहा है और इसके आरोप तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर लग रहे हैं। घुसपैठियों की समस्या से त्रस्त पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद विदेशी घुसपैठिओं के चेहरे उतरने लगे हैं, क्योंकि अब इन विदेशी घुसपैठियों को सहन नहीं किया जाएगा। अब उनको बाहर जाना ही होगा। भाजपा की सरकार ही इनको बाहर निकलेगी। देश के गृह मंत्री अमित शाह इसकी चेतावनी पहले से ही देते रहे हैं। यहां यह कहना भी उचित होगा कि भाजपा ने केवल घुसपैठियों को बाहर निकालने की ही बात की है, भारत के मुसलमानों की नहीं, लेकिन विपक्ष और खासकर तृणमूल कांग्रेस ने ऐसा भ्रम फैलाने का प्रयास किया कि सारे मुस्लिमों पर इसका प्रभाव होगा। विदेशी घुसपैठियों को बाहर निकालना सभी चाहते हैं, विपक्ष को इस मुद्दे पर भाजपा का साथ देना चाहिए, क्योंकि यह राष्ट्रीय हित की बात है।

वैश्विक संकट के बीच सबसे बड़े कूटनीतिक मिशन पर निकल रहे हैं मोदी, विश्व राजनीति में होगा बड़ा उलटफेर



नीरज कुमार दुबे

वैश्विक चुनौतियों, बदलते भू-राजनीतिक समीकरणों, ऊर्जा संकट, आपूर्ति श्रृंखला की अनिश्चितताओं और तकनीकी प्रतिस्पर्धा के बीच भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बड़े कूटनीतिक मिशन पर निकल रहे हैं। 15 मई से 20 मई तक प्रस्तावित उनकी बहुराष्ट्रीय विदेश यात्रा के दौरान वह संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा करेंगे। यह यात्रा भारत की वैश्विक रणनीति, आर्थिक हितों और सामरिक साझेदारियों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। इस दौरान ऊर्जा सहयोग, व्यापार, हरित प्रौद्योगिकी, रक्षा, निवेश, नवाचार और वैश्विक सुरक्षा जैसे अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी, जिससे भारत की अंतरराष्ट्रीय भूमिका और अधिक मजबूत होने की संभावना है। इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि भारत अपने पारंपरिक मित्र देशों के साथ केवल व्यापारिक संबंधों तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि वह प्रौद्योगिकी, हरित ऊर्जा, रक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, समुद्री सुरक्षा और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला जैसे क्षेत्रों में दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग को भी विस्तार देना चाहता है। हाल के वर्षों में भारत ने विश्व मंच पर एक भरोसेमंद और संतुलित शक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाई है।

> ● विपक्षी सांसदों का दावा था कि ओम बिरला ने 'पक्षपातपूर्ण व्यवहार' दिखाया है और उनका कार्यालय अपेक्षित निष्पक्षता बनाए रखने में विफल रहा है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि कई बार लोकतांत्रिक प्रक्रिया और स्पीकर की भूमिका पर चर्चा हुई है और कई बार मेरा नाम लिया गया, मेरे बारे में गंदी बातें कही गईं।

यही कारण है कि यूरोप और पश्चिम एशिया के देश भारत को भविष्य के आर्थिक और सामरिक साझेदार के रूप में देख रहे हैं। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा की शुरुआत संयुक्त अरब अमीरात से करेंगे, जहां वह राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग, निवेश, डिजिटल भुगतान, रक्षा और भारतीय समुदाय के कल्याण जैसे विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हुई है। संयुक्त अरब अमीरात भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है तथा बीते पच्चीस वर्षों में भारत में निवेश करने वाले प्रमुख देशों में शामिल है। दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते ने व्यापार को नई गति दी है। ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भी संयुक्त अरब अमीरात भारत का महत्वपूर्ण सहयोगी है। इसके अलावा भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा दोनों देशों की सामरिक निकटता को और अधिक मजबूत बना रहा है। वहां रह रहे लाखों भारतीय दोनों देशों के सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों की मजबूत कड़ी हैं। संयुक्त अरब अमीरात के बाद प्रधानमंत्री नीदरलैंड जाएंगे। यह यात्रा भारत और नीदरलैंड के बीच बढ़ते आर्थिक तथा प्रौद्योगिकी सहयोग को नई दिशा देगी। प्रधानमंत्री वहां के राजा विलेम अलेक्जेंडर, महारानी माक्सिमा और प्रधानमंत्री रोब येटन से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच रक्षा, सुरक्षा, हरित हाइड्रोजन, जल प्रबंधन, सेमीकंडक्टर और नवाचार जैसे क्षेत्रों में तेजी से सहयोग बढ़ रहा है। नीदरलैंड यूरोप में भारत का प्रमुख व्यापारिक साझेदार है और भारत में बड़े निवेशकों में शामिल है। जल प्रबंधन और कृषि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नीदरलैंड की विशेषज्ञता भारत के लिए अत्यंत उपयोगी मानी जाती है। दोनों देश मुक्त और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र के समर्थन में भी एक समान दृष्टिकोण रखते हैं। मोदी की स्वीडन की यात्रा भारत और नॉर्डिक देशों के साथ

बढ़ते सहयोग को और मजबूत बनाएगी। प्रधानमंत्री गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन से वार्ता करेंगे। दोनों देशों के बीच व्यापार, हरित परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उभरती प्रौद्योगिकी, रक्षा, अंतरिक्ष और जलवायु कार्रवाई जैसे क्षेत्रों में व्यापक सहयोग की संभावनाएं हैं। हम आपको बता दें कि स्वीडन की अनेक प्रमुख कंपनियां भारत में सक्रिय हैं और दोनों देशों के बीच नवाचार आधारित साझेदारी तेजी से विकसित हो रही है। भारत और स्वीडन लोकतांत्रिक मूल्यों, सतत विकास और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में समान सोच रखते हैं। हरित औद्योगिक परिवर्तन और जलवायु संरक्षण के लिए दोनों देशों का सहयोग वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इसके बाद नॉर्वे जाएंगे, जहां वह तीसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी और पिछले तैंतालीस वर्षों में भारत से वहां होने वाली पहली प्रधानमंत्री स्तरीय यात्रा भी मानी जा रही है। नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्तोरे के साथ होने वाली वार्ता में व्यापार, निवेश, हरित प्रौद्योगिकी और समुद्री अर्थव्यवस्था पर विशेष जोर रहेगा। भारत और नार्वे के संबंध समुद्री सहयोग, हरित ऊर्जा और सतत विकास पर आधारित हैं। भारत-यूरोपीय मुक्त व्यापार समझौते के बाद दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को नई गति मिलने की संभावना है। नॉर्वे का विशाल पेंशन कोष भारतीय पूंजी बाजार में महत्वपूर्ण निवेश कर चुका है। आर्कटिक क्षेत्र, हरित जहाजरानी और समुद्री संसाधनों के प्रबंधन में दोनों देशों का सहयोग

● प्रधानमंत्री मोदी इसके बाद नॉर्वे जाएंगे, जहां वह तीसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी और पिछले तैंतालीस वर्षों में भारत से वहां होने वाली पहली प्रधानमंत्री स्तरीय यात्रा भी मानी जा रही है। नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्तोरे के साथ होने वाली वार्ता में व्यापार, निवेश, हरित प्रौद्योगिकी और समुद्री अर्थव्यवस्था पर विशेष जोर रहेगा। भारत और नार्वे के संबंध समुद्री सहयोग, हरित ऊर्जा और सतत विकास पर आधारित हैं।

भविष्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पक्ष होगा। इसमें नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड के शीर्ष नेता शामिल होंगे। यह मंच भारत और नॉर्डिक देशों के बीच प्रौद्योगिकी, नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा, अंतरिक्ष, सतत विकास और समुद्री अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नई रणनीतिक दिशा देगा। वैश्विक आपूर्ति शृंखला को मजबूत बनाने और हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में यह सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री इटली जाएंगे। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और राष्ट्रपति सर्जियो मातारेला के साथ उनकी बैठकें भारत-इटली रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेंगी। दोनों देश 2025 से 2029 तक की संयुक्त रणनीतिक कार्ययोजना पर तेजी से काम कर रहे हैं। व्यापार, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और औद्योगिक सहयोग इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। इटली ने चीन की बेल्ट एंड रोड पहल से अलग होकर भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे को समर्थन दिया है, जिससे दोनों देशों की सामरिक निकटता बढ़ी है। रक्षा क्षेत्र में सह-विकास और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर जोर दिया जा रहा है। इटली भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के प्रयासों का भी समर्थन करता रहा है। वहां रह रहा भारतीय समुदाय दोनों देशों के संबंधों को सामाजिक और सांस्कृतिक मजबूती प्रदान करता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह विदेश यात्रा केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत की बदलती वैश्विक भूमिका का प्रतीक भी है। यह यात्रा भारत को ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी सहयोग, हरित विकास, रक्षा साझेदारी और वैश्विक व्यापार के नए अवसर प्रदान करेगी। साथ ही यह संदेश भी देगी कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत विश्व राजनीति और अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख और विश्वसनीय केंद्र बनकर उभर रहा है।



धर्मनिरपेक्षता की मृगतृष्णा में भटक रहा 'इंडिया गठबंधन' तोड़ रहा है सियासी दम?



कमलेश पांडेय

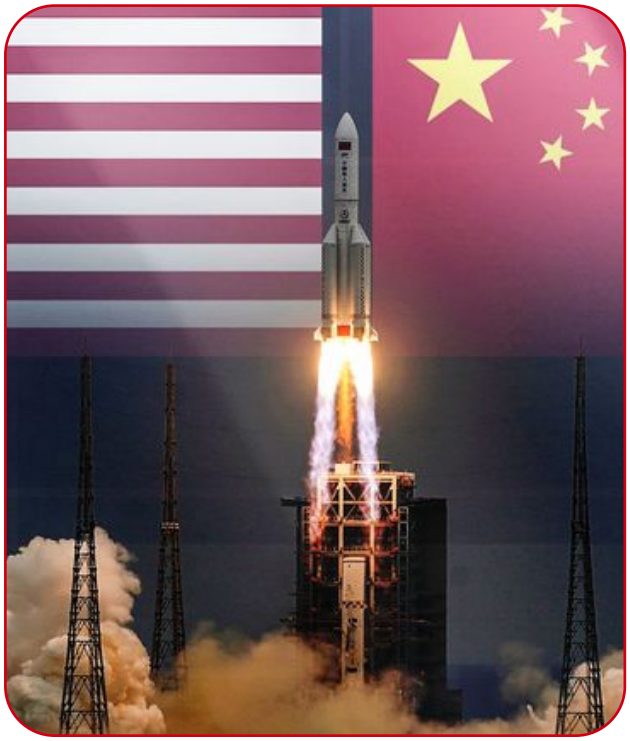
धर्मनिरपेक्षता की भारतीय अवधारणा मूलतः 'सर्वधर्म समभाव' और राज्य की धार्मिक निष्पक्षता पर आधारित रही है। लेकिन पिछले कई दशकों में भारतीय राजनीति के एक हिस्से ने इसे सामाजिक संतुलन के बजाय 'अल्पसंख्यक तुष्टिकरण' के राजनीतिक औजार के रूप में प्रस्तुत किया। यही कारण है कि आज अनेक क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दल वैचारिक संकट से गुजरते दिखाई दे रहे हैं। सच कहूं तो वे सभी धर्मनिरपेक्षता की मृगतृष्णा में भटक रहे हैं, 'इंडिया गठबंधन' के सहयोगी दल कांग्रेस की बेरुखी से अपना अपना सियासी दम तोड़ते जा रहे हैं! जानिए कैसे जहां कांग्रेस ने स्वतंत्रता के बाद लंबे समय तक खुद को धर्मनिरपेक्ष राजनीति की केंद्रीय धुरी के रूप में स्थापित रखा। परंतु समय के साथ उस पर यह आरोप मजबूत होता गया कि उसने बहुसंख्यक समाज की सांस्कृतिक आकांक्षाओं को पर्याप्त महत्व नहीं दिया और वोट बैंक आधारित राजनीति को प्राथमिकता दी। इसका परिणाम यह हुआ कि भाजपा ने 'सांस्कृतिक राष्ट्रवाद' और 'बहुसंख्यक अस्मिता' के प्रश्न को राजनीतिक विमर्श के केंद्र में ला दिया। आज स्थिति यह है कि जो दल कभी भाजपा के हिंदुत्व विमर्श का तीखा विरोध करते थे, वे भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मंदिर, सनातन परंपरा, जातीय-सामाजिक प्रतिनिधित्व और राष्ट्रवाद की भाषा बोलने लगे हैं। इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि भारतीय मतदाता अब केवल 'धर्मनिरपेक्षता' के पारंपरिक नारों से संतुष्ट नहीं है, बल्कि वह सांस्कृतिक आत्मसम्मान और विकास के संतुलन की अपेक्षा कर रहा है। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा संकट यह है कि वह अभी तक यह तय नहीं कर पाई है कि उसकी राजनीति की मूल दिशा क्या होगी–पारंपरिक अल्पसंख्यक केंद्रित गठजोड़? सामाजिक न्याय आधारित नई राजनीति? या फिर भारतीय सांस्कृतिक चेतना के साथ सामंजस्य? यदि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल समय रहते अपने वैचारिक ढांचे का पुनर्मूल्यांकन नहीं करते, तो उनके सामने तीन बड़े खतरे बने रहेंगे– पहला, बहुसंख्यक समाज से लगातार बढ़ती दूरी उनके लिए सियासी चिंता का सबब बन सकती है। क्योंकि क्षेत्रीय दलों द्वारा उनके पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाया जा चुका है। दूसरा, भाजपा के राष्ट्रवादी विमर्श के सामने वैकल्पिक नैरेटिव का अभाव उतपन्न हो गया है। हालांकि यह भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय लोकतंत्र केवल बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक राजनीति पर नहीं चलता। तीसरा, अंततः जनता विकास, सुशासन, सुरक्षा, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय आत्मविश्वास–इन सभी का संतुलन चाहती है। इसलिए भविष्य उसी राजनीतिक शक्ति का होगा जो पहचान की राजनीति से ऊपर उठकर विश्वसनीय शासन मॉडल प्रस्तुत कर सके। कांग्रेस के लिए चुनौती केवल चुनाव जीतने की नहीं, बल्कि अपनी वैचारिक प्रासंगिकता बचाने की है। आने वाले वर्षों में यह स्पष्ट होगा कि वह अपने पुराने ढांचे से बाहर निकलकर नई राजनीतिक भाषा गढ़ पाती है या नहीं।

•सच कहूं तो वे सभी धर्मनिरपेक्षता की मृगतृष्णा में भटक रहे हैं, 'इंडिया गठबंधन' के सहयोगी दल कांग्रेस की बेरुखी से अपना अपना सियासी दम तोड़ते जा रहे हैं! जानिए कैसे जहां कांग्रेस ने स्वतंत्रता के बाद लंबे समय तक खुद को धर्मनिरपेक्ष राजनीति की केंद्रीय धुरी के रूप में स्थापित रखा।

अंतरिक्ष में चीनी-अमेरिकी संघर्ष के बीच भारत

पुष्परंजन

बीते बुधवार को कांग्रेस की एक सुनवाई में अमेरिकी सांसदों को बताया गया, कि चीन, अमेरिका के लिए 'अंतरिक्ष में सबसे बड़ा खतरा और प्रतिस्पर्धी' है, जो अपनी खगोलीय क्षमताओं का इस्तेमाल 'कूटनीति और सामरिक प्रभाव के एक हथियार के तौर पर' कर रहा है; यह बात ऐसे समय में सामने आई है जब चांद पर पहुंचने की इन दोनों देशों की होड़, और तेज़ हो गई है। अमेरिका और चीन के बीच अंतरिक्ष को लेकर चल रही होड़ में दोनों देशों का लक्ष्य आने वाले सालों में चांद पर अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजना है। जहां चीन ने अपनी पहली मानवयुक्त चंद्र लैंडिंग के लिए 2030 का लक्ष्य रखा है, वहीं अमेरिका के आर्टेमिस कार्यक्रम का लक्ष्य 2028 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चांद की सतह पर वापस लाना, और 2030 तक वहां एक अंतरिक्ष सैन्य अड्डा बनाना शुरू करना है; इससे इन दोनों महाशक्तियों के बीच कड़ी टक्कर शुरू हो गई है। 'सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़' में एयरोस्पेस सिक्योरिटी प्रोजेक्ट की निदेशक कैरी बिंगेन के हाउस फॉरेन अफेयर्स सब-कमेटी ऑन यूरोप की एक सुनवाई में दी जानकारी के मुताबिक, 'जैसे-जैसे देश मानकों के मामले में अमेरिका या चीन में से किसी एक के साथ जुड़ेंगे, तो जीतने वाला देश न सिर्फ़ तकनीक देगा, बल्कि वह उन शर्तों को भी तय करेगा, जिनके आधार पर सूचनाओं का आदान-प्रदान होगा। नेटवर्क आपस में काम करेंगे, लेकिन दुनिया को किस नज़र से देखा जाएगा?' सुनवाई के दौरान फ्लोरिडा के रिपब्लिकन कांग्रेसी रैंडी फाइन के अनुसार, 'जब अंतरिक्ष की बात आती है, तो वह 'चीन को लेकर बहुत चिंतित हैं, जैसा कि मुझे पता है कि और भी कई लोग हैं। मुझे लगता है कि चीन खुद को हमारे साथ युद्ध की स्थिति में देखता है। यह भी कि हम अक्सर इसे उसी नज़र से नहीं देखते।' दरअसल पिछले एक साल में अंतरिक्ष दौड़ में कई अहम घटनाक्रम देखने को मिले हैं; अमेरिका ने अपने आर्टेमिस कार्यक्रम का दूसरा सफल मिशन पूरा किया, वहीं चीन ने अपने 2030 के मून मिशन की तैयारी में कई अहम प्रगति की। अमेरिका ही एकमात्र ऐसा देश है, जिसने इंसानों को सफलतापूर्वक चांद पर पहुंचाया है। दूसरी तरफ़ चीन, भारत और पूर्व सोवियत संघ सहित अन्य देशों ने चांद की सतह पर रोबोटिक मिशन उतारने में कामयाबी हासिल की। गत बुधवार को हुई इस सुनवाई का शीर्षक था, 'ऑर्बिट्स ऑफ़ इन्फ्लुएंस : यूएस स्पेस सिक्योरिटी'। यह सुनवाई उसी दिन हुई, जिस दिन ट्रंप ने व्हाइट हाउस में आर्टेमिस-टू के अंतरिक्ष यात्रियों की मेज़बानी की थी। इस कार्यक्रम में नासा मिशन में तीन अमेरिकी और एक कनाडाई अंतरिक्ष यात्री शामिल थे। सुनवाई के दौरान, एयरोस्पेस सिक्योरिटी प्रोजेक्ट की निदेशक कैरी बिंगेन का चीन पर आरोप था कि वह ग्लोबल साउथ में अपनी साझेदारियों का विस्तार करके अंतरिक्ष का इस्तेमाल अन्य देशों पर अपना प्रभाव जमाने के लिए कर रहा है। जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के स्पेस पॉलिसी इंस्टिट्यूट के डायरेक्टर स्कॉट पेस के मुताबिक, चीन अपनी महत्वाकांक्षाओं को मशहूर 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' के ज़रिए आगे बढ़ा रहा है, जिसमें पार्टनर देशों को जोड़ने वाला एक बढ़ता हुआ स्पेस कंपोनेंट भी शामिल है। कैरी बिंगेन के खुलासे के मुताबिक, चीन ने 'ग्लोबल साउथ' कहे जाने वाले लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के कई देशों के साथ समझौते किए हैं। बिंगेन के मुताबिक, 'वे स्पेस ग्राउंड एंटीना, ग्राउंड स्टेशन कमांड और कंट्रोल साइट लगा रहे हैं। यह बुनियादी टेक्नोलॉजी है जो उन ग्राउंड स्टेशनों और एंटीना को सरकारी सिस्टम या किसी कमर्शियल सिस्टम के साथ बातचीत करने में मदद करता है।' अमेरिकी एयरोस्पेस सिक्योरिटी प्रोजेक्ट की निदेशक कैरी बिंगेन के मुताबिक, 'चीन, जहां एक तरफ अपना कमर्शियल स्पेस सेक्टर बना रहा है, वहीं उसका यह प्रोग्राम काफी हद तक पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और सरकार द्वारा ही चलाया जा रहा है। इस सुनवाई में शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और रूस के बीच हुई स्पेस रेस का भी ज़िक्र हुआ, जब रूस, 'सोवियत संघ' के नाम से जाना जाता था।' 20वीं सदी का ज़्यादातर



हिस्सा मुकाबले में गुज़र गया, लेकिन हाल के सालों में हालात बदल गए हैं। इस बारे में बिंगेन के विचार हैं कि जहां रूस अभी भी एक खतरा बना हुआ है, वहीं चीन एक अहम खिलाड़ी के तौर पर उभरा है, जो किसी भी आधुनिक स्पेस प्रोग्राम के इतिहास में सबसे तेज़ तरक्की में से एक है। कैरी बिंगेन के अनुसार, 'स्पेस में नई ऊंचाइयां छूने की दौड़ जारी है- अमेरिका, चीन और रूस, मिलिट्री और सुरक्षा के क्षेत्रों में स्पेस में एक-दूसरे से लगातार मुकाबला कर रहे हैं।' ठीक से देखा जाये, तो यह पूरी दुनिया के लिए चेतावनी है। यहां रक्षा और अंतरिक्ष मामलों के विशेषज्ञ कौशिक रे की यह बात महत्वपूर्ण है कि, 'हालांकि, भारत आर्टेमिस-टू में सीधे तौर पर शामिल नहीं है, लेकिन वह 'आर्टेमिस अकार्ड' का हस्ताक्षरकर्ता है, और इस तरह वह अमेरिका के नेतृत्व वाले चांद की खोज के बड़े इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाता है। नतीजतन, आर्टेमिस-टू की सफलता उस ढांचे को मज़बूत करती है, जिसमें भारत अब एक हिस्सेदार है।' गौरतलब है कि भारत ने पूरी शिद्दत से रूस, अमेरिका और चीन के बाद, मानव अंतरिक्ष उड़ानें लॉन्च करने वाला चौथा देश बनने का लक्ष्य रखा है। इस संदर्भ में चंद्रयान चंद्र अन्वेषण मिशनों का भी रे ने जिक्र किया। उनके मुताबिक, 'इसरो को आर्टेमिस-टू मिशन द्वारा जुटाए गए अनुभव और डेटा से फ़ायदा होगा, जो भारत के चंद्रयान और गगनयान कार्यक्रमों के साथ-साथ लंबी अवधि की मानव अंतरिक्ष उड़ानों में इसरो की भविष्य की महत्वाकांक्षाओं के लिए भी बहुत प्रासंगिक है।' चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) कक्षा में उपग्रहों को नष्ट करने के लिए डिज़ाइन की गई जमीनी मिसाइलों का विकास जारी रखे हुए है। पीएलए ने रोबोटिक भुजाओं, कैमरों और सेंसरों से लैस उपग्रह तैनात किए हैं, जो शत्रु उपग्रहों से निपटने या उनमें हस्तक्षेप करने में सक्षम हैं। चीन, इमेजिंग उपग्रहों को नुकसान पहुंचाने, जैमर के ज़रिये उनकी क्षमता कम करने, या उन्हें 'अंधा' करने के लिए डिज़ाइन की गई, जमीनी लेजर प्रणालियां विकसित कर रहा है। पेंटागन की रिपोर्ट की मानें, तो पीएलए, उपग्रह नियंत्रण प्रणालियों को हैक करने, सैन्य लामबंदी और रसद व्यवस्था को बाधित करने पर फोकस्ड है। आर्टेमिस-टू का सहयोगी बनने से हमारी महत्वाकांक्षाओं को मज़बूती मिलती है, यहां तक तो बात ठीक है। लेकिन जो भविष्य की तैयारियां हम देख रहे हैं, यदि चीन और अमेरिका के बीच अंतरिक्ष में युद्ध छिड़ा, फिर भारत के लिए विकट स्थिति होगी। दोनों पक्षों में देर-सवेर अंतरिक्ष में घमासान होना तय मानिये। ऐसे में भारत किसकी तरफ़ होगा? यह विचारणीय विषय है!

सोनार बांग्ला का संकल्प



सरोज वार्ता/ब्यूरो

यह भाजपा के लिए आह्लादित होने का वक्त है कि आजादी के बाद पहली बार बंगभूमि में उसकी सरकार बनी है। जिस धूमधाम व उल्लास संग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा व एनडीए के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार का शपथग्रहण समारोहपूर्वक संपन्न हुआ, उससे इसके महत्व का पता चलता है। भाजपा के लिए यह मौका इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उसकी पूर्ववर्ती मातृ पार्टी जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि में सरकार बनाने का सपना पौन सदी बाद पूरा हुआ। दशकों तक वामपंथी दलों का गढ़ रहे बंगाल में दक्षिणपंथ का उदय एक विस्मयकारी घटना है। डेढ़ दशक से सत्ता में काबिज तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने में भाजपा ने साम-दाम-दंड-भेद के मुहावरे को हकीकत बनाया। कई दशकों के योजनाबद्ध अभियानों के बाद बंगाल में कमल खिला है। आक्रामक प्रचार तंत्र, मजबूत संगठन व संघ के वरदहस्त के चलते आज पश्चिम बंगाल भाजपामय हुआ है। यह पल इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि भाजपा ने कभी वामगढ़ रहे प्रदेश में अपनी यात्रा शून्य से शुरू की है। एक दशक में सुनियोजित अभियान से भाजपा का सत्ता पर काबिज होना भारतीय राजनीति की ऐतिहासिक घटना कही जा सकती है। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि शुभेंदु विपक्ष में रहते दिखाए गए आक्रामक तेवरों को छोड़, प्रतिशोध की राजनीति में न उलझकर, इस परिवर्तन को सार्थक बनाएंगे। कुछ ऐसा करें कि देश में शुभेंदु विकास मॉडल की चर्चा हो। निस्संदेह, बंगाल में मिली बड़ी कामयाबी का श्रेय केंद्रीय नेतृत्व व पार्टी संगठन के साथ ही शुभेंदु अधिकारी को दिया जाना चाहिए, जिन्होंने सत्ता के दमन का सामना करते हुए न केवल संगठन को मजबूत बनाये रखा, बल्कि नंदीग्राम से लेकर भवानीपुर तक बंगाल की शेरनी कही जाने वाली ममता बनर्जी को सीधी लड़ाई में परास्त भी किया। वे पिछले पांच वर्ष से सड़क से विधानसभा तक में आक्रामक ढंग से टीएमसी का प्रतिरोध करते रहे। लेकिन अब जब उन्हें राज्य की बागडोर सौंपी गई है तो उम्मीद करें कि वे राज्य की कानून व अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएंगे। उद्योग विरोधी नीतियों को दूर कर, राज्य में भारी निवेश को आमंत्रित करके बेरोजगारी संकट को दूर करने का प्रयास करेंगे। राज्य में कानून व्यवस्था, खासकर महिला सुरक्षा का बड़ा मुद्दा रहा है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद राज्यव्यापी आक्रोश पनपा था। संदेशखाली में महिलाओं से दुर्व्यवहार व हिंसा की घटनाएं लोगों को याद हैं। राष्ट्रवादी नीतियों को लेकर अगुवा रहने वाली भाजपा के लिए बांग्लादेश सीमा से घुसपैठ रोकना प्राथमिकता होगी, लेकिन इसका खमियाजा भारतीय नागरिकों को न भुगतना पड़े। उम्मीद की जानी चाहिए कि शुभेंदु सरकार राज्य में राजनीतिक व चुनावी हिंसा पर लगाम लगाने की ठोस पहल करेगी। साथ ही उन हिंसा करने वाले दबंग तत्वों पर लगाम लगाएगी, जो चोला बदलकर हर नई सरकार की छतरी के नीचे खड़े हो जाते हैं। जो कालांतर राज्य में अराजक राजनीतिक संस्कृति को जन्म देते हैं। कानून व्यवस्था सुधरने से ही पश्चिम बंगाल पटरी पर लौटेगा।

> **उद्योग विरोधी नीतियों को दूर कर, राज्य में भारी निवेश को आमंत्रित करके बेरोजगारी संकट को दूर करने का प्रयास करेंगे। राज्य में कानून व्यवस्था, खासकर महिला सुरक्षा का बड़ा मुद्दा रहा है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद राज्यव्यापी आक्रोश पनपा था।**

सोने व ईंधन का संयम



सरोज वार्ता/ब्यूरो

खाड़ी युद्ध से उपजे हालात व बाधित वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के बीच प्रधानमंत्री का ईंधन के उपयोग व सोने की खरीद में संयम बरतने का आह्वान निस्संदेह, वक्त की जरूरत है। लेकिन तेलंगाना के बाद बडोदरा से दूसरी बार उनके राष्ट्र को संबोधन व इसके समय को लेकर सवाल भी उठे हैं। निस्संदेह, हालात काफी दिनों से चुनौतीपूर्ण बने हैं, रुपये में तेज गिरावट व महंगे कच्चे तेल के आयात की वजह से हमारा विदेशी मुद्रा भंडार काफी दबाव में रहा है। आलोचक सवाल उठा रहे हैं कि इस घोषणा के लिये विधानसभा चुनाव परिणामों का इंतजार क्यों किया गया। कुछ लोगों का मानना है कि सत्ता शीर्ष से किया गया आह्वान कई बार देश में असुरक्षाबोध पैदा करता है, जिसका नकारात्मक असर भी पड़ सकता है। दरअसल, इससे कृत्रिम संकट पैदा करने वाले तत्व भी सक्रिय हो जाते हैं। इससे चीजों की जमाखोरी और कालाबाजारी को भी बढ़ावा मिलता है। इसमें दो राय नहीं कि देश बड़ी मात्रा में कच्चा तेल व सोना आयात करता है। जाहिर बात है जब इनकी वैश्विक कीमतें बढ़ती हैं तो इन दोनों के कारण भारी दबाव देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ता है। निस्संदेह, विषम वैश्विक परिस्थितियों में ईंधन की बचत, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता कम करना चुनौतियों से मुकाबले के लिये समझदारी भरे उपाय हैं। लेकिन एक हकीकत यह भी है कि पिछले डेढ़ माह में सरकार विधानसभा चुनावों में व्यस्त रही। इस दौरान आर्थिक प्रबंधन का मुद्दा हाशिये पर चला गया। अब इन चुनौतियों से मुकाबले के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन लोगों से विदेशों में शादियां टालने, सोना खरीदने से बचने के लिये कहना बताता है कि रुपये में तेज गिरावट से सरकार चिंतित है। कहा जा रहा है कि बार-बार अर्थव्यवस्था के मजबूत होने का दावा करने वाली सरकार को जनता से व्यवहार में संयम बरतने का आग्रह करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। दरअसल, आशंका यह भी है कि इन कदमों के ऐसे भी नतीजे निकल सकते हैं,जिनकी उम्मीद न की गई हो। निर्विवाद रूप से सोना भारतीय संस्कारों में है। वहीं भारत में आभूषण उद्योग लाखों लोगों की रोजी-रोटी का जरिया है। ऐसे में सोने की खरीद में गिरावट से संपन्न निवेशकों के मुकाबले श्रमिकों को ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। वहीं दूसरी ओर वर्क-फ्रॉम होम की नीति, काम करने वालों के बड़े तबके के लिए व्यावहारिक नहीं है। निस्संदेह, किसी भी आसन्न संकट में नागरिकों की जिम्मेदारी मायने रखती है। यह हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। लेकिन सवाल यह है कि मंत्रियों के कारों के काफिलों पर भी अंकुश लगेगा.. क्या शासन प्रशासन की शाहखर्ची पर लगाम लगेगी...। यदि ऐसा नहीं होता तो जनता की स्वतःस्फूर्त पहल प्रभावित होगी। वैसे भी नागरिक जिम्मेदारी एक हद तक तो प्रभावी हो सकती है,लेकिन वह किसी आपातकालीन योजना का विकल्प नहीं हो सकती। सरकार को भी अपनी आर्थिक नीतियों पर पुनर्विचार की जरूरत है। जहां तक सोने की खरीद पर संयम का सवाल है तो उससे देश में गहरा भावनात्मक लगाव जुड़ा रहा है। सोना हमारी संस्कृति, परंपरा, बचत और पारिवारिक समारोहों में गहरे तक शामिल रहा है। लेकिन सदियों से सम्मोहित करते सोने का आयात विदेशी मुद्रा भंडार पर गहरा असर डालता है। ऐसे में राष्ट्र हितों के मद्देनजर जीवन यापन करना, राष्ट्रीय कर्तव्य निभाने जैसा है। विगत में कई बार जब देश पर संकट आया तो लोगों ने राष्ट्र की संप्रुभता की रक्षा के लिये सोना तक दान किया। आंकड़े बताते हैं कि देश में हर साल छह सौ से सात सौ टन सोना आयात होता है, लेकिन निर्यात का प्रतिशत ना के बराबर है। बताया जाता है कि देश का नब्बे फीसदी सोना आयात होता है। यह सोना अर्थव्यवस्था में सक्रिय न होकर घरों में एकत्र हो जाता है। एक अनुमान के अनुसार देश के घरों में करीब 27 हजार टन सोना जमा है। बड़ी मात्रा में डॉलर खर्च करके आयात होने वाला सोना देश के चालू खाते और विदेशी मुद्रा भंडार पर प्रतिकूल असर डालता है। ऐसे में सोने पर संयम अर्थव्यवस्था को संबल देने में मददगार हो सकता है।

भारतीय सैन्य सेवा की प्रतिज्ञा और अनुबंध के मायने



लेफ्टिनेंट जनरल एसएस मेहता

कोहिमा युद्ध स्मारक पर एक सादा-सा शिलालेख है, जिसको भारतीय भूमि पर लड़े गए भीषणतम युद्धों में एक की यादगार में लगाया था, इस पर उकेरी पंक्ति है : 'जब तुम घर लौटोगे, तो उन्हें हमारे बारे में बताना और कहना कि तुम्हारे कल के लिए, हमने अपना आज दिया'। यह कोई नारा नहीं, सच्चाई की दास्तां है। बहुत से लोगों को पहले और दूसरे विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों के योगदान का तो पता है, जो तीन महाद्वीपों में लड़ी गई थीं। लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि दूसरे विश्व युद्ध की एक लड़ाई भारतीय भूमि पर भी लड़ी गई। कोहिमा की लड़ाई, जिसे 'भूला-बिसरा युद्ध' भी कहा गया था , आज दुनिया भर के सैन्य इतिहासकार इसे द्वितीय महायुद्ध के बेहतरीन सैन्य अभियानों में से एक के रूप में मानते हैं। वर्ष 1944 में, पहाड़ी की चोटी पर - जो बाद में कोहिमा की लड़ाई का पर्याय बन गयी- सैनिक इतनी नज़दीकी से लड़े कि आमने-सामने की खंदकों के बीच पड़ता टेनिस कोर्ट ही युद्ध का मैदान बन गया। वर्षों बाद वह शिलालेख न केवल प्राप्त विजय के बारे में है, बल्कि उससे कहीं अधिक गहरी चीज़ का प्रतीक बन गया : अपने

> **बिना भेदभाव, बिना संकोच, बिना किसी शर्त के राहत पहुंचाने। भारत में सेना उन चंद संस्थाओं में से है, जहां 'अनेकता में एकता ' नारा न होकर कामकाजी अनिवार्यता है। यह उपलब्धि, हमारे गणतंत्र की बड़ी संस्थागत सफलताओं में से एक है। 'जेनरेशन ज़ेड' (1997 से 2012 के बीच पैदा हुई पीढ़ी) इसे सहज बोध से जानती है। यह पीढ़ी संस्थाओं का महिमामंडन नहीं करती। अपनी एकमात्र ज़िंदगी कैसे बिताई जाए, इस बारे में सोच-समझकर भर्ती होती है।**

आप में सैन्य सेवा की प्रकृति का। इसने कुछ नया नहीं रचा। यह तो एक प्राचीन विरासत पर मुहर लगाता है- भारतीय सैनिक की सभ्यतागत विरासत पर। ऐतिहासिक रूप से, भारतीय सैनिक सदा बलिदान देने के लिए स्वेच्छा से अग्रणी रहा है। यह खासियत मायने रखती है। आज इसका महत्व पहले से कहीं अधिक है। दूसरों के उलट, सैनिक अपनी मर्ज़ी से नौकरी नहीं छोड़ सकता, न यूनियन बना सकता है, न ही तबादले के खिलाफ़ मुक़दमा कर सकता है, और न ही वह किसी ऐसे आदेश को मानने से इनकार कर सकता है जिसकी वजह से उसकी जान भी जा सकती हो। यह महज एक जीवनशैली चुनने का मामला नहीं। जो हक अन्य नागरिकों के पास होते हैं, यह उनका कानूनन समर्पण करना है। गणतंत्र का यह एकमात्र पेशा है, जहां संविधान केवल वह चीज़ नहीं जिसके तहत आप जीते हैं, बल्कि यह वह चीज़ है जिसके लिए आपको अपनी जान देने का आदेश भी दिया जा सकता है। इस शपथ को उसी ढांचे के अधीन रखना जिसमें सामान्य 'दायित्व-आधारित सेवा' परिभाषित की जाती है, न केवल प्रशासनिक लापरवाही, बल्कि एक 'श्रेणीगत त्रुटि' भी होगी। लेकिन सैनिक का दायित्व शरीर से आगे उसके 'स्व'में समा जाता है। वह उन सब चीज़ों को छोड़ देता है, जो बतौर नागरिक जीवन में उसको अलग पहचान देती हैं। मसलन, भाषा, जाति, धर्म, क्षेत्र, राजनीतिक पसंद और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं-ये सभी इंसान के तौर पर उसका हिस्सा तो बनी रहती हैं, लेकिन उस विस्तारित मानसिकता पर हावी नहीं हो पातीं, जिसमें वह स्वयं को ढाल चुका होता है। यह बदलाव क्रियान्वयन से जुड़ा है। गोलीबारी के



बीच पहचान प्रबंधन की खातिर एकजुटता खारिज नहीं हो सकती। रेजिमेंट काम कर पाती है क्योंकि वर्दी 'स्व' की जगह कुछ बड़ा स्थापित कर देती है। पहचान अहलदा रखनी पड़ती है क्योंकि ज़िंदा रहने, कमान और भरोसे के लिए यह करना जरूरी है। अंततः सैनिक हरेक नागरिक का सैनिक बन जाता है। जब वह बाढ़, आग या हिंसा-दंगे के बाद राहत पहुंचाने किसी के द्वार पहुंचता है, तो वह उससे उसकी जाति नहीं पूछता। न ही सैनिक अपनी जाति बताता है। भारतीय समाज को बांटने वाली चीज़ें उस दहलीज पर पहुंचते ही मिट जाती हैं। वह निजी पहचान रूपी टुकड़े को वहां पहुंचने से बहुत पहले तज चुका होता है। सेवा चयन बोर्ड में भर्ती के वक्त। पासिंग-आउट परेड में। पहली बार जब वह वर्दी पहनता और समझ बन जाती है कि यह उससे क्या चाहती है। नौकरी के लिए यह त्याग वक्ती नहीं। सेवा का सबसे गहरा रूप है। दरवाज़े पर पहुंचा सैनिक बतौर एक देश आया है। बिना भेदभाव, बिना संकोच, बिना किसी शर्त के राहत पहुंचाने। भारत में सेना उन चंद संस्थाओं में से है, जहां 'अनेकता में एकता ' नारा न होकर कामकाजी अनिवार्यता है। यह उपलब्धि, हमारे गणतंत्र की बड़ी संस्थागत सफलताओं में से एक है। 'जेनरेशन ज़ेड' (1997 से 2012 के बीच पैदा हुई पीढ़ी) इसे सहज बोध से जानती है। यह पीढ़ी संस्थाओं का महिमामंडन नहीं करती। अपनी एकमात्र ज़िंदगी कैसे बिताई जाए, इस बारे में सोच-समझकर भर्ती होती है। यह पीढ़ी पहचान से भरपूर ऐसी दुनिया में पली है, जिसमें प्रत्येक मंच पर उसे बढ़िया कर दिखाना, खुद को बेहतर दिखाना पड़ता है। 'स्व' अब प्रदर्शन बन गया जो

● सैन्य सेवा के लिए यह बलिदान वक्ती नहीं,इसकी संरचना का ही हिस्सा है। राष्ट्र को युद्ध में नेतृत्व करने वाले युवा चाहिये। उसे ऐसी सेना चाहिए जो दबाव में भी आगे बढ़ने, डटे रहने, सही फ़ैसले लेने में सक्षम हो। इसलिए, संकुचित सैन्य कार्यकाल कोई प्रशासनिक त्रुटि नहीं। यह इस संस्था के अपने कामकाजी तरीके का हिस्सा है। जब कोई युवा इस बात को समझ लेता है, खुली आंख से आगे बढ़ता है और उस सैनिक शपथ को लेने का मन बना लेता है, तब गणतंत्र का उस व्यक्ति के प्रति लिखित उत्तरदायित्व महज रस्मी न होकर संरचना में, नीतियों में और रूपरेखा में हो।

थकाऊ होता है। फिर उनका सामना वर्दी से होता है। वर्दी कहती है: यहां, इनमें से किसी भी चीज़ के मायने नहीं। उनमें से कई के लिए, यह कोई बलिदान न होकर एक राहत है। सेना वह प्रदान करती है जो कोई नवाचार, वेतन और इन्फ्लुएंसर अर्थव्यवस्था नहीं दे सकती: एक ऐसा उद्देश्य जो 'स्व' को अपने अंदर समाहित कर ले और उसके बदले कहीं ज़्यादा बड़ा लौटाए। नयी पीढ़ी खुद को न्योछावर करने से भाग नहीं रही। उसे तलाश है ऐसी जगह की, जहां उसका 'स्व' अंततः तिरोहित हो जाए। और वह जगह है वर्दी। आज जो युवा स्वयंसेवक आगे आता है, वह भर्ती आंकड़ों का कोई इत्तेफ़ाक नहीं, न ही किसी और युग की यादें। 'जेनरेशन ज़ेड' ने न सिर्फ अपनी रुचि से, बल्कि अपने परिवार, साथियों और आसपास के नैतिक माहौल से विरासती मूल्यों से भी आकार पाया है। इसी निरंतरता के बीच कहीं न कहीं, सैनिक बनने की विरासत आज भी इस गणतंत्र की रगों में ज़िंदा है। यही वजह कि सैनिक बनने का आकर्षण कायम है। हर पीढ़ी, अपने दबावों के बीच,अपनी भाषा में, सैनिक शपथ लेना फिर से चुनती आई है। 1948, 1971 और कारगिल से लेकर 'ऑपरेशन सिंदूर' तक-एक के बाद एक पीढ़ी ने शपथ की पुकार को बिना कोई मोल-भाव किए सुना है। पहाड़ों, रेगिस्तानों, जंगलों, उग्रवाद से लड़ाई वाले माहौल और मानवीय संकटों में, भारतीय सैनिक ने बारम्बार वह कर दिखाया है जो आधुनिक दुनिया में लुप्त हो रहा है: संवैधानिक सीमाओं के भीतर एक अनुशासित फौज। भारत की सैन्य परंपरा न केवल विजय प्राप्ति से बल्कि सदा से आक्रमण करने, नियंत्रण बनाने और फिर वापसी करने से बंधी रही है। हालांकि, शपथ का भाव दोनों ओर बरकरार रखना जरूरी है। देश अक्सर सैन्य सेवा को केवल प्रत्यक्ष बलिदान के पलों से मापता है। लेकिन इसका गहरी कीमत खामोश, धीमी और जुड़ती जाने वाली होती है। जो अधिकारी वक्त से पहले सेवामुक्ति ले लेते हैं, उन्होंने भी राष्ट्र को उतने ही दशक दिए होते हैं जिनका इस्तेमाल अन्य पेशे वाले लोग अपना कैरियर, धन-दौलत, पहचान और सुरक्षा के लिए करते हैं। फौजी केवल अपनी जान ही जोखिम में नहीं डालता, कमाई के अपने अहम दशकों को भी न्योछावर करता है।

विध्वंस से सृजन तक की यात्रा का जीवंत होना



नरेंद्र मोदी

जय सोमनाथ! वर्ष 2026 की शुरुआत में मुझे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला। यह सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले आक्रमण के एक हजार वर्ष बाद भी मंदिर के शाश्वत व अविनाशी होने का पर्व था। अब 11 मई को मुझे एक बार फिर सोमनाथ जाने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। यह यात्रा पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में है। मैं उस क्षण को फिर जीने जा रहा हूं जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद जी ने मंदिर का लोकार्पण किया था। उस दिन, सोमनाथ में विध्वंस से सृजन तक की यात्रा फिर से जीवंत होगी। छह महीनों के भीतर सोमनाथ के इतिहास से जुड़े इन दो अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ावों का साक्षी बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, हमारी सभ्यता का अटूट संकल्प है। इसके सामने लहराता विशाल समुद्र अनंत काल की अनुभूति कराता है। इसकी लहरें सिखाती हैं कि तूफान चाहे कितने भी विकराल क्यों न हों, मनुष्य का साहस-आत्मबल हर बार फिर से उठ खड़ा होने में सक्षम है। तट से टकराती लहरें सदियों से उद्घोष कर रही हैं कि मानवीय चेतना लंबे समय तक दबायी नहीं जा सकती। हमारे प्राचीन शास्त्रों में लिखा है–प्रभासं च परिक्रम्य पृथिवीक्रमसंभवम्? अर्थात दिव्य प्रभास (सोमनाथ) की परिक्रमा पूरी पृथ्वी की परिक्रमा के समान है! जब लोग यहां दर्शन-पूजन हेतु आते हैं, तब उन्हें उस सभ्यता की अद्भुत निरंतरता का भी अनुभव होता है, जिसकी ज्योति कभी बुझाई नहीं जा सकी। कई साम्राज्य आए और गए, समय बदला और इतिहास ने ढेरों उतार-चढ़ाव देखे, फिर भी सोमनाथ हमारे हृदय में हमेशा बना रहा। यह समय उन असंख्य महान विभूतियों के स्मरण का भी है, जो क्रूर आक्रांताओं के सम्मुख अडिग रहे। लकुलीश और सोम शर्मा जैसे मनीषियों ने प्रभास को शैव दर्शन का महान केंद्र बनाया। चक्रवर्ती महाराज धारसेन चतुर्थ ने सदियों पहले वहां दूसरा मंदिर बनवाया। समय की कठिन परीक्षा के बीच भीम प्रथम, जयपाल और आनंदपाल जैसे शासकों ने आक्रमणों के विरुद्ध अपनी सभ्यता को ढाल बनकर मंदिर की रक्षा की थी। मान्यता है कि महान राजा भोज ने भी इस पावन स्थल के पुनर्निर्माण में अमूल्य योगदान दिया था। कर्णदेव सोलंकी और जयसिंह सिद्धराज ने गुजरात की राजनीतिक-सांस्कृतिक शक्ति को पुनर्स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। भाव बृहस्पति, कुमारपाल सोलंकी और पाशुपताचार्यों ने इस तीर्थ को आराधना-ज्ञान के केंद्र के रूप में स्थापित करने में योगदान दिया। विशालदेव वाघेला और त्रिपुरांतक ने इसकी बौद्धिक और आध्यात्मिक परंपराओं की रक्षा की। महिपाल चूड़ासमा और राव खंगार चूड़ासमा ने विध्वंस के बाद पूजा-पाठ की परंपरा को पुनर्जीवित किया। पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होल्कर, जिनकी 300वीं जयंती मनाई जा रही है, उन्होंने सबसे चुनौतीपूर्ण समय में भी भक्ति की परंपरा को जीवंत रखा। बड़ौदा के गायकवाड़ों ने तीर्थयात्रियों के अधिकारों की रक्षा की। साथ ही हमारी यह धरती वीर हमीरजी गोहिल, वीर वेगड़ाजी भील जैसे पराक्रमियों से धन्य हुई है। उनका साहस-बलिदान स्मरणीय है। 1940 के दशक में स्वतंत्रता की भावना पूरे भारत में फैली। सरदार पटेल जैसे महान नेताओं के नेतृत्व में स्वतंत्र भारत की नींव रखी जा रही थी। एक बात जो उन्हें बहुत व्यथित करती थी, वह थी- सोमनाथ की दुर्दशा। 13 नवंबर, 1947 को,

> *सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, हमारी सभ्यता का अटूट संकल्प है। इसके सामने लहराता विशाल समुद्र अनंत काल की अनुभूति कराता है। इसकी लहरें सिखाती हैं कि तूफान चाहे कितने भी विकराल क्यों न हों, मनुष्य का साहस-आत्मबल हर बार फिर से उठ खड़ा होने में सक्षम है। तट से टकराती लहरें सदियों से उद्घोष कर रही हैं कि मानवीय चेतना लंबे समय तक दबायी नहीं जा सकती।*

दिवाली के समय, उन्होंने सोमनाथ के जर्जर अवशेषों के सामने खड़े होकर, समुद्र का जल हाथ में लेकर संकल्प लिया, 'इस (गुजराती) नववर्ष पर हमारा निश्चय है कि सोमनाथ का पुनर्निर्माण होगा। सौराष्ट्र के लोगों को हर तरह से अपना योगदान देना होगा। यह एक पावन कार्य है, जिसमें हर किसी को भागीदारी निभानी होगी।' उनके आह्वान ने सिर्फ गुजरात ही नहीं, बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष को नए उत्साह से भरा। दुर्भाग्यवश, सरदार पटेल अपने उस सपने को साकार होते नहीं देख सके, जिसके लिए उन्होंने स्वयं को समर्पित किया था। इससे पहले कि जीर्णोद्धार उपरांत सोमनाथ मंदिर भक्तों के लिए खुलता, उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इसके बावजूद, प्रभास पाटन की पावन धरती पर उनका प्रभाव निरंतर महसूस होता रहा है। उनके विजन को के.एम. मुंशी ने आगे बढ़ाया, जिन्हें नवानगर के जामसाहेब का समर्थन मिला। 1951 में मंदिर का पुनर्निर्माण पूरा होने पर राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद को उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के विरोध के बावजूद, डॉ. प्रसाद ने समारोह में हिस्सा लेकर इसे ऐतिहासिक बना दिया। मुझे अक्तूबर, 2001 का समय आज भी अच्छे से याद है, जब मैंने मुख्यमंत्री के रूप में दायित्व संभाला था। 31 अक्तूबर, 2001 को, सरदार पटेल की जयंती पर गुजरात सरकार ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 50वीं वर्षगांठ का भव्य आयोजन किया। इसी समय सरदार पटेल की 125वीं जयंती भी मनाई जा रही थी। इस कार्यक्रम में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और तत्कालीन गृहमंत्री लालकृष्ण आडवाणी जी की मौजूदगी ने इसे और भी गरिमापूर्ण बना दिया। 11 मई, 1951 को अपने भाषण में डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि सोमनाथ मंदिर दुनिया को यह संदेश देता है कि अद्वितीय श्रद्धा और विश्वास को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। उन्होंने आशा व्यक्त की, कि यह मंदिर सदैव लोगों के हृदय में बसा रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि मंदिर के पुनर्निर्माण से सरदार पटेल का सपना साकार हुआ है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि सरदार पटेल की भावनाओं के अनुरूप लोगों के जीवन में समृद्धि भी लानी होगी। इसको लेकर उनके संदेश अत्यंत प्रेरणादायी रहे हैं। पिछले एक दशक से हम इसी मार्ग पर चल रहे हैं। 'विकास भी, विरासत भी' के मंत्र से प्रेरित होकर सोमनाथ से काशी, कामाख्या से केदारनाथ, अयोध्या से उज्जैन और त्रयंबकेश्वर से श्रीशैलम तक, हमने अपने आध्यात्मिक केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया है। इसके साथ ही उनकी पारंपरिक पहचान को भी बनाए रखा है। आज बेहतर कनेक्टिविटी से ज्यादा से ज्यादा लोग यहां आ पा रहे हैं। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिल रहा है, आजीविका सुरक्षित हो रही है, साथ ही 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना और सशक्त हो रही है। सोमनाथ की रक्षा और इसके पुनर्निर्माण के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया, उनका संघर्ष हम कभी नहीं भुला सकते। भारत के विभिन्न हिस्सों से आए लोगों ने इसकी भव्यता और दिव्यता को लौटाने में अपना अद्भुत योगदान दिया। उनकी ऐसी ही आस्था पूरे भारतवर्ष को लेकर भी थी। वे एकता की ऐसी अद्भुत डोर से बंधे थे, जिसे जमीनी सीमाओं में नहीं बांटा जा सकता। आज की विभाजित दुनिया में, सोमनाथ से मिलने वाली एकता की यह सीख पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। सोमनाथ अपनी गौरवशाली परंपरा के साथ हमेशा खड़ा रहेगा, क्योंकि यह हमारी साझा सभ्यता का प्रतीक है। इसी गौरव को नमन करते हुए बलिदान देने वाले वीरों की स्मृति में और दानवीरों की उदारता को याद करते हुए अगले एक हजार दिनों तक यहां विशेष पूजा आयोजित की जाएगी। यह देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि बड़ी संख्या में लोग इस पुनीत कार्य में अपना योगदान दे रहे हैं। सोमनाथ हमें याद दिलाता है कि जब कोई समाज अपनी आस्था, अपनी संस्कृति और अपनी एकता से जुड़ा रहता है, तब उसे लंबे समय तक दबाया नहीं जा सकता। आज भी हमारी सबसे बड़ी शक्ति यही साझा चेतना है, यही एकात्म भाव है। यही भावना हमें विभाजन से ऊपर उठकर राष्ट्रहित में साथ चलने की प्रेरणा देती है।

● तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के विरोध के बावजूद, डॉ. प्रसाद ने समारोह में हिस्सा लेकर इसे ऐतिहासिक बना दिया। मुझे अक्तूबर, 2001 का समय आज भी अच्छे से याद है, जब मैंने मुख्यमंत्री के रूप में दायित्व संभाला था। 31 अक्तूबर, 2001 को, सरदार पटेल की जयंती पर गुजरात सरकार ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 50वीं वर्षगांठ का भव्य आयोजन किया। इसी समय सरदार पटेल की 125वीं जयंती भी मनाई जा रही थी।



तेजाब और पितृसत्ता के बीच संघर्ष करती स्त्री



डॉ. रितु सारस्वत

हाल ही में देश के शीर्ष न्यायालय ने 'शाहीन मलिक बनाम भारत संघ' मामले में एसिड अटैक के संबंध में मौजूदा कानूनों के तहत तेजाब हमलों से जुड़े मामलों के निस्तारण को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की। अदालत ने माना कि ऐसे अपराधों के लिए निर्धारित दंड पर्याप्त नहीं हैं तथा कई पीड़ित अब भी उचित कानूनी पहचान और सहायता से वंचित हैं। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों की भी समीक्षा की। अदालत ने पाया कि अधिनियम की वर्तमान अनुसूची में तेजाब हमले के पीड़ितों को केवल उन व्यक्तियों तक सीमित रखा गया है जो 'एसिड या इसी तरह के संहारक पदार्थ फेंकने से हुए हिंसक हमलों के कारण विकृत हो गए हैं।' न्यायालय ने केंद्र सरकार से अनुसूची में संशोधन कर ऐसे मामलों को शामिल करने पर विचार करने को कहा। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा, 'यदि इस संशोधन को अधिसूचित किया जाता है तो हम इसकी सराहना करेंगे।' यही नहीं पीठ ने तेजाब की सहज उपलब्धता और उसकी अवैध बिक्री पर भी गंभीर चिंता जताई और कहा कि अवैध रूप से तेजाब बेचने वाले विक्रेताओं को जिम्मेदारी से बचने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए तथा ऐसे मामलों में उनकी जवाबदेही भी सुनिश्चित होनी चाहिए। न्यायालय ने यह भी संकेत दिया कि दायित्व केवल हमलावर तक सीमित नहीं रहना चाहिए। सुनवाई के दौरान अपराधियों पर कठोर आर्थिक दंड लगाने और उनकी संपत्ति जब्त करने जैसे उपायों पर भी चर्चा हुई। अदालत ने टिप्पणी की, 'हमलावर की संपत्ति, जिसमें संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में उसका हिस्सा भी शामिल है, क्यों न जब्त की जाए? हम आत्मसम्मान आदि की बात करते हैं... तो आरोपी को क्यों नहीं भुगतना चाहिए?' एसिड अटैक मानवता के मुंह पर वह तमाचा है, जहां सभ्यता, संस्कृति और संवेदनाएं एक साथ दम तोड़ती दिखाई देती हैं। ऐसे अपराध केवल किसी एक व्यक्ति पर हमला नहीं होते, बल्कि वे पूरे समाज की चेतना और नैतिकता को कठघरे में खड़ा कर देते हैं। विशेष रूप से वे लोग भी प्रश्नों के घेरे में आ जाते हैं, जो इस हिंसा के विरुद्ध बोलने का साहस नहीं जुटा पाते। बिना किसी अपराध के जीवनभर असहनीय पीड़ा सहना केवल शारीरिक या मानसिक यातना भर नहीं है। यह उस धीमे ज़हर की तरह है, जिसमें पीड़िता हर दिन जीते हुए स्वयं को अपराधबोध, उपेक्षा और सामाजिक असहजता के बीच घिरा हुआ पाती है। विडंबना यह है कि तेजाब का प्रभाव केवल शरीर को नहीं जलाता, बल्कि वह व्यक्ति के आत्मविश्वास, संबंधों और जीवन के प्रति विश्वास को भी भीतर तक झुलसा देता है। यदि हम यह सोचते हैं कि ऐसी कुंठित मानसिकता केवल भारत तक सीमित है, तो यह हमारी गंभीर भूल होगी। स्त्री को अस्वीकार किए जाने, नियंत्रण खो देने या आहत अहंकार के प्रतिशोध में हिंसा का शिकार बनाना दरअसल संपूर्ण विश्व की एक सामाजिक बीमारी है। पुरुष अक्सर स्त्री की 'न' को स्वीकार नहीं कर पाता। जब उसका अहंकार घायल होता है, तब वह शक्ति, भय, हिंसा या नियंत्रण के माध्यम से स्त्री पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। और जब वह ऐसा करने में असफल होता है, तब कई बार प्रतिशोध सबसे क्रूर रूप में सामने आता है। नारीवादी चिंतक बेल हुक्स पितृसत्ता को ऐसी व्यवस्था मानती हैं, जो पुरुष को यह विश्वास दिलाती है कि प्रभुत्व उसका स्वाभाविक अधिकार है। वहीं मनोवैज्ञानिक लंडी बैनक्रॉफ्ट अपनी पुस्तक 'व्हाय डज़ ही डू दैट?' में लिखते हैं कि हिंसा केवल क्षणिक क्रोध का परिणाम नहीं होती, बल्कि उसके मूल में स्वामित्व, अधिकारबोध और नियंत्रण की मानसिकता छिपी होती है। यही कारण है कि जब कोई स्त्री अपनी स्वतंत्र इच्छा से निर्णय लेती है, असहमति जताती है या किसी संबंध को अस्वीकार करती है, तब पुरुषवादी अहंकार कई बार उसे दंडित करने पर उतारू हो जाता है। इन तमाम असहनीय यातनाओं और सामाजिक उपेक्षाओं के बीच जो बात सबसे अधिक चकित करती है, वह है एसिड अटैक सर्वाइवर्स की अदम्य जिजीविषा। उनकी जिजीविषा पितृसत्तात्मक मानसिकता को आईना दिखाती है। जिन लोगों ने उन्हें तोड़ने, डराने और जीवनभर के लिए समाप्त कर देने का प्रयास किया, वे उनके शरीर को तो घायल कर पाए, पर उनकी आत्मा, उनका साहस और जीने की इच्छा को समाप्त नहीं कर सके। शायद यही उन अपराधियों की सबसे बड़ी हार है कि जिन स्त्रियों को वे भय और पीड़ा के अंधेरे में धकेल देना चाहते थे, वही स्त्रियां आज संघर्ष, आत्मसम्मान और साहस की सबसे मजबूत आवाज बनकर खड़ी हैं। भारतीय एसिड अटैक सर्वाइवर रेशमा कुरैशी इसका एक सशक्त उदाहरण हैं। जिस लड़की के चेहरे को तेजाब से मिटा देने की कोशिश की गई थी, वही रेशमा बाद में न्यूयॉर्क फैशन वीक के रैंप तक पहुंचीं। यह केवल एक उपलब्धि नहीं थी, बल्कि उस मानसिकता के विरुद्ध एक शांत किंतु दृढ़ प्रतिरोध था, जो किसी स्त्री की पहचान को उसके चेहरे तक सीमित समझती है। कुछ ऐसी ही कहानी ब्रिटेन की केटी पाइपर की भी है। एक भयावह एसिड अटैक के बाद लंबे समय तक शारीरिक और मानसिक पीड़ा से गुजरने वाली केटी ने स्वयं को केवल एक पीड़िता के रूप में सीमित नहीं होने दिया। अनेक सर्जरी, सामाजिक भय और आत्मसंघर्ष के बाद उन्होंने अपने अनुभवों को लेखन और सामाजिक जागरूकता का माध्यम बनाया। उनकी पुस्तक 'ब्यूटीफुल' केवल एक आत्मकथा नहीं, बल्कि उस स्त्री की आंतरिक यात्रा है, जिसने अपने टूटे हुए अस्तित्व को धीरे-धीरे फिर से गढ़ा। दरअसल, रेशमा कुरैशी, लक्ष्मी अग्रवाल और केटी पाइपर जैसी महिलाएं अकेली नहीं हैं। ईरान की अमेनेह बहरामी, कोलंबिया की नतालिया पोंसे दे लियोन, पाकिस्तान की फाखरा यूनुस और बांग्लादेश की जहरा जैसी अनेक महिलाओं ने एसिड अटैक की भयावह पीड़ा झेलने के बावजूद स्वयं को चुप्पी में कैद नहीं होने दिया। इन महिलाओं ने अपने संघर्ष को निजी दुख तक सीमित रखने के बजाय उसे सामाजिक प्रतिरोध और जागरूकता की आवाज में बदल दिया। भारत में भी एसिड अटैक सर्वाइवर्स ने अपने संघर्ष को मौन पीड़ा में बदलने से इंकार किया। आगरा, लखनऊ और नोएडा में संचालित 'शीरोज़ हैंगआउट' केवल एक कैफे नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और पुनर्निर्माण का जीवित प्रतीक है। यहां काम करने वाली महिलाएं हर दिन समाज को यह संदेश देती हैं कि हिंसा किसी स्त्री के साहस को समाप्त नहीं कर सकती। जिन चेहरों को कभी समाज दया की दृष्टि से देखता था, वही चेहरे आज आत्मनिर्भरता, संघर्ष और सम्मान की नई परिभाषा लिख रहे हैं। फिर भी सबसे बड़ा प्रश्न अब भी अनुत्तरित है आखिर एसिड हमलावर भयभीत क्यों नहीं दिखाई देते? क्या वे यह बखूबी जानते हैं कि कानून के गलियारों में अब भी ऐसी सकरी गलियां मौजूद हैं, जिनसे होकर वे बच निकलेंगे? या फिर उन्हें इस बात का आश्वासन रहता है कि दोष सिद्ध हो या न हो, जब अपराध किसी स्त्री से बदला लेने के नाम पर किया गया हो, तब समाज के लिए वह उतना अस्वीकार्य नहीं रह जाता, जितना होना चाहिए। शायद यही कारण है कि किसी स्त्री का पूरा जीवन झुलसा देने से पहले उनके भीतर भय नहीं, बल्कि एक खतरनाक प्रकार का सामाजिक आश्वासन काम करता है। जब तक कानून का भय और समाज की नैतिक अस्वीकृति समान रूप से कठोर नहीं होगी, तब तक ऐसी हिंसा केवल अपराध नहीं, बल्कि पितृसत्तात्मक मानसिकता के संरक्षण में पलती हुई क्रूरता बनी रहेगी।

उच्च शिक्षा को नई दिशा देने की कोशिश



डॉ. सरोज वार्ता/ब्यूरो

भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जहां उसे न केवल अपने पारंपरिक ढांचे की सीमाओं को पार करना है, बल्कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप स्वयं को पुनर्गठित भी करना है। इसी संदर्भ में प्रस्तावित 'विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025' को एक व्यापक और दूरगामी सुधार के रूप में देखा जा सकता है। यह विधेयक मौजूदा नियामक संस्थाओं जैसे यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई को प्रतिस्थापित कर एक एकीकृत, अधिक सक्षम और पारदर्शी ढांचे की स्थापना का विचार रखता है। इसका उद्देश्य केवल प्रशासनिक पुनर्गठन नहीं है, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता, स्वायत्तता और जवाबदेही को नई दिशा देना भी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के पांच वर्ष पूर्ण होने के इस महत्वपूर्ण चरण पर इसका आगमन महज संयोग नहीं है, बल्कि इसे शिक्षा सुधारों की अगली स्वाभाविक और अनिवार्य कड़ी के रूप में भी देखा जा सकता है। तकनीकी शिक्षा, सामान्य शिक्षा और शिक्षक शिक्षा के लिए अलग-अलग संस्थाएं होने के कारण नीतिगत समन्वय में कठिनाइयां उत्पन्न होती थीं। कई बार संस्थानों को समान कार्यों के लिए विभिन्न निकायों से अनुमति लेनी पड़ती थी, जिससे न केवल समय की बर्बादी होती थी, बल्कि प्रक्रियाएं भी जटिल बन जाती थीं। इस विधेयक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है–तीन स्वतंत्र परिषदों का गठन, जो उच्च शिक्षा के अलग-अलग पहलुओं को संभालेंगी। इसके अंतर्गत पहली परिषद है 'शिक्षा विनियमन परिषद', जो संस्थानों के पंजीकरण, अनुमोदन और नियामक अनुपालन से जुड़ी होगी। दूसरी परिषद है 'शिक्षा गुणवत्ता परिषद', जो संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता का कार्य करेगी। तीसरी परिषद है 'शिक्षा मानक परिषद', जिसका कार्य पाठ्यक्रम, शिक्षण परिणाम और न्यूनतम शैक्षणिक मानकों को निर्धारित करना होगा। इसका अर्थ यह है कि 'विनियमन', 'गुणवत्ता' और 'मानक' को अलग-अलग संस्थागत ढांचों में विभाजित करके एक अधिक स्पष्ट और प्रभावी शासन प्रणाली स्थापित करने का प्रयास। विधेयक का दृष्टिकोण केवल संरचनात्मक परिवर्तन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उच्च शिक्षा की मूल भावना को भी पुनर्परिभाषित करने का प्रयास कर रहा है। इसका लक्ष्य संस्थानों को अधिक स्वायत्त बनाना, उन्हें नवाचार और अनुसंधान के लिए प्रोत्साहित करना तथा शिक्षा को परिणाम-आधारित और छात्र-केंद्रित बनाना है। इस विधेयक का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है–वित्तीय सहायता और नियमन के कार्यों का पृथक्करण। पहले यूजीसी अनुदान देने और नियमन दोनों कार्य करता था। नए ढांचे में इन दोनों कार्यों को अलग करने का प्रयास किया गया है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ने की उम्मीद है। पहले पहल यह विधेयक प्रशासनिक जटिलताओं को कम करने और निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेज करने में सहायक हो सकता है। दूसरा, स्पष्ट मानकों और सुदृढ़ प्रत्यायन प्रणाली के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार संभव है। तीसरा, यह भारतीय विश्वविद्यालयों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद कर सकता है, जिससे विदेशी छात्रों और निवेश को आकर्षित किया जा सके। लेकिन चिंताएं यह भी हैं कि इसके माध्यम से अत्यधिक केंद्रीकरण का खतरा है। एक ही संस्था में व्यापक शक्तियां केंद्रित होने से संघीय ढांचे और राज्यों की भूमिका प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा, वित्तीय प्रावधानों की अस्पष्टता भी एक गंभीर मुद्दा है, जो विशेष रूप से राज्य विश्वविद्यालयों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यदि नियामक परिषद की शक्तियां अत्यधिक बढ़ जाती हैं, तो संस्थानों की स्वायत्तता सीमित हो सकती है। विधेयक के संदर्भ में बड़ी चिंता संघीय ढांचे पर इसके संभावित प्रभाव को लेकर है। यद्यपि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत संघ-सूची की प्रविष्टि 66 में उच्चतर शिक्षा या अनुसंधान संस्थानों तथा वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थानों में समन्वय एवं मानकों के निर्धारण का प्रावधान है। निःसंदेह, इतने व्यापक बदलाव को लागू करना अपने आप में एक बड़ी परीक्षा है। संस्थागत संस्कृति, प्रशासनिक प्रक्रियाओं और मानव संसाधनों में समन्वय स्थापित करना दीर्घकालिक और जटिल प्रक्रिया होगी। यदि इसे सावधानीपूर्वक और चरणबद्ध तरीके से लागू नहीं किया गया, तो यह सुधार अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाएगा। अंततः विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 एक ऐसा प्रयास है, जो भारत की उच्च शिक्षा को नई दिशा देने की क्षमता रखता है।

लेखक पंजाब विवि. में कानून के प्राध्यापक हैं।

दुनिया में सबसे अनमोल है जीवन की शांति



सरोज वार्ता/ब्यूरो

आज दुनिया को जिस चीज की सर्वाधिक आवश्यकता है वह है जीवन की शांति। व्यक्ति के जीवन की शांति से ही, परिवार, समाज व देश में शांति संभव है। अक्सर पूछा जाता है कि शांति की परिभाषा क्या है, किसको शांति कहते हैं। किसी ने कहा, युद्ध न होना ही शांति है। लेकिन दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां युद्ध नहीं है तो क्या वहां शांति है... किसी ने कहा कि आवाज का अभाव शांति है... तो क्या आवाज नहीं होना शांति है। दरअसल, जीवन में जैसा आप सोचेंगे वैसे ही अनुभव करेंगे। वैसा ही हमारा जीवन होगा। लेकिन जो मन की शांति है, वो बाहर नहीं मिलेगी। इसीलिए कहा जाता है कि अंदर शांति है तो बाहर शांति। सही मायने में शांति मन की स्थिति है। शांति आत्मा का स्वभाव है। आत्मा का स्वधर्म शांति। जहां आत्मा अपने स्वधर्म को महसूस करती है, वहां शांति व्याप्त होती है। हर चीज का अपना स्वभाव होता है। प्रकृति का अपना स्वभाव है। जैसे हवा का स्वभाव वेग है। जल का स्वभाव शीतलता है। आत्मा का स्वभाव स्वभावतः शांति है। इसी कारण हर कोई शांति चाहता है। हम अपने कर्म और स्वभाव के अनुसार शांति की इच्छा रखते हैं, क्योंकि यह हर किसी का मूल स्वभाव है। शांति का अनुभव किया जा सकता है और इसे ध्यान के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। पहले हम अपनी आत्मा को पहचानें कि मैं कौन हूं। मैं वही हूं जिसका स्वभाव शांति है। निस्संदेह, ये संसार एक मुसाफिरखाना है। हमारे जीवन का लक्ष्य हो कि न दुख दो न दुख लो। ये आत्मा का ट्रीटमेंट है। शांति से संतुलित करुणामय समाज का निर्माण होगा। हमें नफरत की आग को बुझाना है। शांति का सपना सजाना है हमें। लेकिन आत्मा की शान है शांति की अनुभूति। आज वैश्विक आवश्यकता है शांति। युद्ध के बादल पूरी दुनिया में छाये हुए हैं। निस्संदेह, हमारे जीवन से दूसरों के जीवन में शांति आएगी। लेकिन आज हम अपने स्वधर्म को भूल गए हैं। उच्च आत्मा का स्वधर्म शांति है। जब हम स्वधर्म में स्थापित हो जाएंगे तो शांति आ जाएगी। जीवन में सुख-शांति अनुभव करेंगे। हमें अपने को शांति स्वरूप बनाना है। वर्तमान समय में दुनिया में कई जगह युद्ध चल रहे हैं। लेकिन समाज व परिवार में भी किसी प्रकार का कोई संघर्ष है वो समाप्त हो। मनुष्य के जीवन व परिवार में शांति हो। जीवन में प्रगति तभी संभव है जब वहां शांति हो। जब आपका मन शांत होता है, तो आपकी निर्णय क्षमता स्पष्ट हो जाती है। शांत मन में बुद्धि में रचनात्मकता और श्रेष्ठ संकल्प उत्पन्न होते हैं। शांत स्वभाव दूसरों पर भी प्रभाव डालता है। विश्व शांति के साथ-साथ हमारे मन में भी शांति होना आवश्यक है। हम सभी की सोच श्रेष्ठ हो। सकारात्मक सोच हो। हमारे हर कार्य में शांति का संदेश हो। ऐसा जीवन का लक्ष्य हो कि शांति व्यापक हो जाए। शांति के लिए अपने अंदर झांकिए मैं कौन हूं। मैं क्यों इस दुनिया में आया हूं। मुझे क्या करना है। मुझे कहां जाना है। आपको भीतर से जवाब मिलेगा कि मैं एक आत्मा हूं। एक सूक्ष्म ज्योति हूं। हम जीवन में जो कार्य करते हैं वो हमारा अभिनय मात्र है। यह दुनिया हमारा कर्म क्षेत्र है। हमारा निवास पांच तत्वों से निर्मित शांति का धाम है। मन और बुद्धि से हम उसी धाम में पहुंच जाएं। तब असीम शांति मिलेगी, क्योंकि हमारी आत्मा शांति स्वरूप है। संसार में हर आत्म शांति का अनुभव करें। तब यह संसार सुख शांति से संपन्न हो जाएगा। हम सबको सुख देने का प्रयास करें। कर्मक्षेत्र में सोच श्रेष्ठ है तो जीवन श्रेष्ठ होगा। जीवन में आनंद से रहें। श्रीकृष्ण की मुरली ने दुनिया में शांति का संदेश फैलाया। बंधुत्वता में शांति का संदेश निहित है। शांति वो नहीं जो शांति की स्मृति है। तूफान में भी शांति बनाये रखें। ताकि विपरीत परिस्थितियों में भी हम शांति स्थापित कर सकें। अपने जीवन में शांति को अनुभव करते हुए दूसरों को शांति दें। हम व्यक्तिगत जीवन से शुरुआत करें। स्वार्थ, क्रोध, अविश्वास आदि अशांति का कारण बनता है। साधन सुविधा जुटाकर शांति जुटाने का प्रयास निरर्थक है। जैसे धन से किताब खरीद सकते हैं ज्ञान नहीं। धन से बिस्तर मगर नींद नहीं खरीदी जा सकती है। हम साधन तो खरीद सकते हैं। शांति नहीं खरीद सकते। लेकिन आज सब कुछ तो है तो शांति नहीं है। धर्म की शरण में हम शांति के लिए जाते हैं। आज धर्म का स्वरूप कट्टरता हो गया है। हम सबके भीतर आत्मा एक है। उसका धर्म शांति है। आत्मा आनन्द स्वरूप, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप है। सभी धर्म शांति का संदेश देते हैं। वसुधैव कुटुंबकम? का संदेश दुनिया को एक सूत्र में बांधता है। अशांत दुनिया में आध्यात्मिक साधना से अनियंत्रित इच्छाएं रोकी जा सकती हैं। हम तनाव, चिंता भय से अशांत होते हैं। ज्ञान व योग से शांति मिलती है। शांत स्वरूप का अभ्यास करें। आत्मचिंतन से सकारात्मकता के विचार से हम मन को चैतन्य बनायें। जब हम मन से अशांत होते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं। हम प्रत्येक दिन परमात्मा को याद करके अपने मन को शांति की स्थिति में ला सकते हैं। विपरीत स्थिति में हम शांति का अनुभव नहीं कर पाते। हम शांत की मनस्थिति में हैं तो समाज में योगदान दे सकते हैं। हम समाज में जो दे रहे हैं, उससे हम समाज की मानसिकता में परिवर्तन ला सकते हैं।

आप सभी का धन्यवाद

सरोज वार्ता के बढ़ते कदम

सरोज के सफल 12 वर्ष का सफ़र

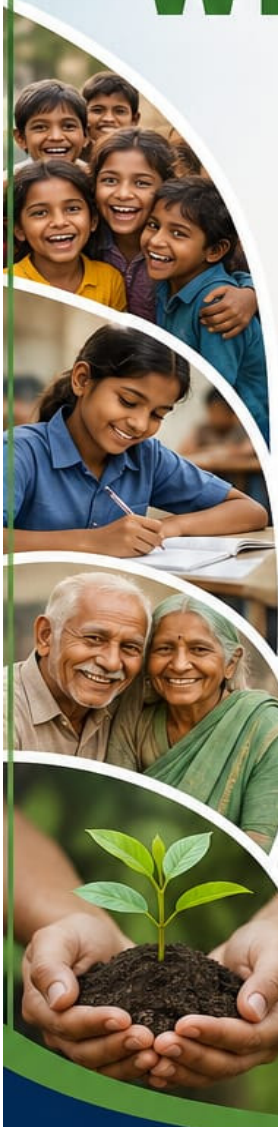


सरोज वार्ता

आप सभी सुधी पाठक, विज्ञापनदाताओं का हार्दिक आभार प्रकट करता है जिन्होने सरोज वार्ता का हर कदम पर साथ दिया

UNITED SOULS CARE WELFARE FOUNDATION

UNITED SOULS CARE WELFARE FOUNDATION



Anurag Pratap Solanki

President/Director

9555253051,9899864010

Email: unitedsoulscarewelfarefoundati@gmail.com

PAN No. AAECU0917D

Darpan ID: DL/2026/1007917

SECTION 8 Licence No.: 180721

NGO Reg No.463868



Together We Care, Together We Can

CARE | SUPPORT | EMPOWER | TRANSFORM

Building a better tomorrow by touching lives today.

यूपी का विधाता अन्नदाता



3.12 करोड़ किसानों को
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
₹99 हजार करोड़+
की राशि अंतरित

रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान
₹3.15 लाख करोड़+
गन्ना मूल्य ₹315 से बढ़ाकर
₹400 प्रति क्विंटल

बिचौलिया मुक्त बाजार
ई-मंडी में 6.42 करोड़+ पर्चियां

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
3.53 करोड़+ किसानों
को क्षतिपूर्ति

किसानों को कार्बन क्रेडिट धनराशि वितरित करने वाला
प्रथम राज्य

पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत
86 हजार+
सोलर पंपों की स्थापना

निःशुल्क बाजार भाव एवं मौसम की जानकारी हेतु
'उत्तर प्रदेश मंडी भाव'
मोबाइल ऐप

86 लाख+
लघु/सीमांत किसानों का फसल ऋण माफ



विकास की गति अपार-डबल इंजन सरकार

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

THE POWER TO GO FASTER

ENERGISING INFINITE POSSIBILITIES FOR VIKSIT BHARAT

एनटीपीसी
NTPC

For half a century, we've fueled India's race towards success. With hydro, wind, solar, hydrogen, and nuclear joining our thermal strength, we are fueling your unstoppable rise. So that a nation in speed has the power to go faster.

NTPC'S CAPACITY MIX

THERMAL | HYDRO | WIND | SOLAR | PSP | GREEN HYDROGEN | NUCLEAR



ntpc.co.in